चिंतन

सच्चाई की सुरक्षा के लिए डीपफेक पर सख्ती जरूरी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को मानव की सहायता के लिए विकसित किया गया था, ताकि कामकाज आसान हो, उत्पादकता बढ़े और जटिल समस्याओं का समाधान मिल सके। एजेंटिक एआई जैसी उभरती तकनीकें बड़े भाषा मॉडल, मशीन लर्निंग और एंटरप्राइज ऑटोमेशन को जोड़कर ऐसे स्वायत्त सिस्टम बना रही हैं, जो डेटा का विश्लेषण कर निर्णय ले सकते हैं और कम मानवीय हस्तक्षेप में कार्य कर सकते हैं। यह तकनीक उद्योगों, प्रशासन और सेवा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है, लेकिन हर तकनीक के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। एआई का दुरुपयोग आज गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। गूगल के सीईओ तक यह स्वीकार कर चुके हैं कि एआई का गलत इस्तेमाल नए खतरे पैदा कर रहा है। इन खतरों में सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण रूप है डीपफेक। डीपफेक ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की आवाज, तस्वीर या वीडियो को इस तरह बदला जा सकता है कि वह वास्तविक प्रतीत हो। इससे किसी की प्रतिष्ठा, निजता और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर आघात पहुंच सकता है। राजनीति, समाज और पारिवारिक जीवन हर क्षेत्र में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में एलन मस्क के एआई 'ग्रोक' के जरिए सोशल मीडिया पर अश्लील और भ्रामक तस्वीरों की बाढ़ इसका ताजा उदाहरण है। विवाद बढ़ने पर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और संबंधित मंचों को सामग्री हटाने के निर्देश देने पड़े। सरकार ने अब सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन कर डीपफेक और एआई-जनित बनावटी सामग्री के प्रबंधन के लिए सख्त प्रावधान लागू किए हैं। 20 फरवरी से लागू होने वाले इन नियमों के तहत एक्स, इंस्टाग्राम जैसे मंचों को सक्षम प्राधिकारी या अदालत के आदेश पर ऐसी सामग्री तीन घंटे के भीतर हटानी होगी। इसके अलावा, एआई से तैयार सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग भी जरूरी कर दी गई है, ताकि उपयोगकर्ता जान सकें कि वे जो देख रहे हैं वह वास्तविक है या कृत्रिम रूप से निर्मित। यह कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि बनावटी सामग्री को अब औपचारिक रूप से 'सूचना' की श्रेणी में रखा गया है और गैरकानूनी गतिविधियों के निर्धारण में इसे अन्य सूचनाओं के समान माना जाएगा। साथ ही, यदि किसी सामग्री पर एआई लेबल लगाया गया है तो उसे हटाने या छिपाने की अनुमति नहीं होगी। जहां संभव हो, वहां स्थायी मेटाडेटा जोड़ना भी अनिवार्य किया गया है। सबसे बड़ी चिंता बच्चों को लेकर है। बच्चों का मन कोमल और संवेदनशील होता है। डीपफेक या भ्रामक सामग्री उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और फर्जी वीडियो के माध्यम से बच्चों को निशाना बनाना एक गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। ऐसे में अभिभावकों, स्कूलों और डिजिटल मंचों को मिलकर बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। एजेंटिक एआई जहां संभावनाओं और अनुकूलनशील तकनीक के रूप में नए अवसर खोल रहा है, वहीं नियतात्मक प्रणालियां जैसे आरपीए सुरक्षित और अनुपालन आधारित संचालन के लिए अभी भी महत्वपूर्ण हैं। भविष्य का डिजिटल ढांचा इन दोनों तकनीकों के संतुलित संयोजन पर आधारित होगा, परंतु तकनीकी प्रगति का अर्थ यह नहीं कि नैतिकता और निजता को दरकिनार कर दिया जाए। आज आवश्यकता है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझें। केवल मुनाफा कमाने की दौड़ में वे समाज को जोखिम में नहीं डाल सकतीं।

दयानंद ने दिखाया था परमार्थ का रास्ता

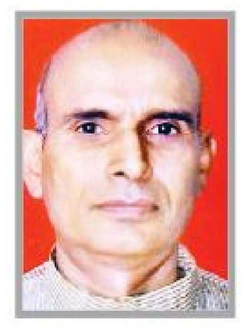

जयंती विशेष
अखिलेश आर्येन्दु

> महर्षि दयानंद ने आर्य समाज, परोपकारिणी सभा, गौकृष्यादि रक्षणी सभा और धर्म सभा की स्थापना की। वे ऐसे समाज सुधारक, वेदों के उद्धारकर्ता और धर्म के रक्षक महामान थे, जिनका मानना था कि दूसरों की उन्नति, प्रगति और विकास को ही अपनी उन्नति और विकास मानना मानव का स्वभाव होना चाहिए। इससे जहां परहित होता है, वहीं पर स्वहित भी होता जाता है। जहां भी सामाजिक कार्य हों, वहां पर अपने निहित स्वार्थ को तज सामाजिक स्वार्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए। सभी मतावलम्बियों के साथ विमर्श कर एक सर्वसम्मत सद्भाव का रास्ता पहली बार दयानंद संन्यासी ने तलाशा। यह बगैर किसी दुराग्रह, आग्रह और स्वार्थ के वशीभूत हो किया गया सर्वहितकारी राष्ट्रहितैषी कार्य था।

गुजरात के काठियावाड़ के टंकारा ग्राम में 200 वर्ष पूर्व जन्म लेने वाले आर्य समाज, परोपकारिणी सभा, गौकृष्यादि रक्षणी सभा और धर्म सभा की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद का जीवन और कार्यों को समझने के लिए किताब खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनसे प्रेरणा लेने वाले लाला लाजपत राय, सरदार भगतसिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद सरीखे अनगिनत मां भारती के वीर योद्धाओं के कार्यों से हम समझ सकते हैं। वे ऐसे समाज सुधारक, वेदों के उद्धारकर्ता और धर्म के रक्षक महामान थे, जिनका मानना था कि दूसरों की उन्नति, प्रगति और विकास को ही अपनी उन्नति और विकास मानना मानव का स्वभाव होना चाहिए। इससे जहां परहित होता है, वहीं पर स्वहित भी होता जाता है। जहां भी सामाजिक कार्य हों, वहां पर अपने निहित स्वार्थ को तज सामाजिक स्वार्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए।

महर्षि दयानंद ने ऐसे सर्वहितकारी विचार तब दिए थे जब भारतीय समाज में अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां और स्वार्थवादी प्रवृत्तियों का बोलबाला था। दयानंद ने निर्भीकता से कहा-सत्य, ज्ञान और विद्या मानव उन्नति और हित के आधार हैं। सत्य के बिना न तो ज्ञान की अहमियत है और न तो विद्या की ही। उन्होंने वेद को सत्य, ज्ञान और विद्या का आधार बताया। वह अपने उपदेशों, उद्बोधनों और प्रवचनों में वेद विद्या को प्रमुखता देते थे। उन्होंने कहा-मानव मन को चंगा करने और जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को हासिल करने के लिए वेद का रास्ता ही सबसे सहज, सरल और पवित्र है। वेद ऐसे ज्ञान, विद्या और विज्ञान के आधार स्तम्भ हैं, जहां से सभी तरह की विद्याओं और विज्ञानों का उद्गम होता है। उपनिषदों में अंधकार के पार देखने वाले और अंधकार के पार जाकर प्रकाश में विचरण करने वाले साधक को 'स्कंद' कहा गया है। जो मानव सभी तरह की बुराइयों, अंधकारों, अज्ञानता और संस्कारों से छूट जाता है, वह परम पावन ज्ञानमयी बन जाता है। दयानंद ऐसे ही परम पावन ज्ञानमयी साधक थे। उनकी साधना ऋद्धियों-सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नहीं थी बल्कि अंधकार, अविद्या, दुख, पाप, असत्य और पाखंड में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए थी। वह ऐसे युग निर्माता और समाज सुधारक थे, जिनके रगों में सर्वहित और सर्वदुख निवारण का रक्त प्रवाहित हो रहा था। महर्षि दयानंद ने कहा, वेद सभी ज्ञान-विज्ञानों और विचारों के अंतिम प्रमाण हैं। वेद ऐसे ज्ञान रश्मि के स्रोत हैं जहां मानव के आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तापों और और विषयों को कसौटी प्रदान करते हैं। महर्षि ने समाज सुधार के अनगिनत कार्य तो किए ही, आजादी के लिए अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी तैयार किए। वह सब का भला चाहते थे, भले ही उन्हें उनके लिए दुख सहने पड़ते हों। असहायों, दुखियों, रोगियों, दलितों, गरीबों और अंधकार में भटक रहे अज्ञानी लोगों के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया, जो वह कर सकते थे। सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका और वेदांजलि में महर्षि दयानंद ने मानव के जीवन के हर पक्ष को मजबूत बनाने और उन्नति करने के सभी तरह के सूत्र और विचार दिए हैं। वह मत-मतांतरों की आलोचना उनके सुधार के मद्देजनर करते हैं। वह जितना

हिंदुओं के सुधार की बात करते हैं, उनता ही मुसलमानों, ईसाइयों, बोद्धों, सिखों और जैनियों के भी। समाज, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, ज्ञान, विद्या और राजनीति सहित अनेक विषयों पर महर्षि दयानंद ने अपने विचार सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्त किए हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति जैसे सबसे विवादित विषयों को भी उन्होंने अपनी पुस्तकों में वेद और तर्क के आधार पर परिभाषित और व्याख्यायित किया है। दुनिया में सबसे अधिक विवाद और झगड़े ईश्वर, धर्म और मत-पंथ पर रहे हैं। महर्षि ने इन पर खुलकर अपने विचार सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्त किए हैं। वह कहते हैं कि पहले ईश्वर, जीव और मत-पंथों को जानों, समझों और फिर मानो। उन्होंने कबीर की तरह गुरु को खूब ठोक-बजाकर ही मानने पर जोर दिया है। इसी तरह, प्रत्येक कार्य, विचार और विषय को भी मानने के पहले उन्हें खूब समझ लेने पर जोर दिया। यूं तो ब्रह्मांड की काल गणना में दो शताब्दी बहुत लम्बा समय नहीं होता, लेकिन किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था के जन्म, कार्य, उद्देश्य और जनहित के कार्य की गणना में महत्व जरूर रखता है। वैरागी जीवन अपनाने के साथ ही, सत्य की खोज का संकल्प और संन्यास लेने के बाद समाज, संस्कृति, वैदिक धर्म, हिंदी, गुरुकुलीय शिक्षा के विकास, दलितों, पिछड़ों के साथ मजलूमों की बेहतरी के लिए समर्पित हो गया था। संन्यास लेने और गुरु विरजानंद से शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दयानंद सरस्वती के रूप में समाज में ख्याति हासिल किया, जो कई धाराओं में आगे बढ़ता हुआ रोशन होता गया। उन धाराओं में वेदों का पुर्नोदय के लिए शास्त्रार्थ व वेदों का हिंदी में भाष्य, भारतीयता को गौरव दिलवाने, समाज सुधार, गुरुकुलीय शिक्षा के उन्नयन, राष्ट्राभिमान और स्वदेशी की महत्ता से राष्ट्रनिर्माण का सूत्र देने जैसी अनेक धाराएं वे एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे।

समाज के शोषित, दलित, असहाय और अशिक्षित वर्ग की हालत विदेशी राज सत्ता की नाइंसाफी की वजह से दिनोंदिन बदतर होती जा रही थी। इसका असर भारतीय समाज के हर क्षेत्र में साफ-साफ दिखाई दे रहा था। स्वामी दयानंद ने इसे समझा और महसूस किया और यहीं से उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, राष्ट्रीय, शैक्षिक सुधार और परंपरागत विचारों में बदलाव करने की ठानी। उस बदलाव का परिणाम यह हुआ कि समाज के हर वर्ग की मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं और विचारों में खुला चिंतन और तर्कवादी विमर्श पैदा हुआ। इससे जहां देश में आजादी की हवा बहने लगी, वहीं गुलामी की जंजीरों की जकड़ धीरे-घीरे ढीली होने लगीं। आर्यसमाज की स्थापना के 150 वर्ष 2026 में पूरे होंगे। पिछले डेढ़ सौ वर्षों में स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित इस संस्था ने समाज सुधार, नव निर्माण, वेदों के प्रचार-प्रसार, समाज के शोषित, दलित, असहाय, अशिक्षित और अंधविश्वास-पाखंड में जकड़े वर्ग को जाग्रत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी दयानंद के, उद्देश्यों, कार्यों, सुधारों और निर्माण को आर्य समाज के कार्यों के साथ जोड़े बगैर उनका पूरा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वहीं पर आर्यसमाज के आंदोलन स्वरूप से गांधी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें कहना पड़ा- जहां-जहां मैं गुजरता हूं वहां आर्य समाज पहले ही गुजर चुका होता है। यह था आर्यसमाज का स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान का असर। लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ऊधम सिंह जैसे तमाम देशभक्तों की बलिदान की कहानी दयानंद और आर्यसमाज के रास्ते से गुजरती है। इसी तरह सभी मतावलम्बियों के साथ विमर्श कर एक सर्वसम्मत सद्भाव का रास्ता पहली बार दयानंद संन्यासी ने तलाशा। यह बगैर किसी दुराग्रह, आग्रह और स्वार्थ के वशीभूत हो किया गया सर्वहितकारी राष्ट्रहितैषी कार्य था।

(लेखक साहित्यकार और चिंतक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

सारा संसार

कोयम्बटूर के धार्मिक स्थलों में से एक, 11वीं शताब्दी का पेरुर पाटेश्वर निर्मित मंदिर राजा करिकाल चोल द्वारा बनाया गया था। शिव को स्वयंभू लिंगम के रूप में, पीठासीन देवता, पट्टेश्वर के रूप में पूजा जाता है। पाटेश्वर के सिर पर कामदेव गाय के पैरों के निशान मौजूद हैं।

विचार

डॉ. राजेश के पिलानिया

खुशहाल जीवन के लिए आत्मग्लानि से मुक्ति

आत्मग्लानि एक बहुत मजबूत भावना है। इसका लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आत्मग्लानि की भावना का एक सकारात्मक प्रभाव भी होता है, लेकिन इसका जीवन के कई पहलुओं पर, खासकर मानसिक स्वास्थ्य और खुशी पर, गहरा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आत्मग्लानि का सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह हमें कुछ नकारात्मक काम करने से रोकती है और हमारे जीवन में किए गए कार्यों पर सोचने में मदद करती है। आत्मग्लानि को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना और जीवन में सही रास्ते पर बने रहना उपयोगी हो सकता है। हालांकि, कई लोगों के लिए आत्मग्लानि तब नकारात्मक प्रभाव डालती है, जब इसे सही तरीके से संभाला नहीं जाता। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो आत्मग्लानि का भारी बोझ उठाए हुए हैं और एक दुखी व असंतुष्ट जीवन जी रहे हैं। उदाहरण के लिए- मैंने जो किया उसके आधार पर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं और यह बात मुझे हर समय परेशान करती रहती है; मैं अपने माता-पिता की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने के विचार से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं; अपने पिछले रिश्ते को तोड़ने की आत्मग्लानि के कारण मैं अपने वर्तमान रिश्ते की सफलता को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूं; अपने जीवन की एक गलती के कारण मुझे खुद पर शर्म महसूस होती है; या मैंने जो किया उसकी शर्म की वजह से मैं लोगों से घुल-मिल नहीं पाता और अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता हूं, और ऐसे कई अन्य उदाहरण। आत्मग्लानि शर्म, अलगाव, अकेलापन और मानसिक आघात जैसे कई हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकती है। लोग उन बातों के लिए भी आत्मग्लानि महसूस करते रहते हैं जो कई दशक पहले हुई थीं। शोध से पता चलता है कि यह लंबे समय तक बनी रहने वाली आत्मग्लानि जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है, जिनमें आत्मविश्वास, रिश्ते, काम, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, समग्र भलाई और खुशी शामिल हैं। यह आत्मग्लानि से निपटने का सही तरीका नहीं है। हमें इसे संभालने का एक बेहतर तरीका खोजने की जरूरत है। हालांकि यह कठिन है, लेकिन सही दिशा में छोटे और सरल कदम उठाकर इसे किया जा सकता है। पहला कदम है आत्मग्लानि की भावना को पहचानना और उसे स्वीकार करना। दूसरा कदम यह देखना है कि क्या यह भावना वास्तव में सही है—क्या व्यक्ति वास्तव में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार है, या वह गलत धारणाओं के आधार पर खुद को दोषी मान रहा है। तीसरा कदम है आत्मग्लानि की जड़ को पहचानना और उसे निष्पक्ष रूप से देखना। चौथा कदम है उससे सीख लेना और अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करना, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। पांचवां कदम यह है कि खुद को माफ करके, अपनी गलतियों से सीख लेकर और उन्हें दोहराने से बचने का संकल्प लेकर व्यक्ति आत्मग्लानि की भावना से बाहर आ सकता है। यदि किसी को अपने दम पर आत्मग्लानि से बाहर निकलना कठिन लगे, तो वह दूसरों से मदद ले सकता है, जिसमें पेशेवर मदद भी शामिल है। आत्मग्लानि को समझकर और उससे सीख लेकर व्यक्ति एक नई शुरुआत कर सकता है। इस नई शुरुआत के साथ वह उदासी की छाया से बाहर आ सकता है और अतीत के बोझ से मुक्त महसूस कर सकता है। इसके बाद व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में खुशी के छोटे-छोटे कदम उठाना शुरू कर सकता है, अधिक खुश रह सकता है और एक अधिक संतोषपूर्ण जीवन जी सकता है।

(लेखक एमडीआई गुरुग्राम में प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

स्वीकारोक्तिः गलतियों को खुले मन से स्वीकार करें

संकलित
दर्शन

कार्य संपन्न होने की प्रक्रिया में कदाचित त्रुटियां रह सकती हैं, भले ही कार्य निष्ठा से किया जाए। अगर कोई आपके किए-कराए में चूक निकाले, उस पर टिप्पणी करे तो नाराज होने के बजाय उसे खुलेमन से स्वीकार करें। वैसे आप गलतियां करने से तभी बच पाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे। अपने अवगुण या खोट को स्वीकार करना श्रेष्ठ मानवीय गुण है। औसत सोच का व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। अवांछनीय या अनुचित कार्य की अनदेखी का अर्थ है संशोधन के द्वार बंद कर देना। सर्वगुणसंपन्न व्यक्ति तो साक्षात देवता है। भूल-चूक की स्वीकारोक्ति प्रगति की राह में पहला चरण है। इस प्रक्रिया में आप अनेक व्यक्तियों का विश्वास जीतते हैं। जिस सत्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं, उसे बदलेंगे कैसे? जिसे अपनी अपूर्णताओं का आभास नहीं वह मूर्ख नहीं, बल्कि दयनीय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर नहीं कर सकेगा। जिस सीमा तक हम अपनी अपूर्णताओं और अवांछनीय व्यवहार के प्रति सजग रहेंगे और समाधान की ओर अग्रसर रहेंगे, उसी अनुपात में हम नैतिक रूप से समृद्ध होंगे। व्यावहारिक जीवन में संयमी, संयत व्यक्ति से भी भूल-चूक हो जाती है। उन्नत सोच का व्यक्ति अपनी भूल को तुरंत स्वीकार कर लेगा। मध्यम सोच वाले को गलती का अहसास तो होगा, वह मन में कुढ़ेगा भी, किंतु लज्जित होने की आशंका से वह गलती को खुलेआम नहीं मानेगा। अपनी छवि के प्रति अत्यंत चौकस अधिसंख्य व्यक्ति अपने गलत कार्य या कथन की वैसी संरक्षा करेंगे जैसे सद्गुण या शील दांव पर हो।

गौतम ऋषि के तप से प्रकट हुई थीं गंगा

संकलित
प्रेरणा

मान्यता है कि पुराने समय गौतम ऋषि और देवी अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। वर्तमान में ये क्षेत्र नासिक जिले में है। गौतम ऋषि तपस्वी थे, इस कारण उन्हें हर जगह मान-सम्मान मिलता था। इस बात से यहां अन्य साधु-संत गौतम ऋषि के लिए जलन की भावना रखते थे। साधु-संत गौतम ऋषि का अपमान करने का कोई न कोई बहाना खोजते रहते थे। एक दिन जलन की वजह से सभी साधु-संतों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या करने का झूठा आरोप लगा दिया। सभी साधु-संतों ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए आपको देवी गंगा को यहां बुलाना होगा। तब गौतम ऋषि ने यहां शिवलिंग स्थापित करके तपस्या करना शुरू की। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती यहां प्रकट हुए। जब शिव जी ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा तो गौतम जी से वरदान में मांगा कि देव नदी गंगा को यहां भेज दीजिए। ऐसा कहने पर शिव जी की इच्छा से देवी गंगा भी वहां प्रकट हो गईं। गंगा ने कहा कि अगर शिव जी भी यहां रहेंगे, तभी मैं भी यहां रहूंगी। गौतम ऋषि को वरदान देने और देवी गंगा की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी यहां ज्योति रूप में विराजमान हो गए। इसके बाद देव नदी गंगा भी यहां गौतमी नदी के रूप में बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदवरी भी है। इसके बाद गौतम ऋषि पर लगाया गया आरोप झूठा साबित हो गया। साधु-संतों को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। गौतम ऋषि ने सभी को क्षमा भी कर दिया।

अंतर्मन

आज की पाती

बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद हों

आज के अत्याधुनिक दौर में सोशल मीडिया का अनियंत्रित विस्तार न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर मानसिक संकट का कारण बनता जा रहा है। इस तकनीकी उछाल ने इनसान को धीरे-धीरे मानसिक रूप से निर्बल बनाया है, साथ ही वह स्वाभाविक जीवन जीने की क्षमता भी खोता जा रहा है। सोशल मीडिया का सबसे अधिक विषैला प्रभाव बच्चों की कोमल मानसिकता पर पड़ रहा है। दुनिया के कई विकसित और प्रगतिशील देश बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कड़े कानून बना चुके हैं और कठोरता से लागू भी कर रहे हैं। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। भारत में भी 16 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट तुरंत बंद होने चाहिए।

- मनोज जोशी, राजनांदगांव

करंट अफेयर

बाल देखभाल केंद्रों में तेजी से बढ़ रही गंभीर घटनाएं

ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभिक बाल शिक्षा केंद्रों तथा बाल देखभाल केंद्रों में गंभीर घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्पादकता आयोग की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में प्रति 100 सेवा केंद्रों पर ऐसी 160 गंभीर घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि यह आंकड़ा 2023-24 में 148 और 2022-23 में 139 था। गंभीर घटना से आशय ऐसी स्थिति से है जो किसी बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण को गंभीर रूप से प्रभावित करे। इसमें गंभीर चोट या बीमारी जिसके लिए चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता हो, आपात सेवाओं की मौजूदगी वाली घटनाएं, बच्चे का लापता हो जाना आदि शामिल हैं। इसके अलावा दुर्व्यवहार या बच्चे की मृत्यु भी इस श्रेणी में आती है। दिसंबर 2025 में जारी राष्ट्रीय बाल देखभाल सुरक्षा एवं गुणवत्ता एजेंसी (एसीईसीक्यूए) की रिपोर्ट के अनुसार चोट, बीमारी या आघात के मामले कुल गंभीर मामलों के 77.7 प्रतिशत थे। ये आंकड़े देशभर में प्रारंभिक बाल शिक्षा केंद्रों तथा बाल देखभाल केंद्रों की सुरक्षा को लेकर जारी चिंताओं के बीच सामने आए हैं। पिछले सप्ताह नियामकों ने सिडनी में एक पारिवारिक बाल देखभाल केंद्र को बंद किए जाने की जानकारी दी, जहां चाकू और ज़हर जिस स्थान पर रखे गए थे, बच्चे वहां तक आसानी से पहुंच सकते थे।

ऑफ बीट

क्या गर्म पानी पीने से वजन घटता व साफ होती है त्वचा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया चलन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रोजाना एक कप सादा गर्म पानी (बिना किसी मिश्रण के) पीने से वजन घटाने, त्वचा साफ होने, गले की खराश और मासिक धर्म के दर्द में राहत जैसे फायदे मिलते हैं। इसे सरल और प्राकृतिक उपाय के रूप में पेश किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार गुनगुना (उबलता नहीं) पानी पीना सामान्यतः सुरक्षित है और कई लोगों को इससे आराम महसूस होता है, लेकिन इसके विशेष स्वास्थ्य लाभों के पक्ष में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। लाभ संभवतः अधिक पानी पीने, नियमित स्वास्थ्य आदत अपनाने या गर्माहट से मिलने वाले सुकून के कारण हो सकते हैं, न कि पानी के तापमान के कारण। पानी, चाहे ठंडा हो या गर्म, शरीर के लिए आवश्यक है। पर्याप्त पानी पीना पाचन, रक्त संचार, गुर्दा क्रिया, रक्तचाप नियंत्रण और समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। 2025 के एक अध्ययन में संकेत मिला कि पर्याप्त पानी न पीने से रोजमर्रा के तनाव से निपटना कठिन हो सकता है। हालांकि अब तक ऐसा कोई मजबूत प्रमाण नहीं है कि गर्म पानी, सामान्य या ठंडे पानी की तुलना में अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ देता है।

ट्रेंड

अंत्योदय के प्रणेता

सर्वस्व समर्पण उस चेतना की अभिव्यक्ति है, जिसमें राष्ट्र और मानवता सर्वोपरि होती है। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी इसी भावना से देश के जन-जन को सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारतीय टेक्सटाइल

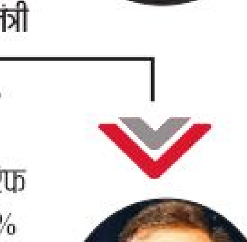

टेक्सटाइल की रेस में भारत 18% टैरिफ की बेड़ियों में दौड़ेगा और बांग्लादेश 0% टैरिफ के खुले मैदान में। पीएम का ट्रम्प की शर्तों के सामने समर्पण का ऐलान, भारतीय टेक्सटाइल के लिए मौत का फरमान है।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

सम्मानजनक स्टाइफंड

1 साल में हेल्थ सेक्टर की 27 साल पुरानी लीगेसी प्रॉब्लम्स का हमने समाधान निकालना शुरू कर दिया है। नर्सिंग इंटर्न्स, जिन्हें स्टाइफंड के नाम पर केवल 500 रुपये मिलते थे, आज उन्हें 13,000+ का सम्मानजनक स्टाइफंड मिल रहा है।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

उप्र बजट लोक लुभावना

उत्तर प्रदेश विस में पेश किया गया बजट लोक लुभावना ज्यादा तथा जनता के वास्तविक उत्थान एवं सर्वसमाज व सभी क्षेत्र के विकास का कम प्रतीत होता है। फिर भी जो घोषणायें व आश्वासन आदि जनता को देने का प्रयास किया गया है उसका सही से समयबद्ध तरीके से अमल जरूर हो।

- मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

खबर संक्षेप

टाइटन का मुनाफा 61% बढ़कर 1,684 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। आभूषण और घड़ी बनाने वाली प्रमुख कंपनी टाइटन का वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 60.84 प्रतिशत बढ़कर 1,684 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें घरेलू आभूषण व्यवसाय का योगदान रहा। कंपनी ने एक साल पहले अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में 1,047 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था।

अशोक लेलैंड का मुनाफा बढ़कर 862 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लेलैंड लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 5.19 प्रतिशत बढ़कर 862.24 करोड़ रुपये हो गया। वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी ने बुधवार को अपने तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की जानकारी दी।

टाटा ऑटोकॉम्प देशभर में नए संयंत्र करेगी स्थापित

नई दिल्ली। टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स लिमिटेड ने कहा कि वह देश भर में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस साल भारत में कई अतिरिक्त संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी, जिसने 30 जनवरी को साणंद (गुजरात) में दो नए विनिर्माण संयंत्रों का उद्घाटन किया था।

सूचीबद्धता से कंपनियों का संचालन हो सकता है बेहतर: सेबी चेयरमैन

एजेंसी ▶▶| मुंबई

- एसएमई क्षेत्र की पहुंच अभी भी सीमित बनी हुई

सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ समय में हुए विकास के बावजूद, पूंजी बाजार के नजरिये से लघु एवं मझोले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र की पहुंच अभी भी सीमित बनी हुई है।

पांडेय ने यहां इंडिया एसएमई वित्तपोषण और निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि सूचीबद्धता से ऐसी छोटी कंपनियों में संचालन व्यवस्था बेहतर हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि नियामक संस्था को अतीत में इस मोर्चे पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

वित्तपोषण और निवेश सम्मेलन में बोले पांडेय

रियायतों का दुरूपयोग हुआ

सेबी प्रमुख ने कहा, ''कुछ समय पहले, बाजार से पूंजी प्राप्त करने में एक और बाधा तब उत्पन्न हुई जब कुछ एसएमई ने एसएमई ढांचे के तहत उपलब्ध रियायतों का दुरुपयोग किया। ऐसे मामलों ने एसएमई आईपीओ में निवेशकों के भरोसे को बुरी तरह प्रभावित किया।''

कंपनियों ने 98 आईपीओ से 9800 करोड़ जुटाए

पांडेय ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में कंपनियों ने 98 आईपीओ के माध्यम से 9,800 करोड़ रुपये जुटाए। यह वित्त वर्ष 2025-26 में जनवरी तक 232 सूचीबद्धता के साथ बढ़कर 10,500 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) द्वारा शेयर बाजार के माध्यम से कर्ज जुटाने को स्वागत योग्य कदम बताया। पांडेय ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र से आईपीओ का अधिक चलन है।

1400 कंपनियां एसएमई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध

पांडेय ने कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए जहां कुछ एसएमई ने सकारात्मक माहौल बनाने और निवेशकों को अपने शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करने को अनुचित व्यापार गतिविधियों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि 1,400 कंपनियां अलग से बनाये गये एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और उनका कुल बाजार पूंजीकरण 4.1 लाख करोड़ रुपये है।

पतंजलि शहद पर किया गया शोध अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल में प्रकाशित

हरिद्वार। पतंजलि अपने प्रत्येक उत्पाद में गुणवत्ता, शुद्धता और उपभोक्ता सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस प्रतिबद्धता को एक और सशक्त वैज्ञानिक मान्यता उस समय मिली, जब पतंजलि शहद पर किया गया विस्तृत शोध विश्वप्रसिद्ध एल्सेवियर प्रकाशन के प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल अप्लाई फ़ूड रिसर्च में प्रकाशित हुआ। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि जो कहता है, वही करता है और यह एक शाश्वत सत्य है। पतंजलि का उद्देश्य है इस देश को मिलावट के जहर से बचाना और पतंजलि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदा ही समर्पित है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य उत्पादों को लेकर लंबे समय से वैश्विक मंच पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है, किंतु अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित इस शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि भारत में भी विश्वस्तरीय अनुसंधान संभव है। यह उपलब्धि न केवल पतंजलि के लिए, बल्कि समूचे भारतीय एफएमसीजी उद्योग के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने आगे बताया कि अध्ययन के दौरान यह भी प्रमाणित हुआ कि पतंजलि शहद में किसी प्रकार की बाहरी शर्करा, सिंथेटिक सिरप या अवांछित रासायनिक अवशेष नहीं पाए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पतंजलि की आपूर्ति श्रृंखला, कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर अंतिम पैकेजिंग तक, कठोर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं से गुजरती है। यह शोध इस बात का प्रमाण है कि पतंजलि शहद गुणवत्ता, शुद्धता और वैज्ञानिक प्रमाणिकता के वैश्विक मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता है। इस शोध में, पतंजलि शहद के 25 विभिन्न बैचों का उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों, एचपीएलसी एचपीएलटीसी और युएचपीएलसी के माध्यम से व्यापक परीक्षण किया गया।

मानकों के पालन के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे : इंडिगो

डीजीसीए के नए ड्यूटी नियमों के लिए पूरी तरह तैयार इंडिगो, पायलटों को बड़ी राहत

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

इंडिगो ने विमानन नियामक डीजीसीए को बताया है कि संशोधित पायलट ड्यूटी मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक परिचालन, 'रोस्टरिंग' और निगरानी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विमान कंपनी इंडिगो को दिसंबर में बड़े पैमाने पर परिचालन संबंधी व्यवधान के बाद नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।

विमानन कंपनी को नए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) मानकों पर मिली अस्थायी छूट मंगलवार को समाप्त होने के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को बयान जारी कर कंपनी की ओर से दी गई प्रगति रिपोर्ट एवं आश्वासन की जानकारी दी।

उड़ानों में 10 फीसदी की कटौती की गई थी

इंडिगो में परिचालन का अत्यधिक अनुकूलन, अपर्याप्त नियामक तैयारी, सिस्टम सॉफ्टवेयर समर्थन में कमियां एवं प्रबंधन संरचना और परिचालन नियंत्रण में खामियां उन प्रमुख कारणों में से थीं जिनके कारण व्यवधान उत्पन्न हुए, जिसके बाद डीजीसीए ने विमानन की शीतकालीन निर्धारित उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती भी की थी।

मानकों पर मिली अस्थायी छूट मंगलवार को समाप्त हो गई

- आवश्यक परिचालन और निगरानी व्यवस्थाएं की जा रही
- परिचालन व्यवधान के कारण दिसंबर में परिचालन व्यवधान आया था

घरेलू हिस्सेदारी घटकर 59.6 फीसदी

डीजीसीए ने कहा कि उड़ान संचालन को स्थिर करने के लिए दी गई दोनों छूटें निर्धारित शर्तों, प्रति घंटे उड़ान संचालन आंकड़े जमा करने तथा साप्ताहिक/पाक्षिक परिचालन प्रदर्शन रिपोर्ट सौंपने के अधीन थीं। इंडिगो की घरेलू बाजार हिस्सेदारी दिसंबर में घटकर 59.6 प्रतिशत रह गई थी, जो नवंबर में 63.6 प्रतिशत थी तब वह प्रतिदिन करीब 2,200 उड़ानों का संचालन करती थी।

नियामकीय निगरानी बनी रही

बयान में डीजीसीए ने कहा कि छूट की अवधि के दौरान इंडिगो के उड़ान संचालन की नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से करीबी निगरानी की गई तथा यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नियामक अधिकारियों को विभिन्न हवाई अड्डों पर तैनात किया गया। इंडिगो के संचालन नियंत्रण केंद्र में तैनात किया गया जिससे छूट अवधि के दौरान निरंतर नियामकीय निगरानी बनी रही।

2,507 उड़ानें रद्द की गई

इंडिगो के तीन से पांच दिसंबर के बीच 2,507 उड़ानें रद्द किए जाने की पृष्ठभूमि में, डीजीसीए ने संशोधित एफडीटीएल मानकों के क्रियान्वयन में कुछ ढील देने के लिए विमानन कंपनी के अनुरोध को 10 फरवरी तक का समय दिया था। डीजीसीए की ओर से बुधवार को जारी बयान के अनुसार, इंडिगो ने बताया है कि दिया गया समय समाप्त होने के बाद वह वैधानिक प्रावधानों के पालन और नौ अक्टूबर 2025 को स्वीकृत एफडीटीएल योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इंडिगो का परिचालन स्थिर हुआ

डीजीसीए ने 20 जनवरी को कहा था कि निरंतर नियामकीय निगरानी और सुधारात्मक कदमों से इंडिगो का परिचालन स्थिर हुआ है और अब इंडिगो के पास नए उड़ान ड्यूटी मानकों के पालन के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट उपलब्ध हैं। इंडिगो की ओर से प्रस्तुत जानकारी का हवाला देते हुए नियामक ने बताया था कि आवश्यक 2,280 की तुलना में 2,400 कमांड पायलट उपलब्ध हैं जबकि प्रथम अधिकारियों की संख्या 2,050 की जरूरत के मुकाबले 2,240 है।

जांच के बाद 22.20 करोड़ का लगा था जुर्माना

मंगलवार को इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि पहले दिए गए आश्वासन के अनुसार कंपनी के पास अपने 'नेटवर्क' में स्थिर परिचालन सुनिश्चित करने के लिए पायलट सहित पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं। डीजीसीए ने दिसंबर में हुए व्यापक व्यवधान के बाद विमानन कंपनी की शीतकालीन सेवाओं में 10 प्रतिशत कटौती की थी। जांच के बाद कुल 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

एसबीआई बाजार पूंजीकरण के मामले में चौथे स्थान पर

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) मजबूत तिमाही नतीजों के बाद आई तेजी के दम पर बुधवार को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की चौथी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद बैंक के शेयरों में तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी आने से उसने दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को पीछे छोड़ दिया। बीएसई पर एसबीआई का शेयर 3.40 प्रतिशत बढ़कर 1,183 रुपये पर बंद हुआ, जबकि एनएसई पर यह 3.23 प्रतिशत चढ़कर 1,181.10 रुपये पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान यह शेयर लगभग चार प्रतिशत चढ़कर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर बीएसई पर 1,187.70 रुपये और एनएसई पर 1,187.50 रुपये तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 10,91,982.06 करोड़ रुपये रहा, जो बीएसई पर टीसीएस के 10,52,646.38 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण से अधिक है।

बीएचईएल की बिक्री पेशकश को मिला दोगुना अभिदान

नई दिल्ली (एजेंसी)। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में सरकार की पांच प्रतिशत तक हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश (ओएफएस) को बुधवार को बोली के पहले दिन दोगुना से अधिक अभिदान मिल गया। संस्थागत निवेशकों ने 5,650 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां लगाईं। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सचिव अरुणीश चावला ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि सरकार ने बिक्री पेशकश (ओएफएस) में ग्रीन शू विकल्प का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। चावला ने कहा, /"बीएचईएल में बिक्री पेशकश को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और पहले दिन इसे 2.3 गुना से अधिक अभिदान किया गया। खुदरा निवेशकों को बृहस्पतिवार को ओएफएस में बोली लगाने का मौका मिलेगा। सरकार बीएचईएल में अपनी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 254 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर 4,422 करोड़ रुपये जुटाएगी।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्प्ले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

उतार और चढ़ाव भरे कारोबार में शेयर बाजार लगभग स्थिर बंद

मुंबई (एजेंसी)। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार बुधवार को लगभग स्थिर बंद हुए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वाहन शेयरों में हुआ फायदा आईटी शेयरों में मिले नुकसान से जाता रहा। बाजार में कारोबार सीमित दायरे में रहा। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 40.28 अंक की मामूली गिरावट के साथ 84,233.64 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 84,487.24 अंक के ऊपरी और 84,081.25 अंक के निचले स्तर तक गया। निफ्टी 18.70 अंक यानी 0.07 प्रतिशत बढ़कर 25,953.85 अंक पर बंद हुआ। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''भारत- अमेरिका व्यापार समझौते के कारण इस सप्ताह अबतक रही तेजी के बाद घरेलू शेयर बाजार में कुछ समय के लिए स्थिरता आ सकती है। बाजार का ध्यान अब तीसरी तिमाही के मिले-जुले नतीजों, आगामी मुद्रास्फीति आंकड़ों और व्यापार समझौते के विवरणों पर है। विवरण को अंतिम रूप दिए जाने की खबरें आ रही हैं।''

जेयूआईटी एसडी माइंस व फ्लोरिडा विवि के माध्यम से अपने वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को कर रहा मजबूत

नई दिल्ली। जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जेयूआईटी), वाकनाघाट, अमेरिका के साउथ डकोटा स्कूल ऑफ माइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसडी माइंस) और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से अपने वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत कर रहा है। एसडी माइंस के साथ नवगठित त्वरित मास्टर कार्यक्रम के तहत, जेयूआईटी के बी.टेक छात्रों को न केवल पहले की तरह अमेरिका में अपना आठवां सेमेस्टर पूरा करने का अवसर मिल रहा है, बल्कि वे सीधे मास्टर डिग्री में प्रवेश भी ले सकते हैं। यह कार्यक्रम चयनित और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बी.टेक के अंतिम सेमेस्टर के दौरान अपना शोध शुरू करने, उन्नत पाठ्यक्रम लेने और ट्यूशन फीस छूट के लिए पात्र होने में सक्षम बनाता है। इस पहल के तहत, जेयूआईटी के जैव प्रौद्योगिकी और जैवसूचना विज्ञान विभाग की बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी की छात्राएं प्रगति पांडे (दिल्ली) और निधि कपाटिया (अमृतसर) एसडी माइंस में विशिष्ट प्रोफेसर और निदेशक (मेसन) प्रोफेसर राजेश सानी की प्रयोगशाला में शामिल हुईं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उन्नत शैक्षणिक अनुभव और शोध-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना है।

10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद रेलवे को मिली ऐतिहासिक जीत

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे को सुप्रीम कोर्ट से एक ऐतिहासिक और निर्णायक जीत मिली है। लगभग 10 वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई में शीर्ष अदालत ने रेलवे प्रशासन के अधिकारों पर लगी न्यायिक आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह खारिज किया। भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) की वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण गौड़ द्विवेदी से जुड़े इस मामले में आया फैसला न केवल रेलवे के संस्थागत हितों की रक्षा करता है, बल्कि भविष्य में रेलवे प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए एक मजबूत कानूनी आधार भी तैयार करता है। बता दें कि मामले की शुरूआत 30 सितंबर, 2016 को हुई, जब अंबाला के तत्कालीन रेलवे मजिस्ट्रेट ने अंबाला मंडल की तत्कालीन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण गौड़ द्विवेदी को एक अनुरोध भेजा, जिसमें औचक जांच के लिए एक समर्पित टिकट चेकिंग दस्ता देने का अनुरोध किया गया था। मंडल में विशेष महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए प्रवीन गौड़ द्विवेदी ने रेलवे मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि उस विशेष समय पर स्टाफ नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने एक हलफनामे के माध्यम से यह भी प्रस्तुत किया कि "स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट दस्ते" के लिए किसी भी स्वीकृत पद के अस्तित्व में न होने के कारण अनुरोध संभव नहीं है। उन्होंने भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 का हवाला देते हुए यह भी बताया कि टिकट चेकिंग स्वाभाविक रूप से एक कार्यकारी कार्य है। जिसमें स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट (एसआरएम) चेक वाणिज्य विभाग के समन्वय से नियमानुसार नियोजित किए जाने चाहिए न कि न्यायपालिका द्वारा एकतरफा मांगे जाने चाहिए। स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट ने टिकट चेकिंग दस्ता देने से इन्कार से असंतुष्ट होकर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

PUBLIC NOTICE

District Consumer Disputes Redressal Commission, Aurangabad, Maharashtra
Telephone Number: 0240/2321202.
Email: - confo-au-mh@nic.in
Complainant: Mahesh
VERSUS
Respondent: OM-E-vehicle

Whereas the above named claimant **Mahesh Shankarpelli Filed Consumer Complaint No. cc/710/2024 before the Dist. Consumer Dispute Redressal Commission, Aurangabad. Maharashtra. Under Section 35 of Consumer Protection Act 2019** againts **Respondent no.2 Hero Electric vehicles pvt. Ltd. Through its Director, 'Sohinder singh' 50, Okhala Industrial Estate Phase II, Delhi, New Delhi India - 110 020.** That the Notices of this complaint issued to you many times and the same have not been served upon you as returned. You are hereby warned to appear before this Commission in person or through pleader. If you fail to attend The Commission on 04/3/2026 at 11.00AM the commission may in its desecration to proceed with the complaint as Ex-Party and decide it on merit.

Date of Next Hearing: -04/03/2026
Today's Date: - 04/02/2026

SEAL

Register,
District Consumer Disputes Redressal Commission Aurangabad, Maharashtra

राशिफल

मेष: किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी।

वृष: धैर्यशीलता में कमी भी हो सकती है। संयत रहें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाहन के रखरखाव एवं वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं।

मिथुन: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। कारोबार में परिवर्तन की सम्भावना बन रही है। लाभ में वृद्धि होगी।

कर्क: मन प्रसन्न तो रहेगा, परन्तु परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ चिंता परेशान भी हो सकती हैं। माता का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

सिंह: आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचें। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है।

कन्या: आशा-निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। सुस्वादु खानपान में रुचि रहेगी।

तुला: कला एवं संगीत में रुचि रहेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कारोबार में भाग-दौड़ बढ़ेगी, परन्तु स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहे।

वृश्चिक: संयत रहें। क्रोध से बचें। बातचीत में संयत रहें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है।

धनु: आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा, परन्तु मन अशान्त भी रहेगा। आत्मसंयत रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं।

मकर: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार से लाभ में वृद्धि होगी।

कुंभ: आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। फिर भी धैर्यशीलता बनाये रखने के प्रयास करें। बातचीत में सन्तुलित भी रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है।

मीन: आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परन्तु आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। पिता का साथ मिलेगा। किसी रुके धन की प्राप्ति हो सकती है।

वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर बढ़ रहा निवेशकों का भरोसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिग्गज कारोबारी कुमार मंगलम बिड़ला के वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जाने के बाद इसके शेयर सुर्खियों में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह महीनों में वोडफोन आइडिया के शेयरों में लगभग 76 प्रतिशत का उछाल आया है। इस तेजी के पीछे कई वजहें हैं जैसे कि एजीकेआर बकाए पर राहत, तीन साल के टर्नअराउंड प्लान का शुरू होना, ऑपरेटिंग लॉस कम होना और एआरपीयू में सुधार शामिल हैं। इस बीच, कंपनी में प्रमोटर कुमार मंगलम बिड़ला के बढ़ते भरोसे से निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। यह स्टॉक अभी अपने प्रमुख विंग कवरेज- 50 और 200 दिन के एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो शेयरों की कीमत में तेजी से हो रहे सुधार को दर्शाता है। बावजूद इसके, वोलैटिलिटी ज्यादा बनी हुई है, जिसका एक साल का बीटा 1.5 है। यह शेयर बाजार में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव का संकेत देता है।

दिसंबर तिमाही में कम हुआ घाटा

कारोबारी साल 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी को पिछले साल की समान तिमाही में हुए 6609 करोड़ रुपये के मुकाबले में 5286 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस दौरान ऑपरेश्नल रेवेन्यू भी पिछले साल के 11,117 करोड़ रुपये की जगह मामूली बढ़कर 11,323 करोड़ रुपये रह गया।

जनवरी में क्विक कॉमर्स क्षेत्र में भर्तियां 21 प्रतिशत बढ़ी

मुंबई (एजेंसी)। त्वरित आपूर्ति वाले ऑनलाइन खुदरा कारोबार यानी क्विक कॉमर्स क्षेत्र में जनवरी के दौरान पेशेवर एवं प्रबंधन स्तर के पदों की भर्ती में सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बुधवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। 'फाउंडइट इनसाइट्स ट्रैकर' की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, क्विक कॉमर्स क्षेत्र अब सिर्फ विस्तार पर केंद्रित रहने के बजाय लाभप्रदता, मांग के अनुमान और परिचालन दक्षता को प्राथमिकता दे रहा है। रिपोर्ट कहती है कि डेटा एनालिटिक्स, उत्पाद प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला रणनीति जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रतिभा की मांग मजबूत बनी हुई है। डिजिटल भर्ती मंच फाउंडइट की उपाध्यक्ष (विपणन) अनुपमा भीमराजका ने कहा, /"कंपनियां अब पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने, भंडार प्रबंधन को अनुकूलित करने और ग्राहक अनुभव सुदृढ़ करने पर जोर दे रही हैं।

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रु. में	बोर्ड/निगम/प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी / सम्पर्क विवरण/ ई-मेल
1	नगर पालिका बवानी खेड़ा	नगर पालिका बवानी खेड़ा हेतु एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर्स, एक ट्रॉली (जीएसटी, परिवहन, एक्सेसरीज, पंजीकरण और बीमा समेत) की आपूर्ति + 5 कार्य।	09.02.2026 16.02.2026	रु.1,39,63,699/-	https://etenders.hry.nic.in	9802401200 mcbawanikhera@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद-13/2026/40/42927/I/88/7 दि. 11.02.26

शब्द पहेली - 6136

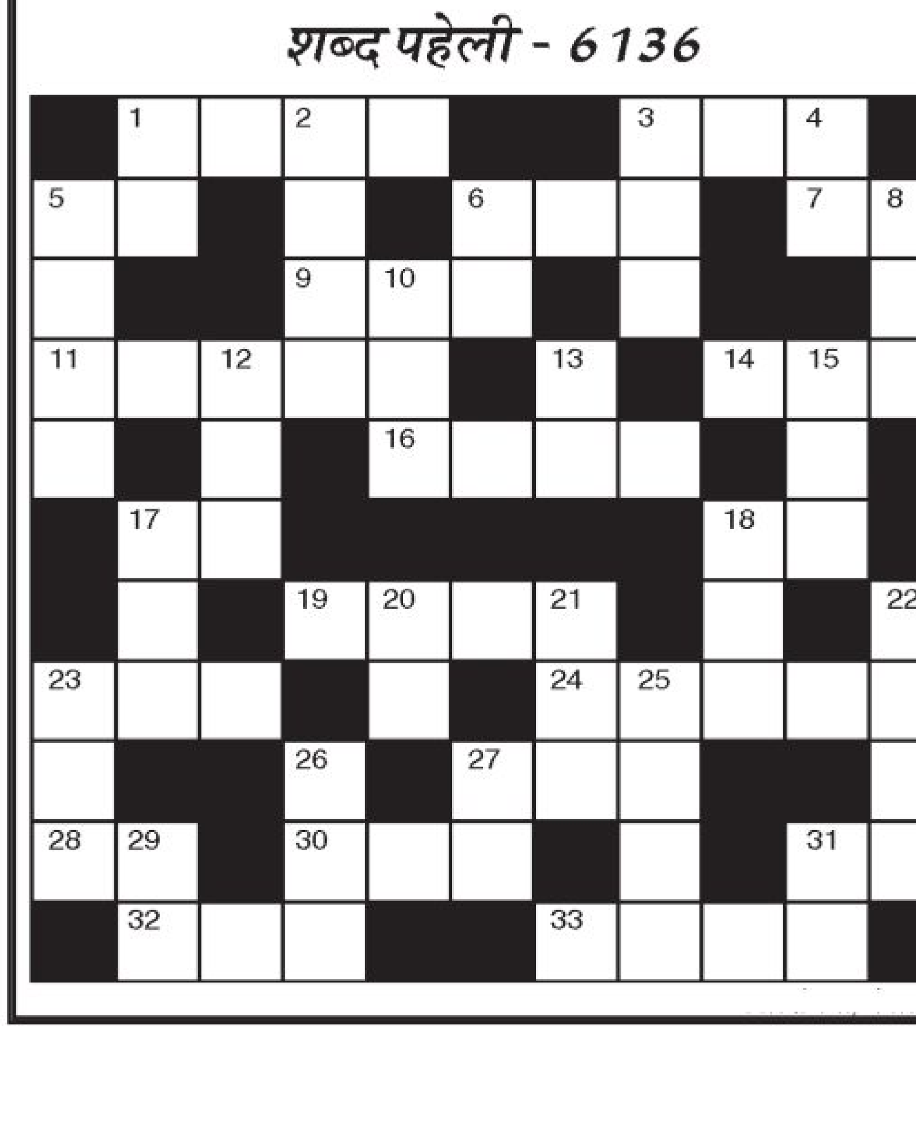

बाएँ से दाए
1. असभ्यता, मूर्खता-4
3. निर्भय, बहादुर-3
5. प्याला-2
6. सहारा, शरण-3
7. मां का भाई-2
9. साठ वर्ष की अवधि-3
11. परतंत्रता, गुलामी-5
14. दानव, दैत्य-3
16. लूटपाट-4
17. वाद्य यंत्र-2
18. परछाई, छाया-2
19. आदत, स्वभाव(उर्दू-4)
23. जंगल, वन-3
24. सेंधमार-5
27. गजल लिखने वाला-3
28. मोटा आटा, सूजी-2
30. गुलिस्तां, बाग-3
31. एक ग्रह, शनिश्चर-2
32. दबाना, कुचलना-3
33. रोब वाला, ठसके वाला-4

ऊपर से नीचे
1. मंत्रों का पाठ-2
2. उद्देश्यहीन-4
3. अनूठा, अनोखा-3
4. लक्ष्मी, कमला-2
5. खीजना, रोना-4
6. एक पौधा, अकुवा, आकड़ा-2
8. दक्ष, होशियार-3
10. जमीकंद, एक सब्जी-3
12. धैर्य, संयम-3
13. अस्थमा-2
15. एक गायिका-3
17. वर्षा ऋतु-3
18. महोदय-3
20. पैंदा, तला-2
21. पुत्र, बेटा-3
22. अवमानना-4
23. नास्तिक (उर्दू-3)
25. करामात-4
26. प्रतिज्ञा-3
27. ठाठ-बाट-2
29. अदालत में प्रस्तुत दावा-2
31. तीर, बाण-2

शब्द पहेली - 6135 का हल

■	अ	स	ह	यो	ग	■	अ	दा	ब	त
र	क्स	■	रा	■	ग	रु	ड़	■	न	र
ख	■	स	ना	त	न	■	ना	म	■	क
र	फ्ता	र	■	■	चुं	गी	■	त	म	स
खा	■	मा	■	चा	बी	■	सी	■	ही	■
ब	ल	या	का	र	■	प	रा	या	प	न
■	क	■	या	■	का	ल	■	द	■	क
द	बा	त	■	भ	ला	■	■	गा	य	ब
र	■	र	ज	■	बा	जी	ग	र	■	ज
क	र	■	ल	ह	जा	■	र्ज	■	खा	न
ना	जा	य	ज	■	र	घु	ना	य	क	■

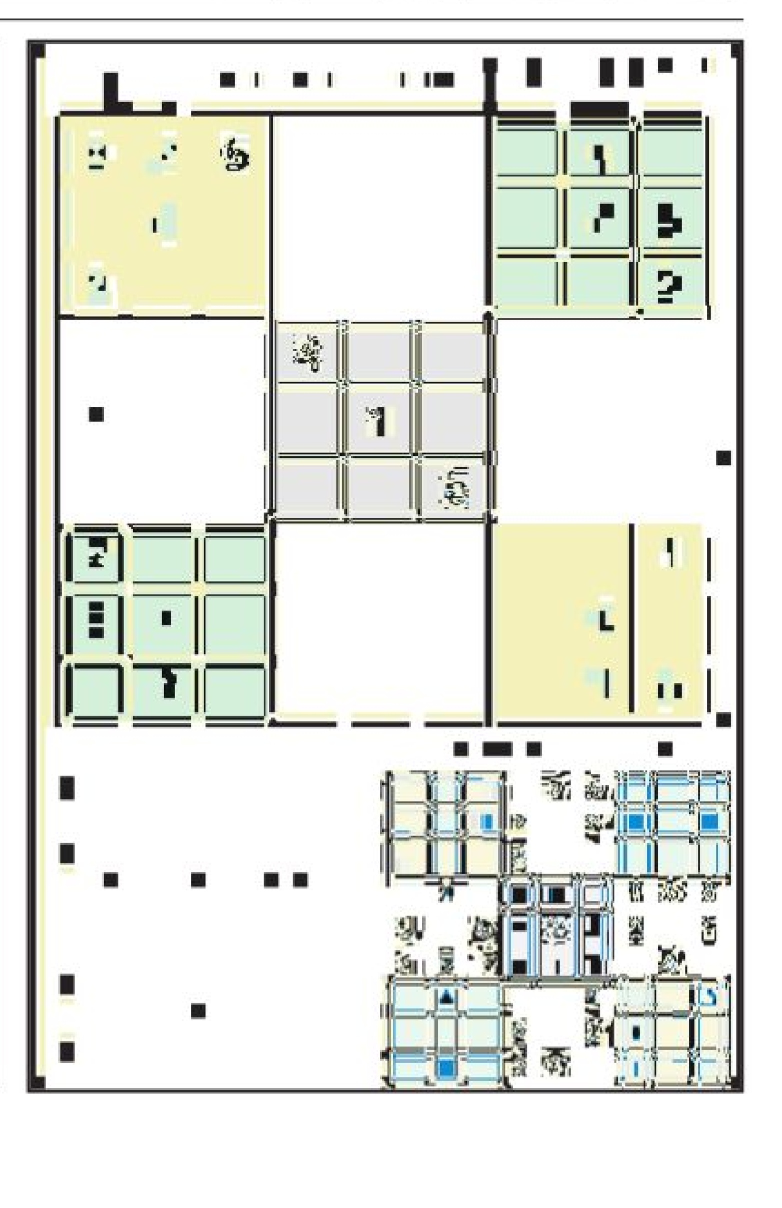

अनावश्यक आपत्ति

अमेरिका ने भारत के साथ होने वाले अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर जारी अपने दस्तावेज में जिस तरह दो बड़े बदलाव किए, उससे भारत के इस पक्ष को ही मजबूती मिली कि इस समझौते के मामले में साझा बयान की बातों को ही महत्व दिया जाए। अमेरिकी दस्तावेज में एक बदलाव यह है कि अमेरिका ने खाद्य एवं कृषि उत्पादों की सूची से दालों को हटा दिया। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका से 500 अरब डालर का सामान खरीदने का इरादा रखता है। पहले इस दस्तावेज में कहा गया था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डालर का सामान खरीदने का वादा कर रहा है। स्पष्ट है कि वादे और इरादे में अंतर होता है। इसके बाद भी इसमें संदेह है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बनी सहमति का अकारण और अतिरंजित विरोध करने वाले शांत बैठेंगे। कुछ किसान संगठन और विपक्षी राजनीतिक दलों ने विरोध का झंडा उठा भी लिया है। इसमें हमेशा की तरह कांग्रेस सबसे आगे है। गत दिवस लोकसभा में राहुल गांधी ने व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि उसने भारत माता को बेच दिया और अमेरिका के सामने पूरी तौर पर समर्पण कर दिया। उन्होंने किसान हितों से लेकर देश की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता करने के भी आरोप लगाए, जबकि किसान हित सुरक्षित हैं और अभी यह स्पष्ट नहीं कि भारत रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद करने जा रहा है।

अमेरिकी दस्तावेज में बदलाव के बाद यह और आवश्यक हो जाता है कि अगले माह यानी मार्च में होने वाले अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की प्रतीक्षा की जाए, क्योंकि उसमें ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी, लेकिन यह स्पष्ट ही है कि राहुल गांधी जैसे विरोध के लिए विरोध करने वाले नेता चैन से बैठने वाले नहीं। वे यही प्रचारित करते रहेंगे कि भारत ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए। गत दिवस उन्होंने यही किया। वे सरकार पर आरोप लगाकर सदन से चलते बने। उन्होंने अपने आरोपों के संदर्भ में सरकार का बयान सुनने की आवश्यकता नहीं समझी। इसका मतलब है कि उनका यही सोचना है कि वे किसी भी मामले में जो कुछ कहें, उसे ही अंतिम सत्य मान लिया जाए। निःसंदेह अमेरिका से होने वाले व्यापार समझौते को लेकर जारी साझा बयान के कुछ बिंदु ऐसे हैं, जिन पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है और उन पर बहस भी हो सकती है, लेकिन यदि इसी नतीजे पर पहुंच रहा हो कि किसी भी देश के साथ होने वाला व्यापार समझौता पूरी तौर पर भारत के पक्ष में झुका हो तो यह संभव नहीं। द्विपक्षीय समझौते आपसी लेन-देन पर ही आधारित होते हैं। संबंधित देशों को एक-दूसरे के हितों की चिंता करते हुए अपने हितों की रक्षा करनी होती है। भारत ने यही किया है।

सख्ती जरूरी

दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाली व्यावसायिक इकाइयों पर एमसीडी की कार्रवाई स्वागतयोग्य है। एमसीडी ने विगत दो माह में विशेष अभियान चलाकर 1280 ऐसी इकाइयों को सील किया है, जो वायु और जल प्रदूषण फैला रही थीं। पिछले साल एक दिसंबर से लेकर इस वर्ष पांच फरवरी तक चलाए गए इस विशेष अभियान में सभी 12 जोन के 242 वार्डों में कार्रवाई की गई। इनमें रेस्तरां, ढाबे, निर्माण सामग्री की दुकानें, जींस रंगाई की फैक्ट्रियां, वेल्डिंग और बेकरी की दुकानें शामिल थीं। सील की गई इकाइयों में से 242 पर जल प्रदूषण फैलाने के लिए कार्रवाई की गई, जबकि 1038 इकाइयां वायु प्रदूषण फैला रही थीं। दिल्ली में वायु व जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो व्यावसायिक इकाइयां प्रदूषण फैला रही हैं, उनपर सख्ती से कार्रवाई किया जाना सर्वथा उचित है।

राजधानी में वायु प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर भी एमसीडी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए

दिल्ली सरकार के निर्देश पर एमसीडी द्वारा ये कार्रवाई की गई, जो दर्शाता है कि सरकार और एमसीडी बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं। हालांकि, इस तरह की कार्रवाई का लाभ तभी है, जब ये एक बार की कार्रवाई तक सीमित न रह जाए। साथ ही एमसीडी को ऐसी कार्रवाई अवैध रूप से चल रही औद्योगिक इकाइयों पर भी करनी चाहिए।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या अपनी अप्रकाशित पुस्तक पर जनरल नरवणे की सफाई के बाद इस प्रकरण पर विवाद समाप्त हो जाना चाहिए?

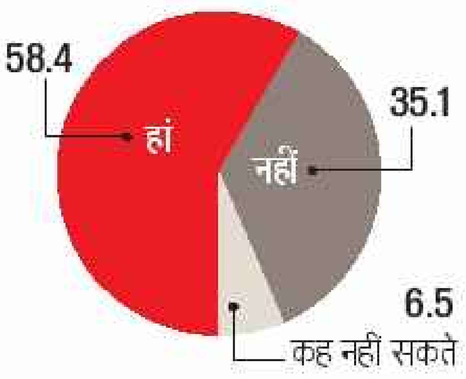

आज का सवाल

क्या मतदाताओं को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विभाजनकारी एजेंडे से बचाए जाएं विश्वविद्यालय

विकास सारस्वत

शिक्षण संस्थानों में विभाजनकारी एजेंडा न केवल विभिन्न वर्गों में अविश्वास की खाई बढ़ाएगा, बल्कि विकसित भारत की लक्ष्यपूर्ति में भी बाधा बनेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में उच्च शिक्षा आवंटन को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 55,727 करोड़ कर दिया है। इसके साथ ही प्रमुख औद्योगिक गलियारों में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित कर शैक्षणिक क्षेत्रों को अनुसंधान और उद्योग के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है। जहां चीन जैसे देश का उच्च शिक्षा बजट भारत से छह गुना अधिक है, वहां यह उतना पर्याप्त तो प्रतीत नहीं होता, किंतु यह सराहनीय है कि इस मोर्चे पर एक पहल तो हुई है। हालांकि आवंटन से परे चिंता की बात यह है कि सरकार विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक परिवेश को लेकर कितनी गंभीर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के कुछ नियमों ने बीते दिनों समाज के कुछ वर्गों में असंतोष बढ़ाने का काम किया। घोषित रूप से ये नियम शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए थे, परंतु सामान्य वर्ग को इन नियमों के दुरुपयोग का भय था, क्योंकि निगरानी टीमों में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की स्पष्ट बात नहीं थी और झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रविधान भी नहीं था। इनके दुरुपयोग की आशंका अकारण नहीं थी। एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग के कई मामले सामने आते रहे हैं।

जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न भारतीय समाज का दुखद पहलू रहा है और आज भी कई क्षेत्रों में इससे मुक्ति नहीं मिली है, परंतु शैक्षणिक संस्थानों में शायद यह समस्या उतनी बड़ी नहीं है। वहां तो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए युवाओं के बीच आजीवन चलने वाली मित्रता बनती हैं। आंकड़े देखे जाएं तो 2023-24 में 3,000 शिक्षा संस्थानों से 378 ऐसी शिकायत मिली थीं। ऐसे में गंभीर मामलों में पहले से मौजूद कानूनी प्रविधानों के तहत कार्रवाई हो सकती थी और नए विद्यार्थियों को ओरिएंटेशन आदि से संवेदनशील बनाया जा सकता है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों को स्थगित कर दिया है, परंतु सवाल सरकार की बुद्धिमत्ता पर उठता है, जो उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के बजाय विश्वविद्यालयों को सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष का मैदान बनाए दे रही है।

पश्चिम में यूनिवर्सिटी कैंपसों को संघर्ष एवं क्रांति का मैदान बनाने की कवायद तब से जारी है, जब से मार्क्सवादियों का विश्वास उस सर्वहारा क्रांति से उठा, जिसमें मजदूर वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ सत्ता पर नियंत्रण करता। इसके बाद सांस्कृतिक मार्क्सवाद की परिवर्तित अवधारणा ने क्रांति की उम्मीद जातीय, नस्लीय, मजहबी एवं लैंगिक अल्पसंख्यकों की गोलबंदी और उग्र फेमिनिज्म एवं पर्यावरण आदि आंदोलनों को जोड़कर बनाई। फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फार सोशल रिसर्च नामक संस्थान में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन नव-मार्क्सवादी विचारों का जन्म हुआ, लेकिन नाजी शासन में यह संस्थान अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गया। अमेरिका के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में पैर जमा चुके नव-वामपंथियों ने विश्वविद्यालयों को जब अपना युद्धक्षेत्र बनाया, तब इसमें कुछ भी दबी-छिपी बात नहीं थी। फ्रैंकफर्ट स्कूल के अतिवादी विचारक हर्बर्ट मारक्यूज ने उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से क्रांतिकारी चेतना के प्रसार की वकालत की। इसी विचार के हिमायती रूडी डुट्सके ने ''लांग मार्च थ्रू द इंस्टीट्यूशंस'' नामक प्रस्ताव रखा। इन अतिवादी विचारों ने अमेरिकी अकादमिक परिदृश्य को इस कदर बदला कि विश्वविद्यालयों में पारंपरिक सिद्धांतों के पठन-पाठन के लिए कोई जगह नहीं है। उनमें वामपंथी विचारों को ही परोसा जा रहा है। समाज का विश्लेषण नस्लीय सामूहिक पहचानों के माध्यम से करने वाली क्रिटिकल रेस थ्योरी हर पहलू को उत्पीड़क और पीड़ित वर्गों में बांट कर करती है।

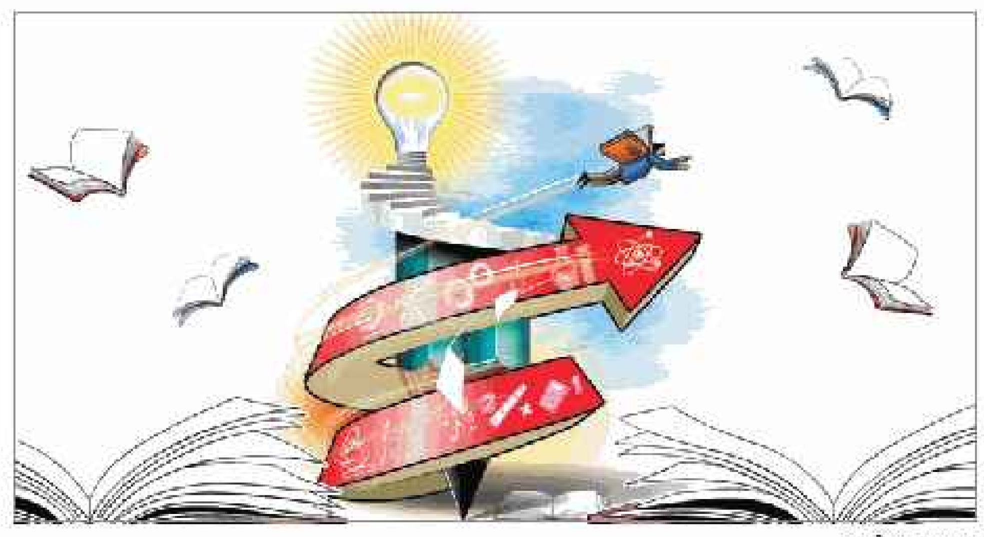

अवधेश राजपूत

अमेरिका के सबसे बड़े शिक्षक संघ नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने दावा किया था कि अमेरिका में होने वाली सैट परीक्षा में अश्वेतों के उत्तीर्ण होने की दर इसलिए खराब है, क्योंकि प्रश्नपत्र श्वेत प्राध्यापक तय करते हैं। राहुल गांधी ने इसी बेतुकी बात को आधार बनाकर कहा कि जेईई परीक्षा में दलित परीक्षार्थियों के कम अंक आने का कारण ''उच्च जाति'' के प्राध्यापकों द्वारा प्रश्न पत्र तय करना है। इसी तरह अमेरिकी संस्था ''द सेंटेंसिंग प्रोजेक्ट'' समेत अन्य बुद्धिजीवियों ने जेलों में अश्वेत कैदियों की बड़ी संख्या का दोषी श्वेत लोगों द्वारा बनाए गए कानून और न्याय व्यवस्था को बताया। भारत में इसी प्रतिरूप को परिवर्तित कर मुस्लिमों के बड़ी संख्या में जेलों में होने के लिए बहुसंख्यक राजनीति को जिम्मेदार ठहराया जाता है और इस बाबत कई विपक्षी सांसदों ने लगातार प्रश्न उठाए हैं। कई मुस्लिमों ने इन आंकड़ों को मुसलमानों के उत्पीड़न के प्रमाण के रूप में पेश किया है। ऐसा ही आरोप दिल्ली दंगों के आरोपित शरजील इमाम ने भी लगाया था।

आज उच्च शिक्षा के भारतीय संस्थानों की रैंकिंग भी निरंतर गिरती जा रही है। नवीनतम क्यूएस रैंकिंग में मलेशिया का प्रदर्शन भी भारत से बेहतर है। जेएनयू में ब्राह्मणों के प्रति हिंसात्मक नारे लग रहे हैं। आइआइटी दिल्ली जैसे संस्थानों में 'हिंदू विहीन भारत की कल्पना'' जैसे विषयों पर गोष्ठी आयोजित हो रही हैं। दिल्ली दंगों में जेएनयू और जामिया के कई छात्र आरोपित बनाए गए थे। दो माह पहले जिस विश्वविद्यालय के डाक्टरों ने लाल किले पर बम ब्लास्ट किया था, उस अल फलाह की 2018 से मान्यता समाप्त थी और कोई देखने वाला नहीं था। दूसरी तरफ गिरते शैक्षणिक स्तर और कैंपसों में व्याप्त अराजकता से बेपरवाह यूजीसी जाति-जाति खेलने में लग गई। दुख की बात यह है कि एक राष्ट्रवादी सरकार ने नव-मार्क्सवादी एजेंडे के सामने उस समय घुटने टेके, जब दुनिया प्रौद्योगिकी, विशेषकर एआइ की उत्तरोत्तर होती प्रगति के कारण युग परिवर्तन के पड़ाव पर खड़ी है। ऐसा एजेंडा न केवल समाज के विभिन्न वर्गों में अविश्वास की खाई बढ़ाएगा, बल्कि विकसित भारत की लक्ष्यपूर्ति में भी बाधा बनेगा।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

मनमानी रोकने वाले नए नियम

एस. कृष्णन

अब यदि कोई प्लेटफार्म नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे चूक माना जाएगा और उस पर कार्रवाई हो सकती है

भारत का डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मशीनी कौशल (एआइ) में हुई प्रगति, खासकर आडियो, वीडियो और आडियो-वीडियो कंटेंट को बनाने और बदलने की तकनीक ने सूचना के सृजन, उपभोग और विश्वास के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। जहां ये तकनीक अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और लोगों तक पहुंच को बढ़ाती हैं, वहीं ये ऐसे नए खतरे भी पैदा करती हैं जो सीधे तौर पर व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी से पैदा होने वाली खास चुनौतियों को समझते हुए भारत सरकार ने डिजिटल मध्यस्थों (डिजिटल इंटरमीडियरी) से जुड़े कानून और नीतिगत ढांचे को और मजबूत किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में किए गए हालिया संशोधन और नवंबर 2025 में इंडिया एआइ मिशन के तहत जारी भारत की एआइ गवर्नेंस गाइडलाइंस, 2025- दोनों को साथ पढ़ने पर सरकार का एक संतुलित और स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आता है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक नुकसान से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी जिम्मेदारियां तय की गई हैं और साथ ही जिम्मेदार तरीके से एआइ को अपनाने के लिए नीतिगत सिद्धांत भी तय किए गए हैं। हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए ये सभी नियम और दिशानिर्देश मिलकर सरकार की एक साफ मंशा दिखाते हैं-तकनीक का विकास ऐसा हो, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक की गरिमा को बनाए रखने वाले ढांचे के भीतर ही आगे बढ़े। संशोधित इंटरमीडियरी नियमों में पहली बार कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी की एक साफ और व्यावहारिक परिभाषा दी गई है। इसमें वह कंटेंट शामिल है जो इस तरह बनाया या बदला गया हो कि वह असली जैसा लगे या हकीकत से अलग पहचान में न आए, लेकिन इसमें सामान्य और ईमानदार कामों को साफ तौर पर बाहर रखा गया है-जैसे तकनीकी एडिटिंग, दिव्यांगों की सुविधा के लिए किए गए बदलाव, पढ़ाई या शोध से जुड़ी सामग्री और वैध रचनात्मक उपयोग। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डिजिटल नुकसान के नए तरीकों से मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर ही निपटा जाए, न कि उसे अनौपचारिक या प्लेटफार्म की अपनी माडरेशन व्यवस्था पर छोड़ दिया जाए। इतना ही महत्वपूर्ण यह स्पष्टीकरण है कि मध्यस्थों द्वारा स्वचालित उपकरणों या अन्य उचित तकनीकी उपायों के माध्यम से सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाइयां वैधानिक सुरक्षा को कमजोर नहीं करती हैं। इससे जवाबदेही बनाए रखते हुए अनुपालन को बढ़ावा देने वाला परिवेश मजबूत होता है।

आवश्यक है नए माध्यमों की जवाबदेही • प्रतीकात्मक

संशोधित ढांचे में सबसे बड़ा और अहम बदलाव यह है कि अब सिर्फ नुकसान होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, पहले से ही रोकथाम पर जोर दिया गया है। जो डिजिटल प्लेटफार्म कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को बनाने या फैलाने में मदद करते हैं, उन्हें ऐसे तकनीकी उपाय अपनाने होंगे, ताकि गैर-कानूनी कंटेंट के बनते समय या फैलते समय ही रोका जा सके। अगर कृत्रिम रूप से बनाया गया कंटेंट कानूनी है तो उस पर साफ और स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, तकनीकी रूप से संभव होने पर उसके साथ स्थायी मेटाडाटा या स्रोत पहचान से जुड़ी व्यवस्था भी करनी होगी, ताकि यह पता चल सके कि वह कंटेंट कहां से आया है। इन लेबल या पहचान से जुड़े चिह्नों को हटाना, बदलना या छिपाना साफ तौर पर प्रतिबंधित होगा। इसमें केवल नुकसान हो जाने के बाद कंटेंट हटाने पर भरोसा नहीं किया गया है, बल्कि पारदर्शिता को नागरिक की गरिमा और भरोसे की सुरक्षा के रूप में देखा गया है। अब नागरिकों को सिर्फ शिकायत करने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, बल्कि वे उसी समय यह पहचान भी कर सकेंगे कि कोई कंटेंट असली है या नहीं। यह नागरिकों के 'जानने के अधिकार' को मान्यता देने जैसा है। अब डिजिटल प्लेटफार्म को समय-समय पर और साफ भाषा में यूजर्स को उनके अधिकार, जिम्मेदारियां और नियम न मानने पर होने वाले परिणामों के बारे में बताते रहना होगा।

बड़े और प्रभावशाली इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के लिए नियमों में अतिरिक्त जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जो उनके आकार और प्रभाव के हिसाब से हैं। अगर कोई प्लेटफार्म नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे चूक माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिन प्लेटफार्म का समाज पर ज्यादा और व्यापक असर है, उन पर शासन और निगरानी की जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले इन नियमों के साथ-साथ, इंडिया एआइ गवर्नेंस गाइडलाइंस, 2025 एआइ को जिम्मेदार, सुरक्षित और सभी को साथ लेकर अपनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा बताती हैं। ये गाइडलाइंस आइटी एक्ट या इंटरमीडियरी नियमों की कानूनी जिम्मेदारियों को खत्म नहीं करतीं, बल्कि ये डेवलपर्स, एआइ सिस्टम लागू करने वालों और संस्थानों को दिशा देने का काम करती हैं।

फिलहाल जो ढांचा बनाया गया है, वह संतुलित नियमों और नीतिगत दिशानिर्देशों पर टिका है, पर यदि जनहित में जरूरत पड़ी, तो संसद के पास बदलती तकनीकी परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाने का पूरा अधिकार बना हुआ है।

(लेखक भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

चुनौतियां

जीवन चुनौतियों से भरी एक यात्रा है। लक्ष्य प्राप्ति और विकास के लिए चुनौतियां और कठिनाइयां महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होती हैं। ये हमें हमारे आराम के दायरे से बाहर धकेलती हैं और क्रियाशील बने रहने के लिए अमूल्य सबक सिखाती हैं। चुनौतियों का सामना करने की क्षमता ही सफलता की बुनियाद है। समय हमारे समक्ष चुनौतियां इसलिए प्रस्तुत करता है ताकि हमें यह अनुभूति हो सके कि हम अपने सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। चुनौती हमारी सहनशक्ति इच्छाशक्ति और लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने की हमारी क्षमताओं की परीक्षा लेती हैं।

सहजता के साथ चुनौतियों का सामना करना उनके विरुद्ध सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। इस क्रम में आप जिन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, उनसे निपटने के लिए अपनी क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें। संभव है कि नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों से घबराकर हमारा मन हार मान सकता है, लेकिन महर्षि व्यास जी ने यथार्थ ही कहा है 'क्षुद्रमना लोग ही दुख के वशीभूत होकर अपना तप, तेज, शक्ति को नष्ट कर लेते हैं। पुरुषार्थी लोग कष्टों को भी अपनी सफलता और विकास का आधार बना लेते हैं।'

हम देखते हैं कि कुछ लोग सदैव एक मुस्कान लिए सबसे मिलते-जुलते हैं। सभी सामाजिक शिष्टाचार और दायित्व निभाते हैं। अपने सब कर्तव्य पूरे करते हुए दूसरों की मदद भी करते हैं। दूसरों से मदद लेते भी हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उनके पास अतिरिक्त समय है या कठिनाइयां-चुनौतियां नहीं हैं। वास्तविकता यही है कि वे ऐसी चुनौतियों से पार पाना अच्छी तरह जानते हैं और व्यस्त होते हुए भी इन सबके लिए समय प्रबंधन का मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। वे जान गए हैं कि कठिनाइयां और परेशानियां जीवन के हर पड़ाव पर मिलेंगी। उनसे घबराकर बैठ नहीं सकते। उन सभी को झेल कर ही जीवन को आगे बढ़ाना है।

डा. निर्मल जैन

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

तकनीकी खतरों से निपटना आवश्यक

'एआइ के खतरों से सावधान रहें' शीर्षक से प्रकाशित अजय कुमार के आलेख के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन स्मरण हो आया कि 'नई तकनीक से डरना नहीं चाहिए।' हालांकि एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन तकनीकों का उपयोग करते समय पूरी सावधानी और समझदारी बरतना भी उतना ही आवश्यक है। आज इंटरनेट मीडिया पर स्क्राल करते-करते यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि जो चेहरा या आवाज हम देख-सुन रहे हैं, वह असली है या एआइ द्वारा बनाई गई। एआइ टूल्स अब किसी व्यक्ति की आवाज, शक्ल और अपीयरेंस का इस्तेमाल कर बिल्कुल उसी के जैसे नकली वीडियो और आडियो तैयार कर सकते हैं, जिनका दुरुपयोग किया जाना बेहद आसान हो गया है। भले ही एआइ में भावनाएं विकसित नहीं हो सकतीं, लेकिन इसके जरिये किसी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से गहरी क्षति पहुंचाई जा सकती है। यह न सिर्फ निजी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। आज जहां चुनावों से लेकर बच्चों के होमवर्क तक में एआइ का उपयोग हो रहा है, वहां इसका संतुलित और जिम्मेदार इस्तेमाल अत्यंत आवश्यक हो गया है। जेडस्केलर थ्रेटलैब्स 2026 एआइ सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के बाद भारत दुनिया भर में एआइ को अपनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ और बदलती परिस्थितियों में सरकार द्वारा आइटी अधिनियम 2021 में संशोधन और एआइ के इस्तेमाल पर कठोर नियम समय की मांग थे। ये कदम 51 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले देश भारत के लिए एक सराहनीय पहल हैं। इनमें मुख्य रूप से एआइ जेनरेटेड कंटेंट पर लेबल लगाना, अवैध या आपत्तिजनक कंटेंट बनाने पर प्रतिबंध तथा ऐसे कंटेंट को तीन घंटे के भीतर हटाने का प्रविधान अत्यंत आवश्यक था। इससे डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों से निपटने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

खुशी जायसवाल, जम्मू

राहुल गांधी के फुस्स बम

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी येन-केन-प्राकरेण हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। राहुल गांधी के 'एटम बम' वाले बयानों का हश्र पिछले कई वर्षों से फुस्स होता रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक पर बवाल मचाए राहुल गांधी को समझना चाहिए कि जब प्रकाशक और लेखक ने सार्वजनिक तौर पर बयान दे दिया है कि वह पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं की गई है, तो राहुल को मामला शांत कर संसद को चलने देना चाहिए। सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन न करना विवाद को बढ़ाता है, जो कानूनविदों के नजरिए से भी गलत है। नियमों के अनुसार, किसी भी अप्रकाशित सामग्री को सदन में कोट नहीं किया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ''असत्य'' को छिपाने के लिए किताब को अप्रकाशित रख रही है। अच्छा है कि लोकसभा स्पीकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों की पुष्टि तक आसन ग्रहण न करने का निर्णय लिया है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

लोकतंत्र का मंदिर या अखाड़ा

बिहार विधान परिषद में हालिया हंगामे ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की गरिमा को समझ रहे हैं या नहीं। मंत्री अशोक चौधरी और राजद के सुनील कुमार सिंह के बीच जिस तरह की तीखी नोकझोंक हुई, वह केवल राजनीतिक मतभेद नहीं था, बल्कि भाषा और आचरण की सीमाओं का खुला उल्लंघन था। आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और मार्शलों को बीच-बचाव करना पड़ा। सदन की कार्यवाही बाधित हुई, सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा और विपक्षी सदस्यों को दिनभर के लिए बाहर करना पड़ा। यह दृश्य केवल एक दिन की अव्यवस्था नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्तर में गिरावट का संकेत था। सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जो राज्य की नीतियां तय करते हैं, कानून बनाते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं। लेकिन जब इसी सदन में 'चोट्टा', 'चोर' और 'घोटालेबाज' जैसे शब्द गूंजते हैं, जब 'औकात' जैसी भाषा का इस्तेमाल होता है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम अपने लोकतंत्र को सही दिशा में ले जा रहे हैं। बहस और विरोध लोकतंत्र की आत्मा हैं, लेकिन गाली-गलौज और व्यक्तिगत हमले उसकी आत्मा को आहत करते हैं। सदन के भीतर की यह स्थिति आम नागरिकों के लिए निराशाजनक है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

पोस्ट

किसी और खेल में ऐसे उतार-चढ़ाव नहीं दिखेंगे, जैसा थ्रिलर क्रिकेट मैच दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान का हुआ। यह क्रिकेट के सर्वकालिक रोमांचक मैचों में गिना जाएगा। — विक्रम चंद्रा@vikramchandra

राहुल गांधी का व्यवहार सदैव सनसनी की खोज में बेचैन किसी इन्फ्लुएंसर की तरह होता जा रहा है, जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए रोजाना नए-नए शिगूफे छेड़ने की फिराक में रहता है। इसीलिए कोई हैरानी नहीं कि डिजिटल मीडिया पर तो कांग्रेस को समर्थन मिलता है, लेकिन वोटों से उसकी झोली नहीं भर पाती। — राहुल रौशन@rahulroushan

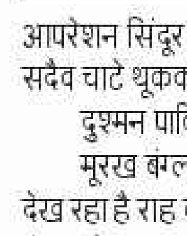

जनरल नरवणे की पुस्तक का भविष्य अधर में दिखता है, पर यदि यह छप भी गई होती तो बस ड्राइंग रूम्स की शोभा ही बढ़ा रही होती। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि सरकार इसे लेकर इतनी बेचैनी दिखाती। उसके रवैये से किताब को चर्चा मिल गई। हालांकि इससे न तो लेखक का भला होगा और न प्रकाशक का। इसके लाभार्थी तो राहुल गांधी बन गए हैं, जिनके समर्थक इसे उनकी जीत की तरह पेश कर रहे हैं। — कमलेश सिंह@kamleshksingh

जनपथ

आपरेशन सिंदूर हो चहे क्रिकेट मैदान,
सदैव चाटे थूककर दुश्मन पाकिस्तान।
दुश्मन पाकिस्तान न इसमें तनिक अजूबा,
मूरख बंगलादेश बुरी संगत में डूबा !
देख रहा है राह बड़ी शिद्दत से नेशन,
पंद्रह को इस बार करो फिर से आपरेशन !!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 209

अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की त्रुटियों को ठीक कराने खुद आगे आए ओम बिरला

नई दिल्ली, प्रेट्र: लोकसभा में विपक्ष द्वारा अपने खिलाफ मोर्चा खोले जाने के बाद भी अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा दिल दिखाया है। विपक्ष द्वारा अध्यक्ष को हटाने के लिए दायर नोटिस के मसौदे में खामियों के कारण उसे खारिज किया जा सकता था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने खुद अधिकारियों को इसे सुधारने का निर्देश दिया ताकि इसे जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जा सके।

स्पीकर ओम बिरला • फाइल/प्रेट्र

- लोकसभा सचिवालय को दिया निर्देश, नोटिस की तकनीकी त्रुटियों को किया जाए दूर
- विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव नोटिस कमियों के आधार पर ही हो जाता खारिज

मंगलवार दोपहर को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को सौंपे गए नोटिस पर विपक्ष के 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में विपक्ष ने नोटिस वापस ले लिया और तारीख में सुधार करते हुए एक नया नोटिस प्रस्तुत किया। सूत्रों ने बताया कि नोटिस में कथित तौर पर फरवरी 2025 की घटनाओं का चार बार उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर नियमों के अनुसार इसे खारिज किया जा सकता था। अध्यक्ष ने लोकसभा सचिवालय को दोषपूर्ण नोटिस को सुधारने और फिर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। दलों का आरोप है कि बिरला ने सदन में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है, जिसके चलते उन्होंने मामले के निपटारे तक सदन की अध्यक्षता से हटने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के लोकसभा उपनेता गौरव गोगोई, मुख्य सचेतक के सुरेश व सचेतक मोहम्मद जावेद ने कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की ओर से संविधान के अनुच्छेद 94सी के तहत लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को नोटिस सौंपा है। बिरला ने नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक अध्यक्ष की कुर्सी पर न बैठने का फैसला किया है। प्रस्ताव पर नौ मार्च को चर्चा हो सकती है।

सहकारी समितियों की स्थापना में तेजी, 27% लक्ष्य हासिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है 2024-25 और 2025-26 के दौरान देशभर में अब तक 8710 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) की स्थापना की गई है, जिससे निर्धारित लक्ष्य का 27 प्रतिशत हासिल हुआ है। शाह ने बुधवार को राज्यसभा में अपने लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने 2024-25 और 2025-26 वित्तीय वर्षों के दौरान 32,752 पीएसीएस बनाने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य के मुकाबले अब तक कुल 8,710 पीएसीएस का गठन किया गया है, जो कि इन दो वर्षीय अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 27 प्रतिशत की उपलब्धि को दर्शाता है। इस अवधि में सबसे अधिक पीएसीएस ओडिशा (1,543) में स्थापित किए गए। इसके बाद राजस्थान (1,387), उत्तर प्रदेश (1,099), मध्य प्रदेश (621) और उत्तराखंड (621) का स्थान रहा। गुजरात में लगभग 525 पीएसीएस और हिमाचल प्रदेश में 116 पीएसीएस स्थापित किए गए।

ड्रोन तकनीक के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं

सरकार ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार कर ली है। मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राज्यसभा में अपने लिखित उत्तर में कहा कि उनके मंत्रालय ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की है।

'जन प्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार मिले'

नई दिल्ली, प्रेट्र : आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को 'राइट टू रिकाल' तंत्र को लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का परफार्मेंस खराब रहता है तो उनके पांच साल के कार्यकाल के पूरा होने से पहले वे उन्हें हटा सकें। मौजूदा प्रणाली में जनप्रतिनिधियों की न तो जवाबदेही तय है और न ही प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है।

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान चड्ढा ने कहा कि भारत के नागरिकों को संसद और विधानसभा के सदस्यों को चुनने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वर्तमान में मतदाताओं के पास ऐसा कोई तंत्र यानी सीधा सिस्टम नहीं है कि वे काम न करने या गलत काम के आधार पर उन्हें बीच में ही वापस बुला सकें। 'राइट टू रिकाल' ढांचा मतदाताओं को एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देगा, जिससे वे एक निर्वाचित प्रतिनिधि को कानूनी रूप से हटा सकें। उन्होंने बताया कि देश में पहले से ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के महाभियोग की व्यवस्था है और सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है।

संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में बोलते राघव चड्ढा • एएनआइ

चड्ढा ने कहा कि सांसदों विधायकों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही के सिद्धांत को लागू करने से लोकतांत्रिक निगरानी को मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा तंत्र राजनीतिक दलों को मजबूत उम्मीदवारों को नामित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जवाबदेही को बढ़ाएगा और भ्रष्टाचार को कम करेगा। उन्होंने विश्व स्तर पर अमेरिका और स्विट्जरलैंड समेत 20 से अधिक लोकतंत्रों का उदाहरण दिया, जहां मतदाता की ओर से चुने गए प्रतिनिधि को हटाने का तंत्र मौजूद है। हालांकि, चड्ढा ने कहा कि इसके राजनीतिक दुरुपयोग या अस्थिरता को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की भी जरूरत है। साथ ही कहा कि चुनाव के बाद कम से कम 18 महीने का अनिवार्य लाक-इन पीरियड हो और उसके बाद ही रिकाल प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

संसद प्रश्नोत्तर

भाजपा सांसद ने मेरठ में एम्स बनाने की मांग उठाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंक का मुद्दा उठाया। उन्होंने इंसानों पर कुत्तों और बंदरों के हमलों की नियमित रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग की। भाजपा के बाबूभाई जेसांगभाई देसाई ने डिजिटल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जबकि उनकी पार्टी के ही लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की चिकित्सा जरूरतों के मद्देनजर मेरठ में एक एम्स स्थापित करने की मांग की।

2020 से 2025 तक करीब 39 लाख किलो गांजा जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि 2020 से नवंबर 2025 के बीच 38.89 लाख किलो गांजा जब्त किया गया। इनमें ओडिशा का हिस्सा कुल बरामदगी का 27% से अधिक है। यहां छह वर्षों की अवधि में बरामदगी 10.65 लाख किलो रही। इस अवधि में राजस्थान में 2020 के 14,826 किलो से बढ़कर 2025 में 58,146 किलो गांजे की बरामदगी दर्ज की गई। बंगाल में 2020 के 25,979 किलो से बढ़कर 32,456 किलो गांजा जब्त किया गया। आंध्र में 44,182 किलो गांजा जब्ती की गई। छग व कर्नाटक में भी गांजा जब्ती में गिरावट दर्ज हुई।

महिलाओं के आनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ सख्ती

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने इंटरनेट मीडिया और डेटिंग एप्लिकेशन समेत विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के बढ़ते दुरुपयोग पर ध्यान देते हुए और सख्त रुख अख्तियार किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आनलाइन लैंगिक हिंसा से निपटने के लिए गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है। इसमें पहचान की चोरी, फर्जी प्रोफाइल का दुरुपयोग, अश्लील सामग्री का प्रसार, और डीपफेक्स शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।

प्रत्येक रेल यात्री को मिलती है 45 प्रतिशत सब्सिडी

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें बहाल न करने के कारणों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को औसतन 45% की रियायत मिलती है। वैष्णव ने लिखित जवाब में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2023-24 में यात्री टिकटों पर 60,466 करोड़ की सब्सिडी दी। इससे यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 45% की रियायत मिलती है।

लोकसभा में कांग्रेस व भाजपा आमने-सामने

अमेरिका से हुई ट्रेड डील संपूर्ण सरेंडर, भारत माता को बेच दिया : राहुल गांधी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: यूं तो ट्रेड डील पर बुधवार सुबह ही अमेरिका की ओर से सफाई आ गई, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका से ट्रेड डील को 'संपूर्ण सरेंडर' करार देते हुए कहा कि सरकार ने भारत माता को बेच दिया है। दबाव में डील पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार समेत भारत की कोई भी सरकार, ऐसी डील पर तब तक हस्ताक्षर करती जब तक उस पर कोई दबाव न हो।' कहा, यह दुखद है कि भाजपा ने वित्तीय ढांचे को बचाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के हितों को सरेंडर किया गया और किसानों की रोजी-रोटी, कपड़ा, देश की ऊर्जा सुरक्षा व डाटा व उसके सोर्स कोड जैसे बेहद अहम क्षेत्रों को गिरवी रख दिया गया है।

लोकसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बुधवार को राहुल ने मार्शल आर्ट की विधा का हवाला देकर आरोप लगाया कि अमेरिका ने सरकार की गर्दन पकड़ रखी (चोकहोल्ड) है और इसीलिए उसने हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने वाली इस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। राहुल ने सरकार के निकट माने जाने वाले एक बड़े औद्योगिक घराने पर अमेरिका में दर्ज मामले और विवादित एपस्टीन फाइल्स के संदर्भ में अनिल अंबानी व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम लेते हुए आरोप लगाया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू और सत्तापक्ष के एतराज के बाद पीठासीन जगदंबिका पाल ने रिकार्ड से हटाने की बात कही। राहुल ने कहा कि 21वीं सदी के वर्तमान उथल-पुथल वाले भू-राजनीतिक परिदृश्य में हमारी 140 करोड़ की आबादी, खाद्य सुरक्षा, डाटा तथा ऊर्जा सुरक्षा चीन एवं अमेरिका के बीच महाशक्ति की होड़ में सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिका की मशीनी हाइटेक खेती के आगे हमारे किसानों को उसके रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। मारे टेक्सटाइल पर 18% टैक्स लगाकर उसे खत्म किया गया है क्योंकि बांग्लादेश पर शून्य टैक्स है जो भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट कर देगा।

संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में बोलते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी • प्रेट्र

- नेता प्रतिपक्ष अड़िग, किसानों के हित, ऊर्जा सुरक्षा, डाटा, टेक्सटाइल पर देश के हितों को रखा गिरवी
- सरकार पर लगाया दबाव व डर से डील का आरोप, कहा- दबाव के बिना कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती

राहुल से बोले जगदंबिका पाल, 'मेरी सलाह मानी होती, तो विपक्ष में न होते'

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा में बुधवार को बजट पर गर्मागर्म बहस और तीखे आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच कुछ हल्के-फुल्के पल भी आए। इस दौरान पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी से कहा कि अगर उन्होंने पहले उनकी सलाह मानी होती, तो वह विपक्ष में नहीं बैठे होते। बजट पर बहस में राहुल ने कुछ मुद्दे उठाए और कुछ नाम लिए। इस पर पाल ने एतराज जताया।

'चीन को सीक्रेट सर्विस देकर राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चंदा लेती रही कांग्रेस'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा में यह सियासी कबड्डी जैसा दृश्य था। बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगभग 45 मिनट तक सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और भाषण खत्म होते ही सदन से चले गए। इसके बाद सत्ता पक्ष की बारी थी। सत्ता पक्ष ने पहले राहुल को इसी बात पर घेरा और कटाक्ष किया कि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है, वह ज्यादा देर टिक नहीं पाते। फिर वरिष्ठ सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए पूछा- कांग्रेस जवाब दे, 2004 से 2014 तक चीन की भारतीय एमएसएमई के विरुद्ध क्या सीक्रेट सर्विस देकर बदले में राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते रहे? संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने राहुल के आरोपों को तथ्यहीन व नियम विरुद्ध बताते हुए ऐसे तथ्यों को कार्यवाही से हटाने की मांग की और चेताया कि अगर राहुल ने अपने आरोपों को नियमानुसार प्रमाणित नहीं किया तो भाजपा की ओर से विशेषाधिकार का नोटिस दिया जाएगा।

राहुल का भाषण समाप्त होते ही सत्ता पक्ष की ओर से रिजीजू ने तुरंत सदन छोड़ देने पर संसदीय नियम का हवाला दिया और कहा कि आपको सदन में रुककर आरोपों का जवाब भी सुनना चाहिए। साथ ही कहा कि राहुल देश को बेचे जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कोई माई का लाल नहीं हुआ जो भारत को बेच या खरीद सके। बजट के बिंदुओं की चर्चा के साथ भारत की बहुआयामी प्रगति का दावा करते हुए सांसद ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर भारतीय बाजार को चीनी उत्पादों के लिए खुला छोड़ रखा था। तंज कसा कि राहुल की प्रोग्रामिंग अंकल सैम (कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा) और अंकल सोरोस (भारत विरोधी अमेरिकी उद्योगपति जार्ज सोरोस) ने की है। इनमें अंकल सैम का सिमकार्ड और सोरोस का साफ्टवेयर है। ठाकुर ने पिछले दिनों कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री की कुर्सी के घेराव वाले घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए भी कांग्रेस व गांधी परिवार को घेरा।

लोकसभा में बुधवार को बोलते भाजपा सदस्य अनुराग ठाकुर • प्रेट्र

- सांसद अनुराग ठाकुर का करारा कटाक्ष, राहुल गांधी के अंदर अंकल सैम का सिम और सोरोस का साफ्टवेयर
- रिजीजू ने कहा- राहुल के आरोप झूठे और तथ्यहीन, प्रमाणित न किया तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस

प्रियंका के सामने कांग्रेस सांसदों ने बिरला को दी गालियां : रिजीजू

रिजीजू ने अपने संसदीय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में गंभीर आरोप लगाया कि बीते दिनों कांग्रेस के 20-25 सांसद लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में घुस गए थे। उस वक्त वह स्वयं वहां मौजूद थे और देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल के सामने कांग्रेस सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गालियां दे रहे थे, लेकिन प्रियंका और वेणुगोपाल ने उन्हें नहीं रोका।

सुधांशु ने दी सलाह, कांग्रेस को राहुल गांधी से डरना चाहिए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: राहुल गांधी को संविधान और संसद की मर्यादा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए भाजपा ने कांग्रेस को उनसे डरने की सलाह दी है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के पुराने कामों की याद दिलाते हुए कहा कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने जिन दो कंपनियों में काम किया था, वे दोनों बंद हो चुकी हैं और उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी का प्रदर्शन रसातल में चला गया।

प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी • फाइल फोटो

- कहा- जिन दो कंपनियों में किया काम, दोनों हो गई हैं बंद
- अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस का प्रदर्शन रसातल में पहुंचा दिया

त्रिवेदी ने परमाणु परीक्षण, बोल्कर रिपोर्ट और भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की याद दिलाते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि कौन किससे डरता है और कौन देश बेचता है। उन्होंने बोल्कर रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि तेल के कूपन के मार्फत मिले पैसे सीधे कांग्रेस के खाते में गए थे। इसी तरह परमाणु समझौते में अमेरिकी दबाव में भारत को झुकते हुए सबने देखा था। यहां नहीं, इस समझौते को संसद से पास कराने के लिए तत्कालीन सांसदों ने लाखों रुपये की रिश्वत दिए जाने के आरोप सदन में लगाया था। इसी तरह से नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि सोनिया गांधी ने उन्हें विदेश मंत्री पद से अमेरिकी दबाव में हटाने की मजबूरी बताई थी। त्रिवेदी ने राहुल से पूछा कि नरसिंह राव सरकार के कार्यकाल में तय परमाणु परीक्षण किसके दबाव में टाल दिया गया था।

त्रिवेदी ने बजट पर बहस के दौरान सरकार पर राहुल के अरुचिकर और जहर उगलने वाले शब्दों पर भी कड़ी आपत्ति जताई और उन पर व कांग्रेस पर सड़क छाप भाषा इस्तेमाल करके एवं सड़क छाप आचरण करके सदन की गरिमा एवं पवित्रता को गिराने का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने कहा, "मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वह हमेशा देश के विरुद्ध और विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए क्यों खड़ी होती है। चाहे हावित्जर हो, अगस्ता वेस्टलैंड डील हो या हिंडनबर्ग, कांग्रेस ही उनके साथ खड़ी रही।"

नरवणे की किताब के विवाद पर उन्होंने कहा कि राहुल के दिए तथ्यों का पूर्व सेना प्रमुख और प्रकाशक दोनों ने खंडन किया, फिर भी वह बेशर्मी से यह मुद्दा उठाते रहे। त्रिवेदी ने कहा, "राहुल गलवन पर बोलना चाहते थे लेकिन डोकलाम पर ही अड़े रहे। जब आप उपलब्ध कराए गए पाठ को पढ़ते हैं तो यही होता है। जब डोकलाम हुआ था, तब न तो जनरल नरवणे सेना प्रमुख थे और न ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे।" कांग्रेस से सवाल किया कि उसने नरवणे की किताब पर विवाद क्यों खड़ा किया, जबकि यह सरकारी गोपनीयता कानून और आर्मी एक्ट का साफ उल्लंघन है। याद दिलाया कि 1971 के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व जनरल मानेकशा के बीच हुई बातचीत अभी भी गोपनीय है।

44 वर्ष बाद मुंबई महानगरपालिका में भाजपा का महापौर निर्वाचित

महापौर चुने जाने पर बीएमसी मुख्यालय में अभिवादन करतीं रितु तावड़े • प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी और सबसे संपन्न महानगरपालिका बीएमसी में बुधवार को नया राजनीतिक इतिहास रच दिया गया। भाजपा की वरिष्ठ पार्षद रितु तावड़े निर्विरोध मुंबई की 78वीं महापौर चुनी गईं। इस जीत के साथ ही बीएमसी मुख्यालय के शीर्ष पर 44 वर्षों के बाद भाजपा का कब्जा हो गया है। अंतिम बार 1982-83 में भाजपा के डा. प्रभाकर पई इस पद पर आसीन हुए थे। विपक्षी खेमे, शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार मैदान में न उतारने के कारण रितु का निर्वाचन महज औपचारिकता रह गया था। सीएम देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे।

"वीबी-जी राम जी" के तहत दस लाख करोड़ खर्च होंगे : शिवराज

अगरतला, आइएएनएस : केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले पांच वर्षों में ग्रामीण भारत में 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो कि विकसित भारत "रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)" (वीबी-जी राम जी) के तहत होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना विकसित भारत के निर्माण के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में वीबी-जी राम जी कार्यक्रम पर एक सम्मेलन में बुधवार को केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह योजना समाज के सभी वर्गों की सेवा के लिए बनाई गई है। ग्रामीण कार्यक्रम के लिए 1,51,282 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त 55 हजार करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिससे कुल आवंटन एक वर्ष में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा।

सुनेत्रा पवार ने मोदी और शाह से मुलाकात की

नई दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के दौरान (बाएं से) महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे और जय पवार • प्रेट्र

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुंबई स्थित मंत्रालय में अपना पदभार संभालने के एक दिन बाद बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। 31 जनवरी को राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली सुनेत्रा पवार मोदी से मुलाकात के दौरान अपने बेटों पार्थ और जय, राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे के साथ थीं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार ने संसद का भी दौरा किया। सुनेत्रा पवार ने 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में अपने पति और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मृत्यु के कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में उनका स्थान लिया।

विमान दुर्घटना पर राजनीति शुरू

राज्य ब्यूरो, मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजीत पवार की बारामती में हुई विमान दुर्घटना अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बनती जा रही है। हादसे के 13 दिन बाद उनके भतीजे और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार द्वारा इस घटना को सौ प्रतिशत घात करार देने के बाद महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को मुंबई में और बुधवार को दिल्ली में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन देते हुए रोहित पवार ने अजीत पवार की विमान दुर्घटना को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र विदेशी एजेंसी से कराने की मांग की। रोहित पवार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार किसी भी संदेह को अनसुना नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विमानन मंत्रालय और डीजीसीए पहले से ही गहन जांच कर रहे हैं।

- अजीत पवार के भतीजे विधायक रोहित पवार ने दुर्घटना को साजिश बताया
- मुख्यमंत्री ने कहा, विमानन मंत्रालय और डीजीसीए मामले की जांच कर रही

वहीं राकांपा के संस्थापक एवं उनके दादा शरद पवार इसे महज एक दुर्घटना बताकर इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील कर चुके हैं। शिव सेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने घटना को रहस्यमयी बताते हुए इसकी तुलना पूर्व के अन्य संदिग्ध मामलों से की है।

हरदीप पुरी की सफाई-एपस्टीन से तीन या चार मुलाकातें हुई थीं, मगर निजी तौर पर नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा 'एपस्टीन फाइल्स' का मुद्दा उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि उनकी एपस्टीन से केवल तीन-चार मुलाकातें हुई थीं और वे भी पूरी तरह पेशेवर तथा आधिकारिक प्रकृति की थीं। अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए पुरी ने कहा कि उनका किसी भी अवैध गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में दस्तावेज दिखाते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी • एएनआइ

राहुल गांधी ने अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों का हवाला देते हुए लोकसभा में दावा किया था कि जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में हरदीप सिंह पुरी का नाम भी है। एपस्टीन की मृत्यु के बाद जारी दस्तावेजों में दुनिया भर के कई राजनेताओं, उद्योगपतियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, जो कभी न कभी उसके संपर्क में रहे थे। राहुल के आरोपों के बाद पुरी ने पत्रकार वार्ता कर सफाई दी। कहा कि वर्ष 2009 में जब वे न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि (राजदूत) थे और बाद में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट से जुड़े थे तो उसी दौरान वे एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में एपस्टीन से मिले थे। ये मुलाकातें इंडिपेंडेंट कमीशन आन मल्टीलेटरलिज्म व संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ से जुड़े विमर्श के संदर्भ में थीं। पुरी ने स्पष्ट किया कि 2009 से 2017 के बीच शिष्टमंडल के रूप में तीन या चार औपचारिक बैठकें हुईं। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में उनके वरिष्ठ टेरजे राड-लार्सन एपस्टीन को जानते थे व संस्थागत स्तर पर बातचीत होती थी, इसका रिकार्ड सार्वजनिक डोमेन में है। पुरी ने बताया कि अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 लाख से अधिक दस्तावेज व ईमेल सार्वजनिक किए हैं, जिनमें बैठकों का उल्लेख है।

खराब हेयरकट पर 25 लाख मुआवजे का सुप्रीम आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : क्या एक खराब हेयरकट किसी को करोड़ों रुपये का मुआवजा दिला सकता है? इस दिलचस्प सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त और स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा-नहीं, जब तक कथित नुकसान का ठोस, विश्वसनीय और प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया जाए, तब तक नहीं। अदालत ने दो टूक कहा कि करोड़ों का हर्जाना भावनात्मक तर्कों, अनुमानों या मात्र दावों के आधार पर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए वास्तविक क्षति का स्पष्ट और प्रामाणिक आधार होना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 34 पेज के फैसले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के दो करोड़ रुपये के मुआवजे के आदेश को बदलकर 25 लाख कर दिया। अदालत ने कहा कि इतना बड़ा दावा होने पर आयोग का दायित्व था कि वह साक्ष्यों का गंभीर परीक्षण करता और स्पष्ट करता कि वास्तविक नुकसान की गणना किस आधार पर की गई। केवल सामान्य चर्चा या फोटोकापी दस्तावेजों के आधार पर इतनी बड़ी राशि तय नहीं की जा सकती।

एनसीडीआरसी ने सेवा में कमी पर तय किया था दो करोड़ का मुआवजा, कोर्ट ने कहा- मुआवजे का निर्धारण तथ्यात्मक हो

माडल ने याचिका में कहा-पहुंचा मानसिक आघात, पेशेवर छवि को भी हुई क्षति मामला वर्ष 2018 का है। माडल और मैनेजमेंट प्रोफेशनल आशना राय दिल्ली के पांच सितारा होटल आइटीसी मौर्य के सैलून में हेयरकट के लिए गई थीं। उनका आरोप था कि हेयर स्टाइलिस्ट ने अनुरोध से अधिक छोटे बाल काट दिए, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा और उनकी पेशेवर छवि को नुकसान हुआ। उन्होंने दावा किया था कि अधिक छोटे बाल काट देने के कारण उन्हें माडलिंग और फिल्म उद्योग के कई बड़े असाइनमेंट गंवाने पड़े। एनसीडीआरसी ने सेवा में कमी मानते हुए दो करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार का निर्देश दिया था, लेकिन अप्रैल 2023 में आयोग ने दोबारा दो करोड़ रुपये मुआवजा देने का ही आदेश पारित किया। इस फैसले को आइटीसी लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-प्रमाणों का ठोस मूल्यांकन आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले ही उपभोक्ता आयोगों पर सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) सख्ती से लागू नहीं होती, फिर भी प्रमाणों का ठोस मूल्यांकन आवश्यक है। मानसिक आघात का हवाला देकर मूल दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भारी मुआवजे का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने यह भी कहा कि आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि दो करोड़ रुपये की वास्तविक आर्थिक क्षति कैसे सिद्ध होती है।

भाजपा में आने का मिला था आफर : भूपेश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • रायपुर: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल के पाडकास्ट में बघेल ने दावा किया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था, इन्कार करने पर केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़वाए गए।

ये वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया है। इसमें भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कई बार बातचीत के लिए बुलाया था। आरोप लगाया कि जब वे इन मुलाकातों से बिना किसी राजनीतिक कमिटमेंट के लौटते थे तो उसके 8-10 दिनों के भीतर ही उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो जाती थी।

संपादकीय

महापौर निवडीचे धक्केबुक्के!

उद्धव व राज या ठाकरे बंधूंनी महापालिका निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा बनविलेला 'मुंबईत मराठी महापौर' हा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाने श्रीमती रितू तावडे यांना उमेदवारी दिल्याने निकालात निघाला. मुंबईच्या प्रथम नागरिक कोण, हा प्रश्न मागे पडला. हा आपल्याच 'मुद्द्या'चा विजय म्हणत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने रिंगणात आपला उमेदवार उतरवला नाही. मुंबईच्या इतिहासात १९८२ नंतर प्रथमच भाजपला महापौरपद आणि तेही बिनविरोध मिळाले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला उपमहापौरपद मिळाले. राज्याच्या 'पश्चिम' टोकावर निवडणुकीतील चुरस अशी लोप पावत असताना 'पूर्वे'कडे चंद्रपूर या छोट्या महापालिकेत मात्र वेगळेच राजकीय नाट्य रंगले होते. त्या नाट्याने राज्याच्या 'टोका'वरचे चंद्रपूर अचानक राजकारणाच्या 'केंद्र'स्थानी आले. थोडे प्रयत्न केले तर मिळू शकणारी काँग्रेसची सत्ता हिरावली गेली. भाजपला महापौरपदाची लॉटरी लागली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात झाडून साऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजप, शिंदेसेना व दिवंगत अजित पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा महायुतीचा डंका वाजला. काँग्रेस किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची उबाठा शिवसेना अथवा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला अगदीच किरकोळ यश मिळाले. विरोधकांना यश देणाऱ्या आणि महायुतीला चकवा देणाऱ्या लातूर, मालेगाव, वसई-विरार, परभणी अशा शहरांमध्ये चंद्रपूर आहे. तिथे भाजपची पिछेहाट झाली. काँग्रेसची सरशी झाली. काँग्रेस पक्ष बहुमताच्या जवळ पोहोचला. अर्थात, कोणालाही स्पष्ट बहुमत नसल्याने ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे सहा, त्यांच्यासोबत आघाडी करून लढलेल्या ॲड. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीचे दोन आणि दोन अपक्षांच्या मतांचे मोल वाढले. एरव्ही महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेस व उबाठा सेना एकत्र यायला हवी होती. तथापि, काँग्रेसमध्ये दोन गटांमध्ये संघर्ष उभा राहिला. चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते विजय वडेट्टीवार यांना निवडणुकीच्या आधीपासून विरोध केला. वडेट्टीवार यांचा ब्रह्मपुरी मतदारसंघ चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात नसल्याने त्यांनी शहराच्या राजकारणात लक्ष घालू नये, पक्षाचे उमेदवार आपल्याच मर्जीचे असावेत, असे धानोरकरांचे म्हणणे. दोघांमधील वाद इतका विकोपाला गेला की, पुण्यावरून परत येत असलेल्या नगरसेवकांची लक्झरी बस समृद्धी महामार्गावर अडवून हल्ला करण्यापर्यंत मजल गेली. हा वाद आधी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यापर्यंत व नंतर थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचला. वडेट्टीवार व धानोरकर यांच्यात वरकरणी समझोता झाला. महापौर, उपमहापौर व गटनेता पदाचे वाटप ठरले. लेखी करार झाला. पण, तोवर उबाठा सेना व अपक्ष बिथरले होते. वारंवार अपमान होत असल्याने वडेट्टीवार यांनी निवडणुकीतून अंग काढून घेतले आणि मग बहुमताचा डोलारा प्रतिभा धानोरकर व त्यांच्यासोबत किल्ला लढविणारे सुनील केदार यांना सांभाळता आला नाही. बहुमताच्या जवळ असूनही सत्ता गमावण्याची नामुष्की काँग्रेसवर ओढवली. महाविकास आघाडीचे जहाज काँग्रेसच्या अंतर्गत गटबाजीमुळे बुडत असल्याचे पाहून उबाठा नगरसेवकांनी भारतीय जनता पक्ष जवळ केला. राजकीयदृष्ट्या तसे करणे शक्य नसल्याने वंचितचे दोन नगरसेवक अनुपस्थित राहिले. एआयएमआयएमचे नगरसेवक तटस्थ राहिले. चंद्रपूरच्या या घडामोडींमुळे राज्याचे लक्ष आता मराठवाड्यातील परभणी या आणखी एका 'ड' वर्ग महापालिकेकडे लागले आहे. तिथे उबाठा सेनेला काँग्रेसच्या मदतीची गरज आहे. काँग्रेस पक्ष चंद्रपूरमधील वाद स्थानिक ठरवून महाविकास आघाडीला पोषक अशी व्यापक भूमिका घेतो, की विदर्भातील नामुष्कीचे उट्टे मराठवाड्यात काढतो, ते पाहायचे. वंचित व एमआयएमच्या नगरसेवकांची भूमिका हा चंद्रपूरच्या राजकीय नाट्यातील एक महत्त्वाचा उपपदर. वंचित बहुजन आघाडीला लातूर व अकोला वगळता फार मोठे यश कुठे मिळालेले नाही. एमआयएमचे तसे नाही. जानेवारी महिन्याच्या मध्यावर निवडणूक झालेल्या राज्यातील २९ महापालिकांपैकी १३ ठिकाणी मिळून एमआयएमचे १२६ नगरसेवक निवडून आले. जिथे महायुतीमधील तिन्ही पक्षांना स्वबळावर किंवा महायुती म्हणून स्पष्ट व मोठे बहुमत आहे तिथे एमआयएमची काही भूमिका नव्हती व नाही. तथापि, जिथे महायुतीला काठावरचे बहुमत आहे किंवा विरोधी आघाडी बहुमताच्या जवळ आहे, तिथे एमआयएम गैरहजर राहण्याची सोयीस्कर राजकीय भूमिका घेत असेल तर त्या भूमिकांचे परखड विश्लेषण होणारच.

मैत्री हीच भारताच्या स्वधर्माची पूर्वअट !

भारतीय प्रजासत्ताकाचा स्वधर्म स्पष्ट करणारी चार सूत्रे धार्मिक, सामाजिक, राजकीय आंदोलनांच्या आधारे अधोरेखित करता येतात. त्या सूत्रांची चर्चा!

योगेंद्र यादव
राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोडो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया

भारतीय प्रजासत्ताकाची स्थापना केवळ ७६ वर्षांपूर्वीच झालेली असली तरी त्याचा 'स्वधर्म' अत्यंत प्राचीन आहे. तीन हजार वर्षांपूर्वीच त्याचा पाया घातला गेला होता. आजचे आपले गणराज्य म्हणजे 'भारतवर्ष', 'हिंदुस्तान' आणि 'इंडिया' अशा तीन प्रवाहांचा त्रिवेणी संगम आहे. हा स्वधर्म आपल्याला प्राचीन भारताच्या सनातन मूल्यांत शोधता येणार नाही, तर तो विविध आंदोलनांच्या आविष्कारात आढळेल. प्रथम बौद्ध आणि जैन धर्मदर्शनांनी, त्यानंतर सुफी आणि भक्ती परंपरांनी आणि आधुनिक काळात राष्ट्रीय आंदोलनाने प्रस्थापित सत्तेला ललकारले; आपल्या स्वधर्मातल्या मूल्यांचा मूळ अर्थ शोधला आणि जनमानस ढवळून काढले. भारतीय प्रजासत्ताकाचा स्वधर्म ढोबळमानाने स्पष्ट करणारी चार सूत्रे आपल्याला याच धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांच्या आधारे अधोरेखित करता येतील. या आणि यापुढील तीन लेखांत ही चार सूत्रे मी विशद करणार आहे.

यातील पहिले सूत्र आहे- 'मैत्री'. भिन्नभिन्न मते, पंथ, संप्रदाय आणि अनुचरांचे समूह यांचे सहजीवन हे नेहमीच भारतीय समाजाचे एक अंगभूत लक्षण राहिले आहे. सहअस्तित्व ही केवळ अपरिहार्यता न राहता, एक आदर्श म्हणून ते विकसित करण्याचे प्रयत्न येथील समाज आणि शासनकर्ते सुरुवातीपासूनच करत आले आहेत. ऋग्वेदात मित्र ही देवता मिलाफ, समन्वय आणि सौहार्दाचे प्रतीक आहे. छांदोग्य उपनिषदात मित्र हा सामंजस्याचे प्रतीक आहे. बुद्धांनी याचाच विस्तार करून मैत्री (पाली भाषेत 'मेत्ता') हा चार ब्रह्मविहारांपैकी एक आदर्श म्हणून मांडला आहे. मैत्री म्हणजे द्वेषहीनता आणि समभाव. सम्राट अशोकाने द्वेषहीनता, अहिंसा आणि स्नेह यांची सांगड सामाजिक सद्भावाशी घातली. सर्वधर्मसमभाव ही शासकीय नीती आणि संयम हा सामाजिक आदर्श बनवून, अशोकानेच पंथनिरपेक्षतेचा पाया घातला.

सुलह-ए-कुल नीतीद्वारे अकबराने अशोकाच्या याच धोरणाचा विस्तार केला : 'बादशहा कोणत्याही धर्माचे पालन करणारा असो, प्रजेला आपापला धर्म, पूजाअर्चना आणि रूढीपरंपरांचे पालन करण्याची पूर्ण मोकळीक असेल. सक्तीने धर्मपरिवर्तन होणार नाही. धार्मिक बाबी, संस्था आणि विधीपालनात राज्यसंस्था कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. प्रशासकीय कायदेकानून कोणत्याही विशिष्ट धर्माचे असणार नाहीत. शासन सर्व धर्मक्षेत्रे आणि संस्थांना संरक्षण आणि अनुदान देईल.' - अकबराचे हे धोरण आधुनिक अर्थाने सेक्युलर नव्हते; पण अकबराने भारताचा स्वधर्म नीट ओळखला होता. संविधानातील पंथनिरपेक्षता म्हणजे अशोक आणि अकबर यांच्या धोरणाचाच विस्तार आहे. आजच्या भारतात 'सेक्युलर' हा शब्द याच अर्थाने वापरला जातो. सर्व धर्मसंप्रदायांना समदृष्टीने पाहणे आणि एकाच संप्रदायाच्या वर्चस्वाला विरोध करणे हाच आपल्या 'धर्मनिरपेक्षते'चा सर्वसामान्य अर्थ आहे; परंतु शब्दांचा पूर्वेतिहास आणि गर्भितार्थ पाहता धर्मनिरपेक्षता किंवा सेक्युलरवाद यापैकी कोणत्याच शब्दातून हा अर्थ नीट व्यक्त होत नाही. कारण आपल्याकडे धर्म म्हणजे रिलिजन नव्हे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता हा शब्द आपला समाज नैतिक मूल्यांबाबत उदासीन असल्याचा गैरसमज अकारण पसरवतो. या अर्थाने राज्यघटनेच्या अधिकृत प्रतीत वापरलेला पंथनिरपेक्षता हा शब्द अधिक संयुक्तिक आहे.

शब्द कोणताही असो, अशोक आणि अकबरापुढे असलेलेच आव्हान आजही आपल्यासमोर आहे.

भिन्नभिन्न धर्म व दृष्टिकोन असलेल्या माणसांमध्ये समभाव निर्माण करणे आणि वर्चस्ववाद, द्वेष आणि हिंसेला आळा घालणे ही दोन्ही आव्हाने जुनीच आहेत; पण वर्तमान परिस्थितीत ती अधिक तीव्र झाली आहेत. विविध धर्मसमूहांतील हानिकारक रूढींमध्ये सुधारणा करण्याची जबाबदारी आजची राज्यसंस्था झटकू शकत नाही. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी 'मैत्री' आणि 'सुलह-ए-कुल' हाच मार्ग स्वीकारून आपल्याला सर्वधर्मसमभाव परिभाषित करावा लागेल. ही 'देशी दृष्टी' धार्मिकतेचा सन्मान करते. धर्माबाबत ती मुळीच उदासीन नाही. कारण धर्म हा तर नैतिकतेचा स्रोत आहे. कोणत्याही विशिष्ट धर्माबाबत मात्र ती निष्पक्ष आहे. मैत्रीभावातून उदयाला आलेली असल्याने ही दृष्टी सर्व धार्मिक समुदायांबाबत समभाव बाळगते. वेगवेगळ्या पंथांदरम्यान परस्परविश्वास आणि सन्मानाचे नाते रुजवत आवश्यक तेथे धार्मिक समुदायांतर्गत होत असलेले शोषणही थांबवणे ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी आहे.

राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत धर्मनिरपेक्षता हा शब्द केव्हा आणि का घातला गेला ही चर्चा निरर्थक आहे. आपल्या राज्यघटनेची मूलभूत बांधणीच मुळात सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वानुसार झालेली होती. या अर्थाने सर्वधर्मसमभाव ही केवळ घटनात्मक तरतूद नाही; सभ्यतेच्या मूलभूत मूल्यांपैकी ते एक मूल्य आहे. भारत देशाला अखंड राखण्यासाठी स्वीकारलेली ती एक अनिवार्य पूर्वअट आहे. भारतीय गणराज्याच्या स्वधर्माचे हे आद्य सूत्र होय.

yyopinion@gmail.com

अन्वयार्थ

एच-१बी व्हिसा अमेरिकेने रद्दच करून टाकला तर?

एच-१बी व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठीचे विधेयक ही भारतासाठी आत्मपरीक्षणाची संधी मानली पाहिजे. धोरणात्मक पुनर्रचनेची हीच वेळ आहे !

रवी टाले
कार्यकारी संपादक, लोकमत, अकोला

एच-१बी व्हिसा व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठी अमेरिकेत विधेयक सादर झाल्याने, कुशल मनुष्यबळाचे स्थलांतर आणि त्याचे अमेरिकेतील नोकऱ्यांवर होणारे परिणाम, या विषयावरील चर्चेला नव्याने तोंड फुटले आहे. भारताच्या दृष्टीने हा मुद्दा भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) अर्थव्यवस्थेचा, मनुष्यबळ निर्यातीचा आणि भारत-अमेरिका तंत्रज्ञान भागीदारीचा केंद्रबिंदू आहे. एच-१बी हा अमेरिकेतील कंपन्यांना विशेष तांत्रिक कौशल्यांची आवश्यकता असलेल्या पदांवर परदेशी कामगारांना तात्पुरते कामावर ठेवण्याची परवानगी देणारा एक बिगर-स्थलांतरित (नॉन इमिग्रंट) कार्य व्हिसा आहे.

गेल्या दशकातील एच-१बी लाभार्थ्यांपैकी सुमारे ७५ टक्के भारतीय आहेत. स्वाभाविकपणे एच-१बी संदर्भातील कोणत्याही बदलाचा भारतावर थेट परिणाम होतो आणि आता तर ती व्यवस्थाच संपुष्टात आणण्याची तयारी चालली आहे.

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान - व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन (आयटी - बीपीएम) उद्योगाचे वार्षिक उत्पन्न २५० अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचले आहे आणि त्यातील तब्बल ५०-६० टक्के महसूल अमेरिकन बाजारातून येतो. अनेक बड्या भारतीय आयटी कंपन्यांचे मोठे ग्राहक अमेरिकेत आहेत. एच-१बी व्हिसामुळे या कंपन्यांना विशिष्ट कौशल्य असलेले कर्मचारी तात्पुरते अमेरिकेत पाठवून प्रकल्प राबवता येतात. हे 'ऑनसाइट - ऑफशोर मॉडेल' भारतीय कंपन्यांच्या स्पर्धात्मकतेचा कणा ठरले आहे.

एच-१बी व्हिसा व्यवस्था संपुष्टात आल्यास, अमेरिकन कंपन्यांना स्थानिक कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी लागून, त्यांचा वेतन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल. कारण अमेरिकेतील तंत्रज्ञांचे सरासरी वेतन भारतापेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. परिणामी, अमेरिकन कंपन्यांचा नफा घटेल. दुसरीकडे भारतीय कंपन्यांचा व्यवसायही कमी होईल. कोरोनानंतर अमेरिकन कंपन्यांना भारतातूनच प्रकल्प हाताळणे अधिक सोयीचे वाटू लागले आहेच. एच-१बीवरील निर्बंध भारतीय कंपन्यांना देशांतर्गत 'डिलिव्हरी सेंटर्स' मजबूत करण्यास प्रवृत्त करू शकतात. परिणामी, बंगळुरू, हैदराबाद, पुणेसारख्या आयटी क्षेत्रातील आघाडीच्या शहरांबरोबरच, टियर-२ शहरांमध्येही तंत्रज्ञानाधारित रोजगार वाढू शकतो.

भारतीय विद्यार्थी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकीतील उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत जातात. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अनेक विद्यार्थी वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) आणि त्यानंतर एच-१बी मार्गे नोकरी मिळवतात. एच-१बी मार्ग बंद झाल्यास भारतीय युवक, कौशल्याधारित स्थलांतर धोरणे अधिक सुलभ असलेल्या कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटनसारख्या देशांकडे वळू शकतात. शिवाय भारतातील स्टार्टअप परिसंस्था, युनिकॉर्न्सची वाढती संख्या, डिजिटल पेमेंट क्रांती, सेमी कंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील धोरणात्मक गुंतवणूक, यामुळे देशांतर्गत संधीही वाढत आहेत.

अमेरिकेत एच-१बीसंदर्भात दोन मतप्रवाह आहेत. एक वर्ग स्थानिकांना संरक्षण, वेतनातील स्थिरता आणि स्थलांतराबाबतची जनभावना, या मुद्द्यांच्या आधारे एच-१बी व्यवस्थेवर टीका करतो, तर दुसरा वर्ग काही अभ्यासांच्या आधारे, एच-१बी व्यवस्था नवोपक्रम आणि पेटंट निर्मिती वाढवते, असा युक्तिवाद करतो. भारतीय धोरणकर्त्यांनी या राजकीय-आर्थिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करूनच प्रतिसाद द्यायला हवा. भावनिक प्रतिक्रिया किंवा केवळ निषेध नोंदवणे पुरेसे ठरणार नाही. तंत्रज्ञान, संरक्षणासारखी क्षेत्रे आणि 'क्वाड'सारख्या बहुपक्षीय व्यासपीठांवरील सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर, उच्च कौशल्याधारित कामगारांच्या मुद्द्यावर विशेष संवाद यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेने भारतीय कुशल मनुष्यबळासाठी कवाडे बंद केल्यास आपण इतर विकसित देशांकडे मोहरा वळवू बघत आहोत. पण, उद्या त्या देशांमध्येही अमेरिकेसारखी मानसिकता तयार झाल्यास काय? आपणच ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करून जगभरातील प्रतिभा आकर्षित करण्याचा प्रयत्न का करू नये? त्यासाठी आपली मानसिकता, धोरणे, व्यवस्थेत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. आज भारताचा संशोधन आणि विकास (आर अँण्ड डी) यावरील खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे जीडीपीच्या जेमतेम ०.७ टक्के आहे, तर अमेरिकेचा दोन ते तीन टक्के ! ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेसाठी आपल्याला सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणूक वाढवणे अपरिहार्य आहे.

ही भारतासाठी व्यापक आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. गेली दोन दशके भारतीय आयटी मॉडेल अमेरिकन बाजारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिले. जागतिक राजकारण, तंत्रज्ञान आणि स्थलांतर धोरणे वेगाने बदलत असताना, केवळ परकीय संधींवर अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. आत्मनिर्भर तंत्रज्ञान परिसंस्था, उच्च दर्जाचे शिक्षण, संशोधनात गुंतवणूक आणि जागतिक भागीदारीचा संतुलित विस्तार, याच मार्गाने भारत दीर्घकालीन प्रगती साधू शकतो. हे लक्षात घेऊन, एच-१बीवरील संकटामुळे भेदरून न जाता, ती धोरणात्मक पुनर्रचनेची संधी समजायला हवी !

ravi.tale@lokmat.com

जगभर

उद्दाम पर्यटकांमुळे जपानचा चेरी ब्लॉसम रद्द!

कल्पना करा, पर्यटकांनी परवानगी न घेता तुमच्या घराचं दार उघडलं किंवा तुमच्या खासगी बागेत ते घुसले किंवा रहिवासी जागेत त्यांनी शौच केले तर? फुजियोशिदा या जपानमधल्या सुंदर शहरात अगदी असंच घडलंय. माउंट फूजीच्या पायथ्याशी वसलेलं हे शहर वसंत ऋतूतील चेरी ब्लॉसमसाठी प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी तेथे मोठा महोत्सव भरवला जातो. यावेळी मात्र हा महोत्सव अचानक बंद करून आयोजकांनी इतक्या वर्षांची आपली ही परंपरा पहिल्यांदाच तोडली आहे.

जपानमधला माउंट फूजी संपूर्ण जगात त्याच्या सौंदर्यासाठी ओळखला जातो. वसंत ऋतूत जेव्हा चेरी ब्लॉसम फुलतात, तेव्हा इथली रौनक पाहण्यासारखी असते. माउंट फूजीच्या बर्फानं झाकलेल्या शिखरांचं आणि चेरी ब्लॉसमच्या सुंदर दृश्यांचं दर्शन घ्यायला संपूर्ण जग आतुर असतं. मात्र पर्यटकांची प्रचंड गर्दी आणि ट्रॅफिक जाममुळे हैराण होऊन जपानमधल्या फुजियोशिदा शहरानं यंदा एक कठोर निर्णय घेतलाय, तो म्हणजे येथील जगप्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिव्हलच रद्द करण्याचा. त्यामुळे संपूर्ण जगच आश्चर्यचकित झालंय. पण त्यांच्या या निर्णयाचं अनेकांनी कौतुकही केलंय.

अधिकाऱ्यांना नाइलाजानं हा निर्णय घ्यावा लागला, कारण पर्यटकांची वाढती संख्या शहराच्या व्यवस्थेवर मोठं ओझं ठरत होती. भीषण ट्रॅफिक जाममुळे लोक त्रस्त होते आणि अनेक ठिकाणी कचऱ्यांचे ढीग साचत होते. पण समस्या एवढ्यावरच थांबत नव्हती. पर्यटकांचं गैरवर्तन स्थानिक लोकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत होती.

शहरातल्या रहिवाशांनी पर्यटकांच्या वर्तनाबाबत अतिशय धक्कादायक खुलासे आणि तक्रारी केल्या आहेत. अहवालानुसार काही पर्यटक स्थानिकांच्या घरांची दारं उघडून परवानगी न घेता बाथरूम

वापरायचे. काही जण त्यांच्या खासगी बागांमध्ये शिरायचे, तर काही लोक थेट रहिवासी जागांवरच शौच करताना आढळले. यासंदर्भात महापौर शिगेरू होरीउची म्हणतात, हा निर्णय नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि शांततेच्या संरक्षणासाठी घेतला आहे. बेशिस्त पर्यटकांचं हे वाढतं संकट आमच्या समाजाच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करीत आहे.

हा उत्सव २०१६ मध्ये 'अराकुरायामा सेन्गेन पार्क'मध्ये सुरू झाला, जिथून पॅगोडा आणि माउंट फूजीचं दृश्य अत्यंत मनोहारी दिसतं. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हा उत्सव सुरू करण्यात आला. मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या फोटोंमुळे आणि जपानी चलन येन कमकुवत झाल्यानं इथली गर्दी प्रचंड वाढली. पर्यटन हंगामात इथे दररोज दहा हजारांपेक्षाही अधिक लोक येतात. एवढ्या पर्यटकांना सांभाळणं आता शहराच्या क्षमतेबाहेर गेलंय.

चेरी ब्लॉसम फेस्टिव्हल रद्द केला असला तरी एप्रिल आणि मे महिन्यांतही पर्यटक येत राहतील, अशी अधिकाऱ्यांना अपेक्षा आहे. हा निर्णय जपानमधल्या 'ओव्हरटूरिझम'वर नियंत्रण मिळवण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांचा भाग आहे. गेल्या वर्षी जपानमधील आणखी एका शहरानं पर्यटकांची गर्दी रोखण्यासाठी एका प्रसिद्ध स्पॉटवर मोठा काळा पडदा लावला होता. केवळ जपानच नाही, तर रोम आणि व्हेनिससारखी शहरंही आता गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी एंट्री फीसारखी पावलं उचलताहेत. रोममध्ये ट्रेवी फाउंटनजवळ जाण्यासाठी २ युरो, तर व्हेनिसमध्ये दिवसा येणाऱ्या प्रवाशांकडून ५ ते १० युरो शुल्क आकारलं जात आहे.

जनमन

मनातला 'विटाळ' कधी जाणार?

सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड्स आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याबाबत नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत. इतक्या क्षुल्लक पण शरीरधर्माशी निगडित अत्यावश्यक बाबींत लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निर्देश द्यावेत यावरून आपली सरकार नामक व्यवस्था नेमकी करते काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मध्यंतरी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने यूडायस प्लस २०२४-२५ हा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यात देशभरातील शाळा, त्यातील सुविधा आदींबाबतची आकडेवारी देण्यात आली आहे. यात देशातील बहुतांश शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र आणि कार्यक्षम स्वच्छतागृहे नसल्याचेही दिसून आले आहे. शाळेत मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड्स पुरवणे ही काळाची गरज आहेच, परंतु त्याआधी मासिक पाळीसंदर्भात आपल्या समाजाच्या मनातील विटाळदेखील संपणे गरजेचे आहे.

मध्यंतरी पुरोगामी विचारांचा म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रातील एका आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींना मासिक पाळी शरीरधर्म काळात वृक्षारोपण करण्यापासून रोखले गेले आणि यामागे 'झाडांची वाढ खुंटते' असे अतार्किक कारण देण्यात आले. यावरून स्त्रियांच्या या मासिक शरीरधर्मास 'विटाळ' समजण्याइतपत मागासलेपण आपल्या समाजातच नव्हे तर शैक्षणिक संस्थांतदेखील आजही कायम आहे. जरी कायद्याने 'विटाळ' संपला असला तरी तो मनाने संपणे गरजेचे आहे.

- बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

सेतू

अमेरिकन नागरिक शिट्ट्या वाजवत रस्त्यावर येतात, तेव्हा...

'आईस'च्या भीतीने घरात कोंडल्या गेलेल्या स्थलांतरितांना मदत करण्यासाठी अमेरिकन नागरिकांनी चळवळ सुरू केली आहे.

प्राजक्ता पाडगांवकर
भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिक, अटलांटा

अमेरिकेत सध्या सगळेच भीषण सुरू असल्यासारखे वाटत असले तरी इथे आनंददायी, आशादायीदेखील काही फुलून येते आहेच. ही गोष्ट आहे मिनेसोटा राज्यातल्या धीरोदात्त नागरिकांची. इथे दोन जुळी शहरं आहेत, सेंट पॉल आणि मिन्निआपोलीस. अनेक महिने इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईस) या शहरात तळ ठोकून बसले आहे. विरोधक सत्तेवर असलेल्या राज्यात जाऊन अराजक, भय, आणि हिंसाचार पसरवणे हा अंतस्थ हेतू, बेकायदा रहिवाशांना शोधून शोधून टिपणे हे मुख्य काम. या देशविरोधी, असंविधानात्मक कृत्याला, मिनेसोटाचे रहिवासी सडेतोड उत्तर देतात. या जन-चळवळीला एक नवा बाज आहे. इथली मंडळी अनोख्या पद्धतीने 'आईस'च्या कारवाईला विरोध करताना दिसतात. इथले जागरूक नागरिक प्रत्येक असंवैधानिक कृतीची नोंद ठेवत आहेत. फोनमधील व्हिडीओ रेकॉर्डिंगमार्फत याबाबतची जनजागृती पसरवत आहेत. 'सिग्नल'सारख्या सामाजिक माध्यमांद्वारे नागरिक संरक्षक गट निर्माण करून, अहोरात्र वस्त्यांमधून गस्त घालत आहेत.

अनेकांनी कर्कश आवाज करणाऱ्या शिट्ट्या सोबत बाळगल्या आहेत. रस्त्याने जाताना जर 'आईस'चे लोक दिसले तर शिट्टी/गाडीचा हॉर्न वाजवून ते सभोवतालच्या नागरिकांना सतर्क करतात. मुलांच्या शाळेच्या बस येण्या-जाण्याच्या मार्गावर उभे राहून मुलांचे रक्षण करतात. एकत्र येऊन अनेक कलाकारांनी 'आईस'विरोधी गाणी, भजने तयार केली

आहेत. लोक रस्त्यांवर ही गाणी गात विरोध दर्शवतात. जिथे 'आईस' अधिकारी हॉटेलवर विश्रांतीसाठी जातात, तिथे जाऊन लोक जोरात ड्रम वाजवतात, फटाके फोडतात. मोर्चे, घोषणा, रोजच अव्याहत सुरू आहेत. यात अहिंसा न सोडता मंडळी स्वतःच्या शेजारी राहणाऱ्या लोकांसाठी रस्त्यावर उतरली आहेत. एका वृद्ध संगोपन संस्थेतील वृद्ध, त्यांचे डॉक्टर, नर्स आणि वकील एकत्रितपणे 'आईस'च्या कार्यालयात धरणे धरून बसली होती.

या शहरांमधल्या शाळा सध्या बंद आहेत, अथवा ऑनलाइन सुरू आहेत. शिक्षक मुलांच्या मनातील अनिश्चितता, भय, यावर काय तोडगा काढता येईल, याचा विचार करत आहेत. 'आईस'चे अधिकारी नागरिकांना काही तास, अथवा दिवस, तुरुंगात डांबून हिवाळ्यात अनवाणी पायाने नेसत्या वस्त्रानिशी रस्त्यावर सोडून देत असल्याचे समजताच, काही वकील आणि सेवाभावी संस्थांनी तुरुंगाबाहेर थांबून लोकांना गरम कपडे, बूट देणे सुरू केले आहे. अनेक छोटे व्यवसाय यात होरपळून निघत आहेत, त्यांना आधार म्हणून शेजारपाजारच्या लोकांनी तिथे आवर्जून काही विकत घेणे सुरू केले आहे. अपुरी कागदपत्रे असलेले / नसलेले स्थलांतरित 'आईस'च्या भीतीने घराबाहेर पडू शकत नाहीत. अशा कुटुंबांसाठी अमेरिकन नागरिक जेवण आणि वाण सामानाची व्यवस्था करत आहेत. इथले आदिवासी, त्यांची पारंपरिक नृत्ये करून विरोध दर्शवत आहेत. हा सगळा विरोध सुरू आहे ते एकमेकांच्या शेजाऱ्यांना सुरक्षित आणि एकीने राहता यावे याकरिता. अशा या अनोख्या नव्या असहकार चळवळीला नाव दिले गेले आहे 'नेबरीझम' अर्थात 'शेजारधर्म'.

उणे २०-३० अंश सेल्सियस तापमानात रस्त्यावर उतरून दंडेलशाहीचा विरोध करत असलेल्या या शहरांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार देण्यात यावा अशी शिफारस 'नेशन' या मासिकाने केली आहे.

praj.padgaonkar@gmail.com

सेतू : जगभरातील मराठी माणसांच्या जगण्यातले रूपरंग शोधणारा हा स्तंभ. तुम्ही स्वतः, तुमचे आप्त परदेशात राहात असाल, तर तुमचे अनुभव जरूर पाठवा. निवडक लेखनाला प्रसिद्धी. **ईमेल करा :** setu@lokmat.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४११०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चीफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.)
'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

...तर ऑनलाइन फसवणुकीतील तुमचेही पैसे परत मिळू शकतात!

जितेंद्र कालेकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : पोलिस अधिकाऱ्याच्या वेशातच व्हिडीओ कॉल करून सायबर ठगांकडून कित्येक तास नजरकैदेत ठेवले जाते. खोटे पोलिस ठाणे, सीबीआय किंवा न्यायालयाचा भाग दाखवून अटकेची भीती दाखवीत कुटुंबासह इतरांशी संपर्क तोडण्यास भाग पाडला जातो. तुमच्याही बाबतीत सायबर फसवणुकीचा प्रकार घडू शकतो किंवा झाला असल्यास वेळीच सावध व्हा. 'गोल्डन अवर'मध्ये तक्रार केल्यानंतर पैसे वाचू शकतात, असा सल्ला ठाणे गुन्हे शाखेच्या सायबर विभागाने दिला आहे.

काय आहे 'गोल्डन अवर' ?

फसवणूक झाल्यापासूनची पहिली ६० मिनिटे महत्त्वाची असतात. पैसे सायबर गुन्हेगारांच्या खात्यात जाण्यापूर्वी किंवा एटीएममधून रक्कम काढण्यापूर्वी गोठविणे किंवा जितकी रक्कम गेली तितकी काढून घेणे (लीन) आवश्यक असते. याच काळा तक्रार केली तर बँक आणि पोलिस यांच्या समन्वयातून मोठी रक्कम परत मिळण्याची शक्यता अधिक असते.

पीडिताने काय करावे?

घाबरविणारा व्हिडीओ कॉल त्वरित बंद करा. १९३० या राष्ट्रीय सायबर क्राइम हेल्पलाइनवर संपर्क करा. सायबर क्राइम डॉट जीओव्ही डॉट इनवर सविस्तर तक्रार करून संबंधित बँकेच्या हेल्पडेस्कलाही त्वरित माहिती दिल्यास फसवणुकीतील रक्कम मिळण्यास मदत होते.

...अशी घ्या खबरदारी

कोणत्याही सरकारी यंत्रणा या व्हिडीओ कॉलवर अटक करीत नाही. पैशांच्या देवाणघेवाणीतून फोनवर पोलिस तपास थांबवत नाहीत. अनोळखी व्यक्तींना बँकेचे तपशील किंवा आधारकार्ड देऊ नका, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र कधी साधणार 'गोल्डन अवर'?

सायबर गुन्ह्यांत ५ वर्षांत ९ हजार कोटी गमावले... वाचवले हजार कोटी; जागरूकता महत्त्वाची

क्राइम वॉच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सायबर आर्थिक फसवणूक प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करून पैसे परत मिळवण्यात उत्तर प्रदेशने मोठी झेप घेत देशात तिसरे स्थान मिळवले, तर महाराष्ट्र २२व्या क्रमांकावर असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या 'नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल'च्या जानेवारी २०२६ मधील आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. सायबर गुन्ह्यातील आर्थिक लूट रोखायची असेल तर 'गोल्डन अवर' महत्त्वाचा असतो. महाराष्ट्राला हा 'गोल्डन अवर' साधायचा असेल तर नागरिकांचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे.

गेल्या पाच वर्षांत राज्यात नऊ हजार कोटींहून अधिक रक्कम सायबर ठगांनी लंपास केली. त्यापैकी जवळपास एक हजार कोटी रुपये वाचविण्यात सायबर सेलला यश आले.

उत्तर प्रदेश तिसऱ्या स्थानावर कसे?

राज्यात जानेवारी २०२६ मध्ये सायबर फसवणुत १३८ कोटी सायबर ठगांनी लाटली. त्यापैकी ४८ कोटी गोठवले. यामुळे वसुली दर ३५.१३ टक्के झाला आणि ते देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आले.

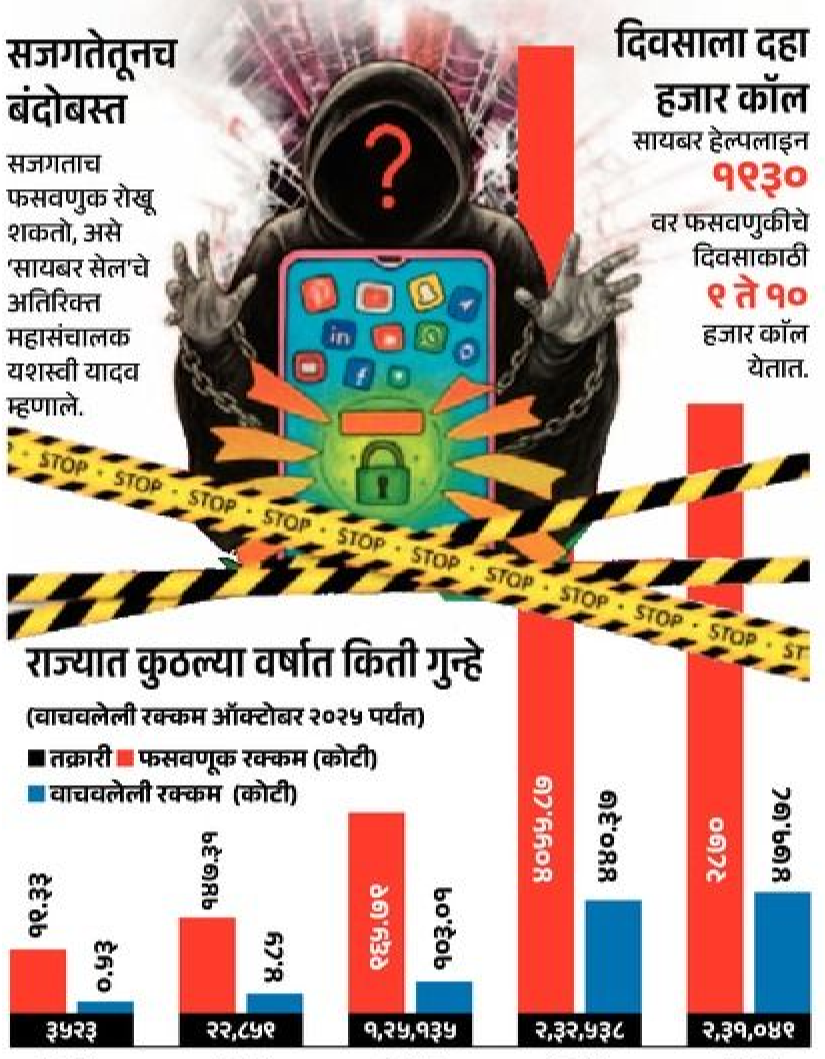

सजगतेतूनच बंदोबस्त

सजगताच फसवणुक रोखू शकतो, असे 'सायबर सेल'चे अतिरिक्त महासंचालक यशस्वी यादव म्हणाले.

दिवसाला दहा हजार कॉल

सायबर हेल्पलाइन **१९३०** वर फसवणुकीचे दिवसाकाठी **९ ते १०** हजार कॉल येतात.

महाराष्ट्रातून सर्वाधिक सायबर फसवणूक

महाराष्ट्रातील नागरिकांची गेल्या वर्षभरात ३,२०३ कोटी रुपयांची लूट.

कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर...तेथून २,४१३ कोटी रुपये लंपास.

तमिळनाडूमधून सायबर ठगांनी १,८९७ कोटी रुपये लांबविले.

उत्तर प्रदेशात १,४४३ कोटी रुपये विविध फसवणूक प्रकरणांतून लांबवण्यात आले.

तेलंगणामधील नागरिकांची १,३७२ कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली.

या पाच राज्यांमधील एकूण नुकसान देशातील एकूण फसवणुकीच्या रकमेपैकी निम्म्याहून जास्त आहे.

धागेदोरे परदेशात

'सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम'च्या आकडेवारीनुसार २०२५ मध्ये सायबर फसवणुकीच्या २१ कोटी तक्रारी आल्या. त्यापैकी ४५ टक्के प्रकरणांचे धागेदोरे कंबोडिया, म्यानमार आणि लाओस आदी आग्नेय आशियाई देशांमध्ये सापडतात.

जनजागृती ठरतेय प्रभावहीन?

मोबाइल कॉलर ट्यूनपासून जनजागृतीपर जाहिराती केल्या जात आहेत. बँका ग्राहकांना एसएमएस पाठवतात. अनेक हेल्पलाइनही आहेत. तरीही डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, मोठ्या हुद्द्यावरील शासकीय अधिकारी आदी शिक्षित, उच्च शिक्षितांनाही सायबर भामटे लक्ष्य करतात. त्यामुळे ही जनजागृती आणि उपाय प्रभावहीन ठरत आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होतो. प्रत्येकापर्यंत किंवा प्रत्येक वयोगटातील व्यक्तीपर्यंत पोचतोय की नाही? याची खातरजमा करणे किंवा आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पोलिसांच्या प्रयत्नांनंतरही नागरिकांच्या ज्ञानात पडेना भर

सूर्यकांत वाघमारे
लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई : गतवर्षात नवी मुंबईतून सायबर गुन्ह्यात फसले गेलेल्या १६ हजार ३६४ जणांचे १३६ कोटी ४३ लाख रुपये सायबर गुन्हेगारांनी हडपले आहेत. त्यापैकी बहुतांश गुन्ह्यांची तक्रार ही गोल्डन अवर निघून गेल्यानंतरच दाखल झाल्याने गोठवलेल्या बँक खात्यात अवघे ७ कोटी ९३ लाख रुपये मिळून आले आहेत. फसवणूक झाल्याची जाणीव नागरिकांना होईपर्यंत गुन्हेगारांनी एका खात्यातली रक्कम वेगवेगळ्या खात्यांत पाठवून डाव साधलेला असतो.

सायबर गुन्ह्यांमध्ये धनदांडग्यांसोबतच सर्वसामान्यांचीदेखील बँक खाती रिकामी होत आहेत. त्यातून अनेक जण आयुष्यभराची जमापुंजी गमाव सोशल मीडियावर ट्रेडिंगमधून नफ्याच्या प्रलोभनाचे जाळे पसरविले जात आहे. मात्र, फसल्या गेलेल्या व्यक्तीला त्याची जाणीव होऊन पोलिसांकडे तक्रार करेपर्यंत काही दिवस ते महिने उलटलेले असतात. त्यामुळे गोल्डन अवर निसटून गेल्यानंतर गोठवलेल्या बँक खात्यात पोलिसांच्या हाती फार काही लागत नाही. त्यामुळे गोल्डन अव्हरमध्ये तक्रार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

२०२५	
दाखल गुन्हे ३६२	उघड गुन्हे १३६
रोकड गेली	१२४ कोटी २२ लाख
फ्रिज केली	७ कोटी ९३ लाख
परत केले	०३ कोटी ७४ लाख

२०२४	
दाखल गुन्हे ४३६	उघड गुन्हे ७९
रोकड गेली	५० कोटी ९७ लाख
फ्रिज केले	४१ कोटी ३२ लाख
परत केले	१० कोटी २२ लाख

१ सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांनी ८८२८११२११२ ही हेल्पलाइन सुरू केली आहे. त्यावर गतवर्षात सायबर गुन्ह्यांसंबंधी २,७०६ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी अनेकांना वेळीच सतर्क करून फसवणूक टाळली आहे. आठवड्यापूर्वीच वाशी पोलिसांनी एका व्यक्तीच्या खात्यातले १५ लाख रुपये एपीके फाईलद्वारे हडपण्याचा सायबर गुन्हेगाराचा डाव हाणून पाडला आहे.

२ जनजागृतीसाठी नवी मुंबई पोलिसांनी व्हॉट्सॲप चॅनेल बनविले आहे. दोन वर्षांत अवघ्या ७६ हजार व्यक्ती जोडल्या गेल्या आहेत. यावरून नागरिकांचा अत्यल्प प्रतिसाद दिसून येत आहे.

न्यायालयाचीही तत्परता महत्त्वाची

पोलिसांनी सायबर गुन्ह्यात गोठविलेले बँक खाते राज्यात, देशात इतरही गुन्ह्यात वापरले गेलेले असते. त्यामुळे या खात्यातली रक्कम तक्रारदाराला मिळावी यासाठी संबंधित न्यायालयात पोलिस धाव घेतात. त्यावर जे न्यायालय तातडीने निर्णय देईल त्या तक्रारदाराला ती रक्कम मिळते. यामुळे इतर ठिकाणच्या तक्रारदारांच्या पदरी निराशाच पडते.

गोठवलेले पैसे परत मिळविण्यासाठी दुप्पट खर्च... बँक, कोर्ट आणि पोलिसचक्रात अडकल्याने दमछाक

मनीषा म्हात्रे
लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : फसवणूक झाली, पैसे गोठवले, आरोपी पकडला, तरीही रक्कम खात्यात परत मिळविण्यासाठी सात ते आठ महिने होऊनही पोलिस ठाणे, कोर्ट बँकेच्या पायऱ्या झिजवण्याची वेळ अंधेरीतील रिअल इस्टेट ब्रोकर यमन सुरेश चटवाल यांच्यावर आली. गमावलेल्या रकमेपेक्षा ती परत मिळविण्यासाठी त्यांचा दुप्पट खर्च झाल्याने न्याय नेमका कुणाकडे मागायचा? असा संतप्त सवाल ते उपस्थित करत आहे.

३० जानेवारी २०२५ रोजी यमन यांनी इन्स्टाग्रामवर पाहिलेल्या व्हिलाबाबत १८ जणांसाठी बुकिंग करण्यासाठी ४३,५०० रुपये ॲक्सिस बँक बँकेतील खात्यावर पाठविले. काही दिवसांनी शंका आल्यावर परतावा मागितला, पण

गुन्हेगाराने संपर्क तोडला. तात्काळ १९३० हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवली. महिनाभराने गुन्हा नोंद झाला, पण वास्तविक संघर्ष नंतर सुरू झाला. त्याच दिवशी त्यांच्याप्रमाणे आणखीन एकाची फसवणूक झाली. ओशिवरा पोलिसांनी तांत्रिक तपास करून मार्चमध्ये आकाश जाधवानीला अटक केली. ४२,५०० रुपये गोठवले. गोठवलेल्या रक्कमेसाठी पोलिसांनी कोर्ट ऑर्डर आणण्यास सांगितले. तीन महिन्यांच्या चकरांनंतर ऑर्डर मिळाली, वकिलासाठी ३० हजार रुपये खर्च झाले. पण प्रवास, पोलिस ठाण्यात थांबणे, कोर्टात तासन्तास वेळ व मानसिक ताण हा स्वतंत्र होता.

पैसे सुरक्षित असल्याचा आनंद ठरला क्षणिक

१ पोलिसांनी बँकेला कोर्ट ऑर्डर पाठवून पैसे खात्यात ट्रान्सफर करण्यास सांगितले. मात्र बँकेने या खात्यात अनेक तक्रारी आल्याचे कारण पुढे करत अंतर्गत चौकशीचा हवाला दिला. कोर्ट ऑर्डर नंतर सात ते आठ महिने उलटूनही रक्कम जमा झाली नाही. अशाप्रकारे अनेकांना या समस्येला तोंड द्यावे लागत असल्याने काहींनी आशा सोडल्या. तर अनेकजण आजही पैशांसाठी पाठपुरावा करत आहेत.

२ पैसे परत मिळवण्यासाठी 'गोल्डन अवर' महत्त्वाचा असतो त्याप्रमाणे गोठवलेले पैसेही खात्यात तात्काळ परत येण्यासाठीही नियम हवेत. नाहीतर हादेखील वेगळ्या पातळीवरचा एक स्कॅमच ठरेल, असे चटवाल यांनी सांगितले.

प्राध्यापक भरतीच्या निकषांमध्ये पुन्हा बदल

आता गुणांकनासाठी राबविणार ६०-२०-२० चा नवा पॅटर्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीच्या निकषांमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने चार महिन्यांतच पुन्हा बदल केला आहे. नव्या निकषांनुसार उमेदवारांच्या शैक्षणिक व संशोधन गुणवत्तेला ६० गुण, अध्यापन कौशल्य मूल्यमापनाला २० टक्के गुण आणि मुलाखतीसाठी २० टक्के गुण दिले जाणार आहेत. त्याचबरोबर उमेदवाराच्या शैक्षणिक आणि संशोधन कामगिरीचे गुणांकन करताना त्याने विविध पदव्या घेतलेल्या शिक्षण संस्थांचे एनआयआरएफ आणि क्यूएस रँकिंगचाही विचार केला जाणार आहे.

यापूर्वी सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीमध्ये शैक्षणिक कामगिरीला ७५ टक्के गुण, तर मुलाखतीसाठी २५ टक्के गुण देण्याचा निर्णय ६ ऑक्टोबर २०२५ ला राज्य सरकारने घेतला होता. निवड प्रक्रियेत पीएच.डी. आणि एम.फिल. केलेल्या उमेदवारांसाठी १७ गुण असतील. तर 'नेट', 'सेट' केलेल्या उमेदवारांना केवळ पाच गुण दिले जाणार आहेत. त्यातून पीएच.डी.धारकांना अधिक संधी असेल. तसेच नामांकित शिक्षणसंस्थांतील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळेल.

मुलाखतीचे होणार चित्रीकरण

मुलाखतीचे गुणांकन करताना ऑडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक केले आहे. यातून पारदर्शकता वाढेल. तसेच यापुढे तासिका, कंत्राटी व एडहॉक तत्त्वावर काम करणाऱ्या उमेदवारांचा ९ महिन्यांचा कार्यकाळ ग्राह्य धरला जाईल. हा निर्णय गुणवत्ता वाढवणारा आहे. मात्र, कमी रँकिंग असलेल्या विद्यापीठातून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांचे गुण हुशार असूनही विद्यापीठाच्या रँकिंगमुळे कमी होऊ शकतात. तसेच प्राध्यापक भरतीला विलंब झाला आहे. आता तरी निवड प्रक्रिया सुरू होऊन उमेदवारांना रुजू करून घ्यायला हवे. त्यासाठी शंभर दिवसांचा कालबद्ध कार्यक्रम देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रीया ऑल इंडिया नेट सेट टिचर्स ऑर्गनायझेशनचे संयोजक डॉ. कुशल मुडे यांनी दिली.

लव्ह ट्रँगलमधूनच 'त्या' तरुणीची गोळी झाडून हत्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : प्रेमात अडसर ठरत असतल्याच्या रागातून तब्बसूम मोहम्मद शेख (२५) हिने शिफा शेखवर गोळी झाडून हत्या केली. त्यानंतर प्रियकर आणि भावाच्या मदतीने तिच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे गोवंडी गोळीबार प्रकरणाच्या तपासात समोर आले. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी तब्बसूमसह प्रियकर नदीम ऊर्फ रिजवान शेख (२७), भाऊ साजीद मोहम्मद शेख (२१) आणि कलाम चौधरी यांना अटक केली आहे.

तब्बसूमचे नदीमसोबत ५ ते ७ वर्षांपासून वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. नदीम हा अभिलेखावरील आरोपी आहे. तो तब्बसूमच्या घरीच राहायचा. ही बाब समजताच तब्बसूमने तिचे घर गाठून नदीमपासून लांब राहा, नाही तर परिणाम वाईट होतील अशी धमकी दिली. कुटुंबीयांनी याबाबत समजताच ३ महिन्यांपूर्वी शिफाला गावी पाठवले. काही दिवसांनी ती पुन्हा गोवंडीतील कमलारामणनगर येथे राहण्यास आली. घटनेच्या दिवशी दुपारी नदीम तब्बस्सूमच्या घरी असल्याचे समजताच तिने घर गाठले. तेथे तब्बस्सूम व शिफामध्ये भांडण झाले. याच रागात तब्बस्सूमने नदीमच्या देशी कट्ट्याने शिफावर गोळी झाडली. दरम्यान चारही जणांना १८ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी दिली.

मुंबई विमानतळावरील सीमा शुल्क विभागाने २ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या गांजाच्या तस्करीचा पर्दाफाश केला असून या प्रकरणी दहिसरच्या एका ४६ वर्षीय व्यक्तीला अटक केली आहे. एन. धाकण असे त्याचे नाव आहे. तो बँकॉकहून आला होता. -८

रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरण : मुंबईत दहशत माजवण्याचा कट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : हिंदी चित्रपट दिग्दर्शक रोहित

शेट्टी यांच्या जुहू येथील निवासस्थानी करण्यात आलेल्या गोळीबारातून शहरात दहशत माजवण्याचा आरोपींचा हेतू होता, असा दावा पोलिसांनी बुधवारी विशेष मकोका न्यायालयात केला. या प्रकरणात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्यात आला असून, विशेष न्यायालयाने पाचही आरोपींना १७ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. हा प्रकार म्हणजे 'हिमनगाचे टोक' असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

जुहू येथील नऊ मजली इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर १ फेब्रुवारीला मध्यरात्री १२:४५ च्या सुमारास आरोपींनी पाच गोळ्या झाडल्या होत्या. या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे 'अँटी-एक्स्टॉर्शन सेल' करत आहे. काही आरोपी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आधीपासून सामील आहेत. त्यामुळे गुन्हे शाखेने मकोका लागू केला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. आतापर्यंत आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी, स्वप्निल साकट आणि आसाराम फासले यांना अटक करण्यात आली आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित शुभम लोणकर हा या प्रकरणातील फरार आरोपी आहे.

पोलिसांचा आरोप...

आरोपींच्या पोलिस कोठडीची मुदत बुधवारी संपल्यानंतर त्यांना विशेष मकोका न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांनी आणखी १५ दिवसांच्या कोठडीची मागणी न्यायालयाकडे केली. आरोपींचे संबंध फरार शुभम लोणकर, तसेच त्याचा भाऊ प्रवीण लोणकर यांच्याशी आहेत. प्रवीण लोणकर सध्या बाबा सिद्दीकी हत्याप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत आहे. जप्त करण्यात आलेल्या शस्त्रांपैकी एक शस्त्र प्रवीण लोणकरने पुरवल्याचा आरोप पोलिसांनी केला.

आरोपींचा युक्तिवाद

बचाव पक्षाचे वकील सचिन झाल्टे पाटील आणि अजिंक्य मिरगळ यांनी कोठडीवाढीला विरोध केला. मकोकामुळे पोलिसांना कोठडीचा अधिकार मिळत नाही, तसेच लोणकर दीड वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत असल्याने त्याने शस्त्र पुरवणे शक्य नाही, असा युक्तिवाद केला.

हे हिमनगाचे टोक आहे...

हे प्रकरण वरवर छोटे वाटत असले तरी ते 'हिमनगाचे टोक' आहे. संघटित गुन्हेगारी टोळीचा कथित सहभाग लक्षात घेता सखोल तपास हवा. सत्य समोर आणण्यासाठी तपास यंत्रणेला वेळ देणे गरजेचे असे न्यायालयाने नमूद केले.

रिक्षाचालकाच्या डोळ्यात माती फेकून मैत्रिणीवरील अत्याचार रोखला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

बदलापूर : बदलापुरात क्लासला जाणाऱ्या १० वर्षीय मुलीचा भररस्त्यात विनयभंग केल्याने रिक्षाचालकाला बदलापूर पूर्व पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. विशेष म्हणजे ज्यादिवशी विनयभंगाची घटना घडली, त्यादिवशी पीडित मुलीसोबत असलेल्या मैत्रिणीने तिच्यावरील अत्याचार रोखण्यास मदत केली. मैत्रीण अडचणीत असल्याचे लक्षात येताच तिने रिक्षाचालकाच्या डोळ्यात माती फेकून मैत्रिणीला सुरक्षितपणे बाहेर काढले. तिच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला.

६ फेब्रुवारीला पीडित मुलगी क्लासला जात असताना रिक्षाचालकाने तिला अडवून विनयभंग केला होता. याप्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. तपास करताना अनेक सीसीटीव्ही फुटेज तपासत पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली. हा रिक्षाचालक अंबरनाथमध्ये राहातो पोलिसांनी त्याला काही तासात बेड्या ठोकल्या. न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडीत केली आहे.

> घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर, आरोपीला शोधणे अवघड जात होते. मात्र, तांत्रिक तपास करून त्या संबंधित रिक्षा चालकाला अंबरनाथमधून अटक करण्यात यश आले.
>
> **राजेश गज्जल,** पोलिस निरीक्षक (गुन्हे)

तिसऱ्यांदा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

गेल्या वर्षी बदलापूरच्या एका नामांकित शाळेमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराची घटना घडली होती. त्यानंतर बदलापुरातील प्री-प्रायमरी शाळेत शिकणाऱ्या एका चिमुकलीवर स्कूल व्हॅन चालकाने अत्याचार केल्याची घटना घडली. त्या प्रकरणातही गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आली.

भारतीय रिझर्व्ह बँक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in
मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग
भारतीय रिझर्व्ह बँक ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी– ओपीडी साठी सेवा प्रदाता म्हणून सहभागासाठी प्रतिष्ठित विक्रेत्यांकडून MSTC (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/) द्वारे ई–निविदा आमंत्रित करण्यात येत आहे. तपशिलांसाठी कृपया www.rbi.org.in वरील निविदा विभागाला भेट द्या.
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
मुंबई मा.सं.प्र.वि, भारतीय रिझर्व्ह बँक

ICICI Bank
नोंदणीकृत ऑफिस: आयसीआयसीआय बँक टॉवर, चकली सर्कल जवळ, जुना पाद्रा रोड, बरोडा - ३९०००७, गुजरात
कॉर्पोरेट ऑफिस: आयसीआयसीआय बँक टॉवर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - ४०००५१, महाराष्ट्र
शाखा पुनर्स्थापना करण्याबाबतची सूचना
आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड, मुंबई-तैकालवाडी शाखेच्या वतीने
प्रिय ग्राहकांनो,
आम्ही तुम्हाला कळवू इच्छितो की 15 एप्रिल, 2026 पासून, आम्ही अधिक सोयीस्कर ठिकाणी स्थलांतर करत आहोत. नवीन ठिकाणाचा पत्ता खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहे.
नवीन ठिकाण: आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड, सर्वे नंबर 1435, तळमजला, सेलेसशिअल बिल्डिंग, गोखले रोड, शिवसेना भवनाजवळ, दादर (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र - 400028.
तुमच्या खाते क्रमांकामध्ये किंवा तुम्हाला जारी केलेल्या सुरक्षा वस्तूंमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.
आमच्या मुंबई-तैकालवाडी शाखेत लॉकर धारण करणाऱ्या ग्राहकांसाठी खालील मार्गदर्शक तत्त्वे लागू आहेत.
आमच्या शाखेचे स्थलांतर करण्याच्या प्रक्रियेत, आम्ही वर नमूद केल्याप्रमाणे सुरक्षित ठेव लॉकर देखील पत्त्यावर स्थानांतरीत करणार आहोत. लॉकर युनिट्सचे स्थलांतर 13 एप्रिल, 2026 रोजी सुरू होईल आणि ते 15 एप्रिल, 2026 रोजी नवीन ठिकाणी स्थापित केले जातील.
जर तुम्हाला तुमचे लॉकर नवीन ठिकाणी चालवणे सुरू ठेवायचे असेल तर आम्ही तुम्हाला तुमचे लॉकर रिकामे करण्याची आणि त्यातील सामग्रीचा ताबा घेण्याची विनंती करतो. कृपया 13 एप्रिल, 2026 पूर्वी असे करा. तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार, 15 एप्रिल, 2026 नंतर बँकिंग तासांदरम्यान कधीही, नवीन ठिकाणी ठेवू शकता.
जर तुम्ही तुमचे लॉकर रिकामे करू शकत नसाल, तर आम्हाला लॉकर युनिट्स, त्यातील सामग्रीसह हलवावे लागतील. लॉकर युनिट्स योग्य देखरेखीखाली हलवले जातील आणि त्यांना काळजीपूर्वक हाताळण्यासाठी प्रत्येक खबरदारी घेतली जाईल.
तुम्हाला सर्वोत्कृष्ट सेवांची हमी नेहमी देत आहोत.
विश्वासू,
शाखा प्रबंधक, मुंबई-तैकालवाडी शाखा

सिडको शहरांचे शिल्पकार
ई-निविदा बोली आमंत्रण सूचना
नवी मुंबई परिसरासाठी, भरती (Tidal), तटीय भूरुपशास्त्र (Coastal Geomorphology) माहिती व इतर CRZ संबंधित सहाय्यक माहितींसह, CRZ अधिसूचना २०१९ व त्यातील सुधारणा यानुसार तसेच CZMP २०१९ नुसार CZMP च्या पुनर्रचनेकरिता अभ्यास व समन्वयासाठी सल्लागाराची नियुक्ती .
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ ई-निविदा प्रक्रियेअंतर्गत पर्यावरण सल्लागारांकडून ऑनलाईन निविदा/बोली आमंत्रित करीत आहे. " नवी मुंबई परिसरासाठी, भरती (Tidal), तटीय भूरुपशास्त्र (Coastal Geomorphology) माहिती व इतर CRZ संबंधित सहायक माहितींसह, CRZ अधिसूचना २०१९ व त्यातील सुधारणा यानुसार तसेच CZMP २०१९ नुसार CZMP च्या पुनर्रचनेकरिता अभ्यास व समन्वयासाठी सल्लागाराची नियुक्ती." या कामासाठी पात्र सल्लागार या बोली प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. तपशील पुढीलप्रमाणे:
१. कामाचे नाव: नवी मुंबई परिसरासाठी, भरती (Tidal), तटीय भूरुपशास्त्र (Coastal Geomorphology) माहिती व इतर CRZ संबंधित सहायक माहितींसह, CRZ अधिसूचना २०१९ व त्यातील सुधारणा यानुसार तसेच CZMP २०१९ नुसार CZMP च्या पुनर्रचनेकरिता अभ्यास व समन्वयासाठी सल्लागाराची नियुक्ती . २. सी.ए. क्रमांक:03/CIDCO/GM(Env.&Forest)/2025-26. पात्रता निकष: (अ) तांत्रिक क्षमता:अ) अर्जदाराने प्रस्ताव सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपूर्वीच्या (PDD) मागील १० वर्षांमध्ये CRZ संबंधित कामे पूर्ण केलेली असावीत.ब) सल्लागाराकडे किमान ३० पूर्ण केलेले CRZ क्लिअरन्स प्रकल्प MCZMA किंवा MoEF&CC कडून मंजूर असावेत. त्यापैकी किमान ०५ प्रकल्प MCZMA तसेच MoEF&CC, नवी दिल्ली येथून CRZ क्लिअरन्स प्राप्त असलेले असावेत. सर्व प्रकल्प मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्यांमध्ये (महाराष्ट्र राज्य) पूर्ण झालेले असावेत.क) सल्लागाराचे मुंबई, ठाणे किंवा नवी मुंबई परिसरात कायमस्वरुपी कार्यालय असणे आवश्यक आहे. आर्थिक क्षमता: अर्जदाराची प्रस्ताव सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपूर्वीच्या सलग ०३ आर्थिक वर्षांमध्ये, सल्लागार सेवांमधून व्यावसायिक शुल्काद्वारे मिळालेली वार्षिक सरासरी उलाढाल किमान रु. ०२ कोटी असावी. फक्त तांत्रिकदृष्ट्या पात्र (किमान ६० गुण प्राप्त) सल्लागाराचीच आर्थिक बोली उघडण्यात येईल. ४. काम पूर्ण करण्याचा कालावधी: १२ महिने (मान्सून कालावधीसह) ५. निवड पद्धत: गुणवत्ता व खर्चाधारित निवड पद्धत (QCBS) - ७०:३० (७०% तांत्रिक व ३०% आर्थिक) ६. अनामत रक्कम :रु. १,००,०००/- (फक्त एक लाख रुपये)(इसारा अनामत रकमेसाठी कोणतीही सूट दिली जाणार नाही) ७. निविदा प्रक्रिया शुल्क:रु.१,१८०/- (१८% जीएसटी सह) - (परत न मिळणारे)
बोली कागदपत्रे व बोली उपक्रम १२/०२/२०२६ रोजी दुपारी १५:०१ वाजल्यापासून https://mahatenders.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील.
महाव्यवस्थापक
(पर्यावरण व वन)
CIN - U99999 MH 1970 SGC-014574
www.cidco.maharashtra.gov.in
सिडको/जनसंपर्क/४१७/२०२५-२६

'सीमेंट की दीवार' पर प्रतिक्रियाएं

पारदर्शिता व जवाबदेही में ही समाधान की राह

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पायों पर अवस्थित लोकतंत्र के मूल स्वरूप में कालांतर में बदलाव आने और इस कारण इसके जनता से दूर चले जाने का जिक्र करते पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के अग्रलेख 'सीमेंट की दीवार' को प्रबुद्ध पाठकों ने आज के दौर की सटीक तस्वीर बताया है। पाठकों का कहना है कि जनता के हित में होने वाले फैसलों का असली लाभ उसके हकदारों तक पहुंच ही नहीं पाता। इसकी बड़ी वजह जवाबदेही का न होना है। बदलाव के लिए अच्छे लोगों को आगे आना होगा। **पाठकों की प्रतिक्रियाएं विस्तार से-**

अग्रलेख लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। यह सही कहा गया है कि लोकतंत्र का मूल स्वरूप, जो जनता की सहभागिता और हितों पर आधारित होना चाहिए था, वह धीरे-धीरे अपने उद्देश्य से भटक गया है। सत्ता, स्वार्थ और नीतियों की जड़ता ने व्यवस्था को ऐसी सीमेंट की दीवार बना दिया है, जिसमें आम नागरिक की आवाज दबकर रह जाती है। शिक्षा और प्रशासन भी जनहित के बजाय सत्ता-हित की ओर झुकते दिखते हैं। **-अवधेश सिंह तोमर**, अधिवक्ता हाईकोर्ट, ग्वालियर

बदलाव के लिए अच्छे लोगों को आगे आना होगा। जनता ही यह तय करे कि उनके प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में आंकठ डूबे न हो। आज के दौर में तो समाज के हर वर्ग में बुराइयों की भरमार है। शिक्षक, सरकार व मीडिया सब इससे अछूते नहीं। अगर हम राष्ट्रधर्म को सर्वोपरि समझें तो हमें स्वार्थ से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के भाव को रखकर चौकन्ना होना पड़ेगा तब लाकर ही हम अग्रलेख में बताई गई इस 'सीमेंट की दीवार' को तोड़ पाएंगे। **-राकेश कुमार मिश्रा**, अनंतपुरा, कोटा

अग्रलेख में यह वाजिब सवाल उठाया गया है कि लोकतंत्र के तीन पाये अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से वहन नहीं कर रहे हैं। उल्टे एक-दूसरे के काम में दखल कर रहे हैं। विधायिका, जिसका काम नीति निर्धारित करना है वहां सत्ता में बैठे लोग पांच साल अपनी कुर्सी बचाने व सरकारी तंत्र का लाभ लेने में मशगूल हो जाते हैं। कार्यपालिका में तो भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि कहीं कोई जवाबदेही तय नहीं। न्यायपालिका में भी कामकाज आज भी अंग्रेजी शासन पद्धति पर चल रहा है। यहां भी कमियों की भरमार है। **-आदर्श अग्रवाल**, जयपुर

अग्रलेख 'सीमेंट की दीवार'सच्चाई को उजागर करता है। देश में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों विधायिका के अधीन हो चुके हैं। विधायिका, कार्यपालिका पर दबाव बनाकर उनसे गलत काम करवाती है फिर गलत कामों पर कार्यपालिका को ब्लैकमेल किया जाता है। प्रिंट मीडिया फिर भी जागरूक है परन्तु कुछ सीमित और संतुलित तरीके से काम कर रहा है। सीमेंट की दीवार के दुष्परिणाम के खतरे खूब हैं। **-प्रकाश मदनानी**, अधिवक्ता, इंदौर

दुर्भाग्य से लोकतंत्र के तीनों पाये और मीडिया तंत्र की नैतिकता टूटती जा रही है। चारित्रिक संकट पैदा हो गया है। राजनीति तो दिन-ब-दिन दुर्बलता ही देती जा रही है। जनता के हाथ विष का प्याला देकर स्नेहिल अभिवादन का दिखावा मात्र बचा रह गया है। आशा की कोई किरण कहीं दिखाई नहीं दे रही। **-कुलदीप पारीक**, नागौर

स्थानीय वार्ड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जिसको भी जनता अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रही है, वह सेवक से राजा बनकर उन पर ही जुल्म ढाने लगता है। विधायक, सांसद और मंत्री सब पूरे कानूनों को सेट करने में लग जाते हैं। सत्ता का सुख जिसके भी हाथ आया है, वह सेवा छोड़कर मेवा खाने में लग जाता है। यही देश की राजनीति का असली चेहरा बन चुका है। **-मुकेश चौधरी**, अधिवक्ता, जबलपुर

जनता का भरोसा टूटना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। सरकार, नेता और अधिकारी जनता से दूर होते दिख रहे हैं। जनता के नाम पर फैसले तो होते हैं लेकिन फायदा कुछ लोगों को ही मिलता है। सरकार और प्रशासन में पारदर्शिता कम होती दिख रही है। **-पं.निलेश शास्त्री**, आगरा रोड, जयपुर

वास्तविकता यह है कि जनता की समस्याओं पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा। नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से हालात बिगड़ रहे हैं। शिक्षा-स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत जरूरतों की अनदेखी की जा रही है। अब उम्मीद है जब जनता जागरूक होकर सही लोगों को चुनें। **-राधेश्याम शर्मा**, जगतपुरा, जयपुर

यह सही है कि देश में लोकतंत्र जनता की बदौलत है, लेकिन यह जनता का नहीं है। कतिपय राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र को खानदान की विरासत बनाकर इसके स्वरूप को बदल दिया है। ऐसे दल जहां भी सत्ता में हैं, वहां सामंतवादी सोच के उदाहरण अक्सर देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। **-बलदेव सिंह बराड़**, श्रीगंगानगर

संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों का जो आचरण देखने को मिल रहा है, उसे देखकर तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति किसी का भी विश्वास डगमगा सकता है। लोग यह भी कहते सुने जा सकते हैं कि इससे अच्छा तो राजे-रजवाड़ों का दौर ही भला था। **-रामावतार हिन्दुस्तानी**, श्रीगंगानगर

जब संस्थाएं जनता से कट जाती हैं, तब लोकतंत्र खोखला हो जाता है। अग्रलेख में शिक्षा, प्रशासन और मीडिया की भूमिका पर उठाए गए प्रश्न बेहद प्रासंगिक हैं। फिर भी समाधान की राह जनता की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही से ही खुलेगी। केवल आलोचना नहीं, सुधार की सामूहिक पहल भी जरूरी है। युवा नेतृत्व भी अनिवार्य है। **-वंदना अवस्थी**, साहित्यकार, सतना

लोकतंत्र के तीन पायों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा चौथे सेतु मीडिया के बीच बढ़ती दूरी तथा जनता से उनके विच्छेदन को अग्रलेख में बखूबी उजागर किया गया है। यह चिंतन का विवश करता है। विशेष रूप से शिक्षा, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और मीडिया की भूमिका पर किया गया विश्लेषण दर्शाता है कि व्यवस्था धीरे-धीरे संवेदनहीन "सीमेंट की दीवार" बनती जा रही है, जिसके उस पार आमजन की आवाज दबकर रह जाती है। **-शैलेन्द्र तिवारी**, रतलाम

जनता का सरकारों और संस्थाओं से भरोसा कम हो रहा है। नीतियां आम व्यक्ति की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रहीं और शिक्षा व्यवस्था युवाओं की उम्मीदें कमजोर कर रही है। **-ब्रजेश तोमर**, साहित्यकार, शिवपुरी

आज के दौर में सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि राजशाही तरीके से चलाई जा रही हैं! यही वजह है कि जनता का सरकारी संस्थाओं से भरोसा उठ रहा है। दुखद है कि पत्रकारिता भी सत्ता को आईना दिखाने वाली अपनी भूमिका के निर्वहन के बजाय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनने की जबर्दस्ती की होड़ में नजर आ रही है। **-अनिल सिंह जाट**, श्योपुर

अग्रलेख जनहित को स्व-हित में परिवर्तन करने वालों को दर्पण दिखाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि यह जनता है, सब जानती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह सत्य है। राजनीतिक पार्टियों के हित साधने का परिणाम है कि जनता के हित कोसों दूर होते जा रहे हैं। **-राजकुमार अग्रवाल**, विदिशा

जनता का भरोसा स्थानीय संस्थाओं से उठ गया है। भ्रष्ट गतिविधियां चल रही हैं। कर्मचारी घूस लेते पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्ट व्यवस्था बदली जानी चाहिए, तभी लोकतंत्र सुरक्षित होगा। **-विजय विश्वकर्मा**, छिंदवाड़ा

शॉप दिलाने के नाम पर 66 लाख की धोखाधड़ी

इंदौर@पत्रिका. चेन्नई एयरपोर्ट के टर्मिनल पर रिटेल शॉप उपलब्ध कराने के नाम पर कंपनी के डायरेक्टर ने लाखों की धोखाधड़ी कर दी। फरियादी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत कर साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके बाद कंपनी डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक 7 फरवरी को फरियादी ने शिकायत की थी। जांच के दौरान आवेदकों ने दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर कथन दिए। इस आधार पर पता चला कि विदवेदा पीआरजी एयरो एंड पोर्ट्स वेंचिस प्रालि, चेन्नई के डायरेक्टर वचिनाथन थंगवेल ने चेन्नई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 और टर्मिनल - 2 पर रिटेल शॉप उपलब्ध कराने की नाम पर आवेदकों से एलओआइ साइन करवाए। उनसे सुरक्षा निधि, अग्रिम भुगतान व अन्य मदों में कुल 66.52 लाख से अधिक रुपए लिए। कंपनी के डायरेक्टर थंगवेल पर केस दर्ज किया है।

राजगढ़ के काले कारोबार की जड़ें गहरीं: 5 करोड़ का केमिकल फेंककर जाने वाली गाड़ी को पुलिस ने किया ट्रेस

एमपी-राजस्थान बॉर्डर से धराए 3 ड्रग पेडलर्स, पार्टनर पर भी केस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

राजगढ़. ड्रग सरगना रघुनंदन पाटीदार की तलाश करती राजगढ़ पुलिस को राजस्थान-एमपी की बॉर्डर पर तीन ड्रग पेडलर्स मिले हैं। इनके पास से कार मिली है। हाल ही में माचलपुर थाने के आलमपुरा के जंगल क्षेत्र से मिले ड्रम इन्हीं लोगों ने फेंके थे। गोघटपुर निवासी रघुनंदन पाटीदार के साथ ही मिलकर अन्य लोग भी काम करते थे। आमलपुरा के मामले में पुलिस ने गोघटपुर के ही एक अन्य किसान पुत्र दीपक गुर्जर को भी आरोपी बनाया है। ड्रग फैक्ट्री मिलने वाले दिन से ही वह फरार है। बताया जाता है कि गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को दीपक ने ही यह केमिकल फेंककर आने के लिए कहा था।

राजगढ़ पुलिस ने केमिकल फेंकने वाले ललित गुर्जर, दिनेश गुर्जर और रामेश्वर तीनों निवासी बरखेड़ा खुर्द (बकानी) को हिरासत में लिया है। इनके पास मिली कार के आधार पर ये ट्रेस हुए हैं। पुलिस हिरासत में तीनों ने स्वीकारा है कि दीपक गुर्जर के कहने पर ही केमिकल फेंकने के लिए गए थे।

बड़े स्तर पर चल रहा नशे का काला कारोबार

जिन युवकों को कार सहित पुलिस ने हिरासत में लिया है वे गोघटपुर से महज 8 किमी दूर राजस्थान बॉर्डर के गांव बरखेड़ा खुर्द (बकानी) के हैं। यानी वे इसी ड्रग फैक्ट्री के लिए काम करते थे। पुलिस ने रघुनंदन के बाद दीपक गुर्जर को प्रमुख पेडलर के तौर पर आलमपुरा में मिले 5 करोड़ के केमिकल मामले में आरोपी बनाया है। माना जा रहा है कि दीपक और रघुनंदन मिलकर ही गोघटपुर में यह कारोबार बड़े स्तर पर कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है लेकिन फरार रघुनंदन अभी भी सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन अब पुलिस उसके बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। राजस्थान पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी है और राजगढ़ पुलिस को मदद कर रही है। साथ ही पकड़े गए पेडलर्स से कड़ी पूछताछ में रघु की अन्य लिंक निकलने का अनुमान है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही वह गिरफ्त में होगा।

आरोपियों ने किया खुलासा... कच्चा माल लाने वाला रूट अलग था और जाने वाला अलग

रघुनंदन पाटीदार का बड़ा नेटवर्क होने का अनुमान है। झालावाड़ पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने एसपी के समक्ष स्पष्ट किया है कि वे रघु को सिर्फ एक प्रकार का केमिकल देते थे। एमडी बनाने के लिए करीब 10 प्रकार के अलग-अलग केमिकल की जरूरत पड़ती है। जयनारायण उर्फ मामू उसे सिर्फ एक ही केमिकल देता था। बाकि के केमिकल वह अन्य जगह से बुलाता था, लेकिन इस सबका खुलासा उसके गिरफ्तार होने के बाद ही हो पाएगा। माना जा रहा है कि कई स्थानीय लोग इसमें जुड़े निकल सकते हैं। रघुनंदन के घर मिली फैक्ट्री के बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि कच्चा माल यहां आता था उसका रूट अलग था। वहीं, जिस रूट से माल सप्लाई किया जाता था वह अलग था। साथ ही यह भी बात तय मानी जा रही है कि इसका नेटवर्क काफी बड़ा था और काफी लोग इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं।

प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक हितग्राही परेशान

पीडीएस का सर्वर धड़ाम

राशन दुकानों पर लटके ताले, प्रदेश की 24 हजार से ज्यादा दुकानों पर व्यवस्था ठप, गरीब परिवारों के सामने संकट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नीमच. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की व्यवस्था पिछले 5 दिनों से तकनीकी खामियों के चलते पूरी तरह बेपटरी हो गई है। सर्वर ठप होने से प्रदेश भर की उचित मूल्य की दुकानों पर लगी पीओएस मशीनें काम नहीं कर रही हैं। इसके चलते गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाला राशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हालात यह है कि नीमच से लेकर भोपाल तक, राशन दुकानों पर सन्नाटा पसरा है या फिर ताले लटके हुए हैं। मजदूर और गरीब तबका रोज दुकान के चक्कर काट रहा है और खाली हाथ लौटने को मजबूर है।

नीमच जिला खाद्य अधिकारी आरएन दिवाकर के अनुसार यह समस्या केवल एक जिले की नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की है। उन्होंने बताया, सर्वर में तकनीकी दिक्कत पूरे प्रदेश में आ रही है। भोपाल स्तर से तकनीकी टीम इसे ठीक करने में जुटी है, लेकिन व्यवस्था कब तक सुचारू होगी, यह अभी निश्चित नहीं है।

कई परिवार सरकारी अनाज पर निर्भर

नीमच जिले की स्थिति गंभीरता को दर्शाती है। फरवरी का आधा समय बीतने को है, लेकिन जिले में अब तक कुल आवंटन का केवल 15.07% राशन ही बंटा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि महीने की शुरुआत में राशन न मिलने से उनके घर का बजट बिगड़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है, जहां कई परिवार पूरी तरह से सरकारी अनाज पर ही निर्भर हैं। लगातार 4-5 दिनों से मशीनें ठप होने से लोगों में भारी आक्रोश है।

एक नजर

- **कुल राशन दुकानें:** मप्र में कुल उचित मूल्य दुकानें 24713 हैं, जहां वितरण प्रभावित है।
- **प्रभावित परिवार:** लगभग 1,31,34,379 राशन कार्ड हैं, जिनमें अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के लाभार्थी शामिल हैं।
- **कुल हितग्राही:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के करीब 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राही (लाभार्थी) इस व्यवस्था से जुड़े हैं।
- **अटका हुआ अनाज:** प्रदेश में हर महीने औसतन 2.5 से 3 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (गेहूं और चावल) का वितरण होता है। सर्वर ठप होने से लाखों टन अनाज गोदामों और दुकानों में ही अटका हुआ है।
- **मिलने वाली सामग्री:** गेहूं, चावल के अलावा अंत्योदय परिवारों को शक्कर और नमक का वितरण भी इसी प्रणाली से होता है, जो अभी रुका हुआ है।

काम छोड़कर लाइन में लगे

राशन दुकान का चक्कर काट रहे मजदूर देवीलाल सेन के अनुसार हम रोज काम छोड़कर राशन लेने आते हैं, दुकानदार कहता है मशीन नहीं चल रही। अगर राशन नहीं मिला तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? बाजार से महंगा आटा खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है।

बालाघाट के वन क्षेत्र में गांव-गांव आंदोलन की तैयारी

जल-जंगल, जमीन बचाने एकजुट हुईं महिलाएं, बॉक्साइट खनन का विरोध

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बालाघाट. वन क्षेत्र में खनन स्वीकृति के विरोध में आदिवासी अंचल की महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। महिलाएं पचामा दादर बॉक्साइट ब्लॉक की स्वीकृति का विरोध कर रही हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि बॉक्साइट खनन परियोजना के लिए तैयार पर्यावरण प्राभाव आकलन रिपोर्ट में वनाधिकार मान्यता कानून 2006 को लागू नहीं होना बताया है। प्रतीत होता हैं कि रिपोर्ट में वास्तविक प्रभाव को छिपाकर भ्रामक जानकारी दी है। महिलाओं का आरोप है कि बगैर ग्राम सभा की सहमति के बॉक्साइड ब्लॉक उत्खनन स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांव वाले अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे।

नहीं ली सहमति

ग्रामसभा की सहमति के बिना वन क्षेत्र में पचामा दादर में खनन की स्वीकृति व जनसुनवाई करने की तिथि निर्धारित की गई है। ऐसा करना वनाधिकार मान्यता कानून 2006 की धारा 4 (5) के अनुसार विधि संगत नहीं है।

आंदोलन की रणनीति

मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व लोक जनसुनवाई के लिए अधिकृत एसडीएम बैहर को आपत्ति लगाई है। 12 को आंदोलन की रणनीति बनाई है। इसमें 70 से अधिक गांवों के आदिवासी समाज के लोग एकत्रित होंगे। विधायक संजय उईके भी इसमें शामिल होंगे।

झोपड़ी में लगी आग, दिव्यांग की मौत

सिंगरौली@पत्रिका. चितरंगी की ग्राम पंचायत रेही में मंगलवार रात आग की चपेट में आने से दिव्यांग की मौत हो गई। जगनारायण कोल (35) को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मंगलवार रात जगनारायण पिता के साथ घर के पास स्थित झोपड़ी में अलाव ताप रहा था। इसी बीच पिता भोजन लेने घर के अंदर गए, तभी जगनारायण को मिर्गी का दौरा पड़ा और सीधे अलाव पर गिर गया। आग ने झोपड़ी को चपेट में ले लिया। झुलसकर जगनारायण की मौत हो गई।

आरटीओ चालान के नाम पर आई 'एपीके' ने खाली कर दिया खाता, ढाई लाख उड़ाए

इंदौर@पत्रिका. आरटीओ चालान के नाम पर भेजी एपीके फाइल डाउनलोड करने पर युवक के खाते से लाखों रुपए निकल गए। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 32 वर्षीय पीड़ित के वॉट्सऐप ग्रुप पर आरटीओ चालान के नाम से एक एपीके फाइल भेजी गई थी। पीड़ित ने फाइल को डाउनलोड कर लिया। इसके बाद उसका मोबाइल हैक हो गया और बैंक खातों से हो रहे लेन-देन की जानकारी भी नहीं मिल पाई। कुछ दिन बाद पीड़ित को सेविंग अकाउंट ऐप से पासवर्ड बदलने और डेबिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के मैसेज मिले, तब ठगी की आशंका हुई।

पीड़ित ने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क कर मोबाइल बैंकिंग सहित सभी डिजिटल चैनल बंद कराए। इसके बाद बैलेंस चेक करने पर खुलासा हुआ कि खाते से 2 लाख 79 हजार 290 रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।

आरोपियों ने रेकी कर दिया घटना को अंजाम

बदमाशों ने व्यापारी को कट्टा अड़ाकर छीने सात लाख रुपए

दमोह@पत्रिका. हटा में लूट की कोशिश के बाद अब देहात थाना अंतर्गत लूट का मामला सामने आया है। जहां व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सागर नाका चौकी अंतर्गत सागर रोड पर ग्राम परसोरिया के पास मंगलवार रात इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से करीब 7 लाख रुपए लूट लिए गए।

जानकारी अनुसार किसान भवन के सामने दुकान संचालित करने वाले व्यापारी राजा सिंधी उर्फ राजकुमार नागदेव गढ़ाकोटा क्षेत्र में बकाया राशि की वसूली के लिए गए थे। देर रात वसूली कर वे बाइक से दमोह लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गिरने पर व्यापारी घायल हो गया। इसी दौरान आरोपियों ने कट्टा अड़ाकर नकदी से भरा बैंग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने परिजनों को सूचना दी। वहीं परिजनों से घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 वाहन से पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

गंभीर बीमारी से जूझ रही अनिका के इलाज के लिए जुटे ₹5 करोड़

इंदौर@पत्रिका. गंभीर बीमारी एसएमए (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) टाइप-2 से पीड़ित बच्ची अनिका के उपचार के लिए शहर में चल रहे सामाजिक अभियान के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक की सहायता राशि एकत्रित की जा चुकी है। अनिका के उपचार पर लगभग 9 करोड़ का खर्च अनुमानित है, जिसके लिए अभी 3 करोड़ से अधिक की और आवश्यकता है। मानवीय अभियान 'बच्ची को बच्चे बचाएंगे' ने शहर में सामाजिक संवेदनशीलता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। शहरवासियों, सामाजिक संगठनों और विशेष रूप से विद्यार्थियों के सहयोग से केवल एक दिन में करीब 28 लाख रुपए जुटाए गए। बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में सहायता राशि का चेक अनिका के माता-पिता को सौंपा गया। महापौर ने शहरवासियों से अधिक सहयोग करने की अपील की।

दान पेटी खुली

4 और 5 फरवरी को नेहरू स्टेडियम में रखे दान पात्र को खोला गया। गणना के बाद पूरी धनराशि सीधे एम्स से जुड़े बैंक खाते में जमा कराई। अब तक 5 करोड़ 13 लाख 52 हजार रुपए एकत्रित हुए हैं।

शासन को लगाया 97.41 लाख का चूना

ई-उपार्जन पोर्टल में फर्जी की एंट्री, समिति प्रबंधक-ऑपरेटर पर FIR

जबलपुर@पत्रिका. धान उपार्जन पंजीयन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सेवा सहकारी समिति लखनपुर में प्रबंधक अखिलेश कुमार पटेल और ऑपरेटर अनुराधा पटेल पर आरोप है कि उन्होंने ऐसे 24 किसानों के नाम ई-उपार्जन पोर्टल में दर्ज कर दिए, जिनके पास न तो जमीन थी और न ही धान। इस फर्जी पंजीयन के जरिए शासन को 97 लाख 41 हजार 162 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। मामले का खुलासा जांच के दौरान हुआ, जिसके बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार जाटव ने मंगलवार रात सिहोरा थाने में प्रबंधक और ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनपुर को केंद्र निर्धारित किया गया था। इसके तहत ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किया गया। इस अवधि में कुल 2763 किसानों का पंजीयन दर्ज हुआ।

88.05 हेक्टेयर रकबा दर्शाकर किया घोटाला

पोर्टल में यह भी दर्शाया कि इन 24 किसानों के नाम कुल 88.05 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत है। वहीं मझौली क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर धान उत्पादकता 46.7 क्विंटल दर्ज होने के आधार पर अनुमानित उपार्जन दर्शाया, जिससे शासन को 97.41 लाख की आर्थिक हानि पहुंचाई गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

ट्रेंडिंग न्यूज

हार्ट अटैक

शादी में डांस कर रहे दूल्हे के मामा की मौत

आलीराजपुर. जिले के छकतला गांव में एक शादी समारोह में हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हे के मामा राकेश भारती (वाणी) को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। राकेश पत्नी के साथ स्टेज पर नाच रहे थे। नाचने के बाद वे पानी पीने के लिए स्टेज से नीचे उतरे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई।

धर्म परिवर्तन

झाबुआ में 5 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी

झाबुआ. ग्राम पंचायत माछलिया अंतर्गत नवापाड़ा गांव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 5 परिवारों की ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में वापसी करवाई। कार्यक्रम थावर सिंह भाबर के सान्निध्य में वैदिक मंत्रोच्चार, हवन एवं पूजा-अर्चना के साथ हुआ। ग्रामीणों के अनुसार संबंधित परिवार पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे।

कार्रवाई

27 लाख की अवैध कच्ची शराब जब्त

पिछोर. शिवपुरी जिले के पिछोर थाना अंतर्गत आबकारी विभाग की टीम ने सिलपुरा के कंजर डेरे पर दबिश देकर 27 लाख की अवैध कच्ची शराब जब्त की है। टीम ने अलग-अलग 10 प्रकरण दर्ज कर दो आरोपियों महिला छाया कंजर व युवक नीलेश कंजर को पकड़ा है। घटनास्थल पर शराब बनाने का सामान भी मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है।

खुला सफलता का द्वार | सेंट्रल लाइब्रेरी में पांच हजार से ज्यादा किताबें उपलब्ध

आदिवासी अंचल झाबुआ को मिला 'ज्ञान का मंदिर'

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

झाबुआ. पश्चिमी मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचल में शिक्षा की नई इबारत लिखी जा रही है। जिला मुख्यालय पर 'सेंट्रल लाइब्रेरी' तैयार हो गई है। यह क्षेत्र के हजारों युवाओं के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगी। कलेक्टर नेहा मीना की पहल पर जनजातीय कार्य विभाग के पुराने भवन का रिनोवेशन कर आधुनिक ज्ञान केंद्र में परिवर्तित किया गया है। 2900 वर्गफीट में फैली लाइब्रेरी का निर्माण डीएमएफ और सीएसआर फंड से किया गया है। हाल ही में निरीक्षण पर पहुंचे संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े भी व्यवस्थाएं देखकर प्रभावित हुए। किताबों का संकलन पूरा होते ही विधिवत संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

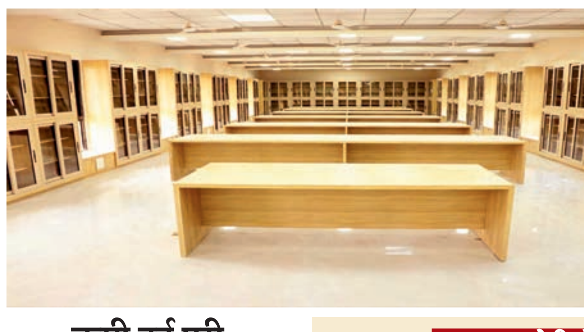

कमी हुई पूरी

जिले में लंबे समय से ऐसी जगह की कमी महसूस की जा रही थी, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अध्ययन सामग्री मिल सके। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान के पास स्थित पुराने भवन को नया रूप देकर यह कमी पूरी कर दी गई है।

सर्वश्रेष्ठ किताबें जुटा रहे

बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ किताबें जुटा रहे हैं। उद्देश्य युवाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, जहां वे ज्ञान अर्जित कर कॅरियर बना सकें। जल्द ही किताबों के लिए डोनेशन ड्राइव भी चलाई जाएगी। **-नेहा मीना,** कलेक्टर

लाइब्रेरी में यह सुविधा

- **क्षेत्रफल:** 2900 वर्गफीट का विशाल परिसर
- **क्षमता:** एक साथ 70 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था
- **संग्रह:** यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्कूल-कॉलेज परीक्षाओं सहित 5000+ पुस्तकें
- **डिजिटल सुविधा:** ऑनलाइन क्लास के लिए विशेष हॉल व कंप्यूटर सेक्शन
- **सुरक्षा:** सीसीटीवी से लैस परिसर, आगंतुकों के लिए वेटिंग रूम

एकलव्य विद्यालय में अव्यवस्थाएं

कलेक्टर से बोले छात्र- घटिया भोजन-फटे गद्दे, करते हैं दुर्व्यवहार

आलीराजपुर@पत्रिका. जिले के आंबुआ स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ बुधवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों छात्र नारेबाजी करते हुए पैदल ही जिला मुख्यालय की ओर निकल पड़े। करीब 20 किमी दूर कलेक्टर से मिलने निकले इन छात्रों ने प्रशासन को हिला कर रख दिया। एसडीएम तपिश पांडे मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त संजय परवाल ने भी समझाइश दी, लेकिन आक्रोश शांत नहीं हुआ। छात्र करीब 10 किमी पैदल चलकर चिचलाना फाटक तक पहुंच गए। सुरक्षा के लिए पुलिस भी साथ थी।

कलेक्टर ने सड़क पर बैठकर सुनी शिकायतें

सूचना पर कलेक्टर नीतू माथुर मौके पर पहुंचीं। उन्होंने छात्रों को रोका और सड़क पर बैठकर समस्याएं सुनीं। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा है। एक छात्रा ने बताया, प्रति छात्र 84 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से विद्यालय को हर महीने करीब 12 से 13 लाख का बजट मिलता है, बावजूद भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है। हॉस्टल में गद्दे फटे हैं। प्राचार्य पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया। कैंपस में रह रहे प्राचार्य के पति के खिलाफ भी नाराजगी दिखाई दी। कलेक्टर ने छात्रों को आश्वस्त किया कि जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुझे बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं, बस बेवकूफी से बचना है। सफल होना चाहते हैं तो पहले यह सीखिए कि क्या नहीं करना है।
चार्ली मुंगर दिग्गज निवेशक

पत्रिका फाइनेंस
@बिजनेस & वेल्थ

पोर्टफोलियो टॉपर
म्यूचुअल फंड्स के पास इन कंपनियों के सबसे अधिक शेयर

एचडीएफसी बैंक	आइसीआइसीआइ-सीआइ	रिलायंस इंडस्ट्री	इंफोसिस
3.34	2.50	1.99	1.35

*(कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स का **निवेश लाख करोड़ रुपए में**)*

जॉब्स उच्च कौशल वाले कर्मचारियों की भर्ती प्रभावित नहीं, एच-1बी खत्म करने के लिए नया विधेयक पेश

$1 लाख एच-1बी वीजा शुल्क के बावजूद हायरिंग जारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

वॉशिंगटन. अमरीकी संसद में एच-1बी वीजा खत्म करने के लिए एक नया विधेयक पेश हुआ है। रिपब्लिकन प्रतिनिधि ग्रेग स्ट्यूबी ने विधेयक पेश करते हुए कहा, एच-1बी वीजा अमरीकी के बजाय विदेशियों को प्राथमिकता देता है। इससे स्थानीय लोगों को नुकसान होता है। इस बीच एक अध्ययन में दावा किया गया है कि एच-1बी वीजा शुल्क 1,00,000 डॉलर करने के बावजूद टेक फर्म्स की हायरिंग जारी है। अमरीकी राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो ने अपनी स्टडी में कहा, वीजा फीस का रोजगार पर असर नहीं हुआ।

शुल्क 2 लाख डॉलर हुआ तो भी असर नहीं

इस अध्ययन में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉर्ज बोर्जास ने कहा, अगर वीजा शुल्क 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर तक बढ़ाया भी जाए, तो भी उच्च कौशल वाले कर्मचारियों की भर्ती में कंपनियों की रुचि कम नहीं होगी। बुर्जास के अध्ययन में पाया कि अधिकांश मामलों में एच-1बी वीजा श्रमिकों की आय अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में कम है। समान शिक्षा, उम्र, लिंग, स्थानीयता और पेशे के आधार पर औसतन एच-1बी वीजा कर्मचारी अमरीकी कर्मचारी से 16% कम कमाते हैं।

46,184 अलग-अलग अमरीकी कंपनियों ने ***चार साल में कम से कम एक एच-1बी वीजा कर्मचारी को हायर किया।***

38.3% एच-1बी वीजाधारक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ***टॉप 5 प्रोफेशन की 70% हिस्सेदारी***

भारतीय कंपनियां दे रहीं कम वेतन: कंपनियों के हिसाब से एच-1बी वीजा कर्मचारियों के वेतन में भारी भिन्नता है। बड़ी अमरीकी टेक कंपनियों जैसे कि मेटा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में एच-1बी कर्मचारियों का औसत वेतन 1.5 लाख डॉलर के करीब है। वहीं, भारतीय आइटी कंपनियों जैसे इंफोसिस और विप्रो में यह औसतन 80,000 डॉलर के आसपास है। बड़ी अमरीकी टेक कंपनियों में वेतन अंतर काफी कम है।

भारत-ब्रिटेन: सामाजिक सुरक्षा समझौता हुआ

भारतीय पेशेवरों के लिए एक अच्छी खबर है। यदि वे तीन साल तक की अवधि के रोजगार के लिए ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड जा रहे हैं तो उन्हें अब पहले की तरह भारत में अपने नियोक्ता से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे ईपीएफ, बीमा, चिकित्सा बीमा आदि का लाभमिलता रहेगा। उन्हें ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा हासिल करने के लिए अंशदान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बातें ब्रिटेन से भारत आने वाले कार्मियों पर लागू होगी। इसके लिए भारत, ब्रिटेन व उत्तरी आयरलैंड ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह उन कर्मियों को दोहरे टैक्सेशन से बचाएगा जो 3 साल तक के लिए ब्रिटेन जाएंगे।

W E A L T H **नेक्स्टजेन बिजनेस** C R E A T I O N

सलाह अलग-अलग एसेट क्लास में उतार-चढ़ाव काफी ज्यादा

सोना, चांदी या शेयर... कहां निवेश करूं?

मुंबई. सोना, चांदी और शेयर मार्केट में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि हाल में सोना और चांदी में आई तेज उठापटक ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। शेयर मार्केट में भी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे अनिश्चितता के माहौल में बहुत से निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां निवेश करें। एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता ने बताया कि हाल के महीनों में ऐसे सवाल बहुत बढ़ गए हैं। ***लोग बार-बार पूछ रहे हैं, 'मेरे पास निवेश करने के लिए 30,000 रुपए हैं, क्या मुझे चांदी खरीदनी चाहिए? मुझे कौन सा फंड चुनना चाहिए?*** उन्होंने कहा, कुछ महीनों से लोग निवेश सलाह लेने के लिए ज्यादा संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग एसेट क्लास में उतार-चढ़ाव काफी ज्यादा है।

एडलवाइस की सीईओ राधिका गुप्ता ने बताए 5 टिप्स

1 *बेसिक चीजें सीखें:* पैसा लगाने से पहले निवेश से जुड़ी बेसिक चीजों को जानें। बहुत से लोग बिना बुनियादी वित्तीय ज्ञान के सीधे निवेश करना चाहते हैं। ***यह ऐसा है जैसे सांस लेना सीखे बिना गोता लगाना।***

2 *इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट:* अपना व्यक्तिगत निवेश स्टेटमेंट बनाइए। अपनी वित्तीय स्थिति और जरूरतों को लिखित रूप में तैयार करें। इसमें चार चीजें शामिल करें- ***कमाई और खर्च, वर्तमान निवेश और देनदारियां, लक्ष्य और उनकी समयसीमा साथ ही नुकसान झेलने की क्षमता।***

3 *प्रोफेशनल की मदद लें:* किसी अच्छे पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल से बात करें। चाहे वह म्यूचुअल फंड वितरक हो या निवेश सलाहकार। ***चाहें तो कई लोगों से बात करें और फिर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिस पर आपको भरोसा हो।***

4 *जल्दबाजी न करें:* जल्दी में कोई बड़ा वित्तीय फैसला न लें। तुरंत डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना, चांदी खरीदना या पीएमए ढूंढना जरूरी नहीं है। ***जब तक खुद सहज महसूस न करें, तब तक इंतजार कर सकते हैं।***

5 *जल्दबाजी न करें:* 5. गलतियों से सीखें: अगर आपने अभी तक निवेश शुरू नहीं किया है, तो शुरुआत करें। अगर शुरू कर चुके हैं और गलतियां हुई हैं, तो परेशान न हों। ***आपको भी कुछ गलतियों की अनुमति है। शांत रहें, सोचें, सीखें और आगे बढ़ें।***

दिसंबर तिमाही रिपोट कार्ड @पत्रिका इंफोग्राफिक्स

बिक्री और नेट प्रॉफिट में छोटी कंपनियों ने मारी बाजी

मुंबई@पत्रिका. *दिसंबर तिमाही में छोटी और मध्यम कंपनियों ने अपनी बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। छोटी कंपनियों ने बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। जहां बड़ी कंपनियों की वृद्धि दर सिंगल डिजिट में रही, वहीं छोटी और मध्यम कंपनियों की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में रही। दिसंबर तिमाही में खर्चों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद छोटी कंपनियां ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी बढ़त दर्ज करने में सफल रहीं।*

बड़ी कंपनियों का हाल

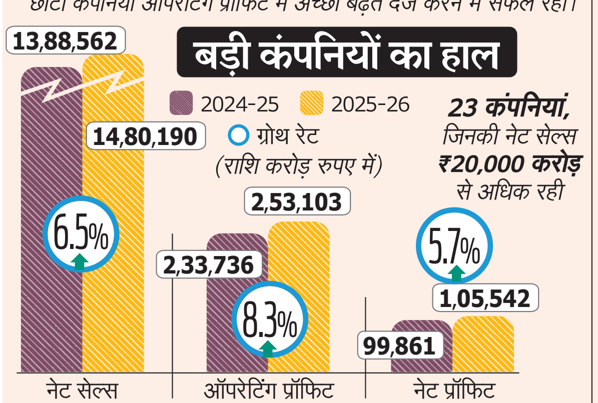

23 कंपनियां, *जिनकी नेट सेल्स **₹20,000 करोड़** से अधिक रही*

मिड-साइज कंपनियों का रिपोर्टकार्ड

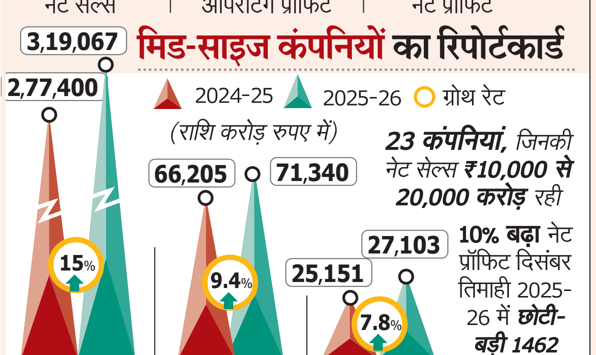

23 कंपनियां, *जिनकी नेट सेल्स **₹10,000 से 20,000 करोड़** रही*

10% बढ़ा नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही 2025-26 में ***छोटी-बड़ी 1462 कंपनियों का***

छोटी कंपनियों का ऐसा रहा प्रदर्शन

1416 कंपनियां जिनकी कुल बिक्री **₹10,000 करोड़** के कम

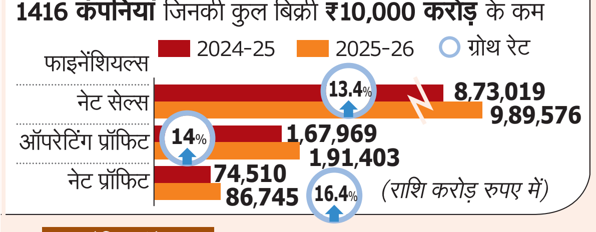

तैयारी ₹1,00,000 तक होटल बिल के लिए पैन देना जरूरी नहीं

50,000 रुपए से अधिक जमा निकासी पर पैन का झंझट खत्म

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. केंद्र सरकार पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। अगर आप बैंक में कैश जमा करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, होटल में पेमेंट करते हैं या इंश्योरेंस लेते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। सरकार ने नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किन-किन रोजमर्रा के पैसों के लेन-देन में पैन कार्ड देना जरूरी होगा। इन बदलावों का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। इन नियमों को 1 अप्रेल 2026 से लागू करने की तैयारी है। सभी सुझावों पर चर्चा के बाद फाइनल नियमों को मार्च में नोटिफाई किया जा सकता है।

ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, एक अप्रेल से बैंक में एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक की जमा-निकासी पर पैन देना जरूरी नहीं होगा, बल्कि साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा के कैश डिपॉजिट या विदड्रॉल पर ही पैन देना अनिवार्य होगा। साथ ही एक लाख रुपए से अधिक के होटल के कमरे के पेमेंट पर ही पैन देना जरूरी होगा। अब आप प्रॉपर्टी की खरीद, बिक्री, गिफ्ट, और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से ज्यादा हो तो ही पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। कार-बाइक की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा हुई तो पैन कार्ड जरूरी होगा। अभी वाहन खरीदने पर पैन कार्ड जरूरी है। नए नियम से सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स को आसानी होगी। लेकिन हाई कैश यूजर्स, रियल एस्टेट खरीद-बिक्री करने वाले लोगों के लिए बिना पैन दिए बड़े खर्च करना नामुमकिन होगा।

ये बड़े बदलाव 1 अप्रेल से लागू होंगे

1 होटल बिल: एक अप्रेल से 1,00,000 रुपए से कम के ***होटल बिल के भुगतान पर पैन देना जरूरी नहीं होगा। अभी यह सीमा 50,000 रुपए है।***

2 गाड़ी की खरीद: दोपहिया या चौपहिया वाहन (कार आदि) खरीदते समय अगर कीमत 5 लाख रुपए से अधिक है, तो पैन देना अनिवार्य होगा। ***ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैन देना जरूरी नहीं।***

3 *प्रॉपर्टी:* अचल संपत्ति के मामले में अगर कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो पैन कोट करना जरूरी होगा। ***अभी इसकी सीमा 10 लाख रुपए है। यानी सीमा दोगुनी की गई है।***

4 नकद लेन-देन: साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा के कैश डिपॉजिट या विदड्रॉल पर पैन देना अनिवार्य होगा। ***अभी सीमा 20 लाख रुपए है। नकद लेनदेन पर सख्ती।***

5 *इंश्योरेंस:* बीमा कंपनियों के साथ खाता-आधारित संबंध रखने के लिए पैन जरूरी कर दिया गया है। ***अभी 50,000 रुपए से अधिक प्रीमियम होने पर ही पैन देना जरूरी है।***

कैश जमा या निकालना अब कैसे बदलेगा?

पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा या निकासी करते है तो पैन अनिवार्य होगा। अभी एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा के लेनदेन पर पैन अनिवार्य है। यानी अब रोज-रोज की टेंशन खत्म। सालभर की कुल रकम अहम होगी।

क्रिप्टो करेंसी पर भी सख्ती

■ ***क्रिप्टो एक्सचेंज:*** अब क्रिप्टो एक्सचेंजों को अनिवार्य रूप से टैक्स विभाग के साथ जानकारी साझा करनी होगी। ***इससे क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर निगरानी बढ़ेगी।***

■ ***सीबीडीसी:*** सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को ***इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के एक स्वीकार्य मोड के रूप में मान्यता दी जाएगी।***

रियल एस्टेट फिल्मी सितारों के जरिए खरीदारों को आकर्षित कर रहे

बॉलीवुड सितारों के दम पर 'पिक्चर' हिट कराना चाहते हैं दुबई के डेवलपर्स

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर इन दिनों बॉलीवुड स्टार पावर के दम पर भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। लग्जरी वॉटरफ्रंट अपार्टमेंट्स से लेकर मिड-इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तक, दुबई के डेवलपर्स अब बड़े फिल्मी सितारों के जरिए भारतीय निवेशकों और खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं।

दुबई की प्रमुख डेवलपर डैमैक प्रॉपर्टीज ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को ब्रांड एंबेसडर बनाया है। वहीं दानुब प्रॉपर्टीज ने शाहरुख खान को अपने साथ जोड़ा है। इम्तियाज डेवलपमेंट्स ने ऋतिक रोशन को अपने अभियानों का चेहरा बनाया है। इन कंपनियों का मानना है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से न सिर्फ ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि भारतीय खरीदारों के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होता है। डेवलपर्स के मुताबिक, भारत दुबई के लिए सबसे तेजी से उभरते विदेशी बाजारों में शामिल है।

...इसलिए दुबई बना हॉटस्पॉट

एक करोड़ रुपए के मकान पर कैलकुलेशन

विवरण	दिल्ली-मुंबई	दुबई
मासिक किराया	25,000-40,000	70,000-1,20,000
किराए पर टैक्स	30% तक	00%
सालाना रिटर्न	6-10%	16%
स्टाम्प ड्यूटी	06%	04%
लोन ब्याज दर	8-9%	04%
किराए का रिटर्न	2-4%	8-12%

3 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो जाएंगे दुबई में अगले 3 साल में, इसलिए बॉलीवुड सितारों को अपने साथ जोड़ रहे डेवलपर, ***ताकि भारतीयों को आकर्षित करें***

रियल्टर्स और बॉलीवुड का गठजोड़

- डैमैक प्रॉपर्टीज ब्रांड एंबेसडर: **आलिया-रणबीर**
- दानुब प्रॉपर्टीज ब्रांड एंबेसडर: **शाहरुख खान**
- इम्तियाज डेवलपमेंट्स **ऋतिक रोशन**

भारत सबसे तेजी से उभरता विदेशी बाजार

पहले जहां भारतीय निवेशक केवल निवेश के उद्देश्य से प्रॉपर्टी खरीदते थे, अब बड़ी संख्या में एंड-यूजर भी सामने आ रहे हैं। टैक्स लाभ, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर रिटर्न और वैश्विक कनेक्टिविटी दुबई को भारतीयों के लिए आकर्षक गंतव्य बना रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनियों का कहना है कि आने वाले वर्षों में दुबई में 3 लाख से ज्यादा नई आवासीय इकाइयों की डिलीवरी की योजना है। ऐसे में डेवलपर भारतीयों को ध्यान में रखते हुए विशेष भुगतान योजनाएं और प्रमोशनल ऑफर तैयार कर रहे हैं।

मार्केट कैप @पत्रिका इंफोग्राफिक्स

टीसीएस को छोड़ा पीछे

एसबीआइ बनी देश की चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी

मुंबई@ पत्रिका. *एसबीआइ ने मार्केट कैप के लिहाज से टाटा ग्रुप की टीसीएस को पछाड़ दिया। एसबीआइ अब देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। दमदार दिसंबर तिमाही नतीजे के कारण बुधवार को कंपनी के शेयर 3.23% की बढ़ोतरी के साथ 1,181 रुपए पर बंद हुए।*

देश की टॉप 10 कंपनियां

कंपनी	मार्केट कैप	नेट प्रॉफिट
रिलायंस इंडस्ट्रीज	19.87	22,290
एचडीएफसी बैंक	14.26	18,654
भारती एयरटेल	12.05	4091
एसबीआइ	10.92	21,028
टीसीएस	10.53	10,720
आइसीआइसीआइ	10.02	11,318
इंफोसिस	6.10	6654
एचयूएल	5.78	जारी नही
एलएंडटी	5.73	3215
एक्सिस बैंक	4.18	6490

(मार्केट कैप लाख करोड़ रुपए में, दिसंबर तिमाही 2025-26 का नेट प्रॉफिट करोड़ रुपए में)

जांच अमरीकी बैन दरकिनार करने का आरोप

ईरान से एलपीजी आयात पर अदाणी ग्रुप से मांगा जवाब

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज ने मंगलवार को कहा कि एक अमरीकी एजेंसी ने प्रतिबंधित इकाइयों के साथ लेनदेन की गैर-आपराधिक जांच के तहत ईरान से पेट्रोलियम उत्पादों के कथित आयात को लेकर कंपनी से जानकारी मांगी है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसे 4 फरवरी को अमरीकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) से सूचना का अनुरोध मिला है। यह अनुरोध जून, 2025 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के संबंध में हुई स्वैच्छिक चर्चा के बाद आया है।

क्या है आरोप

उस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि अदाणी से जुड़ी कंपनियों ने अमरीकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए शिपिंग मार्गों का उपयोग करके भारत में ईरानी तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का आयात किया था। अदाणी एंटरप्राइजेज ने कहा- कंपनी स्वेच्छा से विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ सहयोग कर रही है और मांगी गई जानकारी देगी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि अमरीकी प्राधिकरण से प्राप्त संचार में किसी भी प्रकार के उल्लंघन या गैर-अनुपालन का कोई निष्कर्ष शामिल नहीं है।

कॉर्पोरेट हलचल

अकासा एयर के को-फाउंडर प्रवीण अय्यर का इस्तीफा

नई दिल्ली @ पत्रिका. दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की निवेश वाली अकासा एयर के को-फाउंडर और चीफ कमर्शियल ऑफिसर (सीसीओ) प्रवीण अय्यर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।अकासा एयर में पिछले 6 माह में यह दूसरा बड़ा इस्तीफा है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में कंपनी की इंटरनेशनल ऑपरेशंस की हेड और को-फाउंडर नीलू खत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था। प्रवीण 30 अप्रेल 2026 तक कंपनी के साथ बने रहेंगे ताकि नई लीडरशिप को जिम्मेदारी सौंपने में मदद कर सकें। उनकी जगह अब आनंद श्रीनिवासन को नया सीसीओ नियुक्त किया गया है। आनंद श्रीनिवासन अब कमर्शियल टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। आनंद फिलहाल कंपनी में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पद पर हैं।

गगनयान मिशन पर दिया बयान

भारत इंसानों को जल्द अंतरिक्ष में भेजेगा: शुभांशु शुक्ला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बेंगलूरु. भारतीय अंतरिक्ष यात्री और अशोक चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि तमाम जटिलताओं और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत को महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को उत्साह और लगन के साथ बढ़ाना चाहिए।

भारत-अमरीका स्पेस बिजनेस फोरम में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि गगनयान अभियान की सफलता भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करेगी, जिन्होंने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण किया है। उन्होंने बताया कि दुनिया में केवल तीन अन्य देशों ने ऐसा किया है। शुक्ला इस मिशन के लिए चयनित चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं।

उन्होंने माना कि इस तरह के तकनीकी मिशन में देरी और बाधाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें असफलता नहीं माना जाना चाहिए। अंतरिक्ष सहयोग पर उन्होंने एक्सिओम मिशन का उदाहरण देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से अंतरिक्ष अन्वेषण को नई दिशा मिल सकती है। शुक्ला ने कहा कि इसरो तय मिशनों को पूरा करने में जुटा है। उन्होंने विज्ञान और अंतरिक्ष पर बढ़ते खर्च को भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसरो का लक्ष्य वर्ष 2027 तक गगनयान मिशन को प्रक्षेपित करना है।

वृंदावन उद्घाटन के कुछ घंटों बाद होटल में आग, 40 लोगों को बचाया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मथुरा. मथुरा के वृंदावन में सिद्धि विनायक होटल में बुधवार को उद्घाटन के कुछ घंटों बाद भीषण आग लग गई। इससे होटल में अफरा-तफरी मच गई। करीब 40 लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड और क्रेन की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। आग से दो बच्चे व एक महिला झुलस गई। दमकलों की डेढ़ घंटे मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। होटल की फायर सेफ्टी मानकों पर सवाल खड़े हो गए। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

फोर्ब्स रिपोर्ट मस्क ने अपनी नेटवर्थ का केवल 0.05% दान किया, बफे सबसे बड़े दानवीर

मस्क सहित अमरीकी धनकुबेर दान में फिसड्डी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

न्यूयॉर्क. धनकुबेरों के क्लब में सुर्खियां आमतौर पर इस बात पर टिकी रहती हैं कि ट्रिलियन-डॉलर रेस में कौन आगे है। एलन मस्क, जेफ बेजोस और लैरी पेज जैसे नाम अक्सर इस दौड़ के सितारे होते हैं, जहां उनकी हर कमाई को मानो स्कोरबोर्ड पर अंक की तरह देखा जाता है। ये अमरीकी बिजनेसमैन भले ही अरबों कमाने में सबसे आगे हैं, पर समाज सेवा और दान करने में सबसे फिसड्डी हैं। वर्ष 2026 के लिए फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वार्षिक 'टॉप 25 फिलैंथ्रोपिस्ट' सूची ने यह दिखाया कि अरबों की संपत्ति रखने वाले अमरीकी कारोबारी दान के मामले में टॉप पर नहीं हैं। एलन मस्क की कुल संपत्ति 850 अरब डॉलर से ज्यादा है, पर उन्होंने अपने जीवनभर में एक अरब डॉलर से भी कम दान किया है।

इन्होंने किया सबसे ज्यादा दान

अरबपति	नेटवर्थ	जीवनभर में दान	नेटवर्थ में हिस्सेदारी
वॉरेन बफे	146	68.3	32%
बिल गेट्स	134	52.6	28%
मैकेंजी स्कॉट	30.9	26.4	46%
माइकल ब्लूमबर्ग	109	25.4	19%
जॉर्ज सोरोस	7.5	24	76%
मेरिलिन सिमोंस	32.6	10.3	24%
स्टीव बॉलमर	141	6.5	4%

ये अमीर दान के मामले में कंजूस

वॉरेन बफे

एलन मस्क

अरबपति	नेटवर्थ	जीवनभर में दान	नेटवर्थ में हिस्सेदारी
एलन मस्क	854	0.5	0.05%
लैरी पेज	270	0.1	0.03%
जेफ बेजोस	250	4.7	1.85%
सर्जी ब्रिन	249	5.1	2.01%
लैरी एलिसन	241	1.0	0.41%
मार्क जकरबर्ग	213	6.1	2.78%
जेनसेन हुआंग	162	0.2	0.11%

(नेटवर्थ और दान की राशि अरब डॉलर में)

वॉरेन बफे परोपकार के क्षेत्र में अब भी मिसाल

मस्क का 'फिलैंथ्रोपी स्कोर' महज 1 है। उनकी संपत्ति की तुलना में उनका आजीवन दान 0.05% से भी कम है। वहीं, वॉरेन बफे परोपकार के क्षेत्र में मिसाल हैं। 2025 में 95 वर्ष की आयु में बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से सेवानिवृत्त होने के बावजूद उनका दान लगातार जारी है। फोर्ब्स के अनुसार, बफे ने जीवनकाल में 68.3 अरब डॉलर दान किए हैं। उन्होंने इस साल भी 6.3 अरब डॉलर से अधिक दान किया। उनका योगदान मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है। इसी तरह बिल और मेलिंडा गेट्स के साथ स्कॉट मैकेंजी अमरीकी दानवीरों की सूची में टॉप 3 में शामिल हैं। यह सूची बताती है कि संपत्ति की ऊंचाई और उदारता की गहराई हमेशा एक समान नहीं होती।

दावा

भारत अब अमरीका-वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा

नई दिल्ली @ पत्रिका. अब रूस से नहीं, बल्कि अमरीका और वेनेजुएला से टैंकर भर-भर कर कच्चा तेल भारत आएगा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने देश की सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों से कहा है कि वे अब अमरीका और वेनेजुएला से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने पर विचार करें। हालांकि भारत सरकार का साफ कहना है कि भारत देशहित में वहां से तेल खरीदेगा, जहां से उसे सस्ता कच्चा तेल मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबित, रिफाइनरियों ने बताया कि कंपनियों को स्पॉट मार्केट की बोलियों में अमरीकी च्चे तेल को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वेनेजुएला के कच्चे तेल के बारे में भी इसी तरह का सुझाव दिया गया है।

पेज एक का शेष

पीएम ने...

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि कांग्रेस वंदे मातरम् के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर, 1937 को वंदे मातरम् के विरुद्ध नारा बुलंद किया था। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। नेहरू ने मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देने और उसके बयानों की निंदा करने के बजाय वंदे मातरम् की ही पड़ताल शुरू कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने...

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा था कि सब कैटेगिरी का आधार उचित होना चाहिए। इसके साथ ही संवैधानिक पीठ ने एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमीलेयर को लागू करने की बात कही थी।

भारत मां...

राहुल गांधी ने कहा कि बिजनेसमैन अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं, इसकी वजह है एपस्टीन फाइल। इसके साथ ही राहुल ने मंत्री हरदीप पुरी का नाम भी जोड़ दिया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सांसद रविशंकर प्रसाद ने आपत्ति की।

राहुल ने कहा कि भारतीय इतिहास में पहली बार हमारे किसान तूफान का सामना कर रहे हैं। मक्का, सोयाबीन जैसी फसलों में आपने दरवाजा खोल दिया है। किसानों को मशीनीकृत अमरीकी खेती से मुकाबले के लिए मजबूर किया है। टेक्सटाइल की रेस में भारत 18 फीसदी टैरिफ की बेड़ियों में दौड़ेगा और बांग्लादेश 0 फीसदी टैरिफ के खुले मैदान में। राहुल ने कहा कि इस डील के बाद अमरीका से हमारा इंपोर्ट 46 बिलियन से बढ़कर 146 बिलियन हो जाएगा और हमारा टैरिफ 3 प्रतिशत से बढ़कर 18 हो गया है और उनका 16 से घटकर जीरो हो गया है।

दालों का...

यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि दालों का आयात भारत के कृषि क्षेत्र के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। भारत दुनिया में दालों (मसूर, चना, सूखी फलियां) का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारतीय किसानों को नुकसान से बचाने के लिए भारत लंबे समय से अमरीकी दालों पर ऊंचा आयात-शुल्क लगाता आया है।

डिजिटल सर्विस टैक्स पर भी बदलाव: पहले संस्करण में कहा गया था कि भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा, लेकिन संशोधित फैक्टशीट में यह दावा नहीं है। अब दस्तावेज में सिर्फ यह कहा गया है कि भारत डिजिटल व्यापार (डिजिटल ट्रेड) से जुड़े नियमों पर बातचीत करने के लिए तैयार है।

प्रेरणा

विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। -हेलेन केलर

संपादकीय

नियमों के जंजाल में उलझी है हमारी आंत्रप्रेन्योरशिप

संसद में सरकार ने बताया कि अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स में से जिन 25 पर जमीन अधिग्रहण के अभाव में काम रुक गया है, उनमें से 24 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स से सम्बंधित हैं। रुकने का कारण ट्रांसमिशन लाइन्स के नीचे की जमीन के अधिग्रहण में विलम्ब था यानी रिन्यूएबल एनर्जी की उपलब्धता के बावजूद लाइन्स न होने से ट्रांसमिशन नहीं हुआ। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा रेगुलेशन वाला देश है। एक कंपनी को 1536 कानूनों, 6618 स्टेटमेंट्स, 69233 अनुपालनों से गुजरना होता है। एक दवा कंपनी को 998 नियमों का पालन करना होता है, जिनमें से 49% वे हैं जिनमें जेल की सजा है। इन सबके बावजूद कफ सिरप कांड में दर्जनों मौतें हुईं। कानून तोड़कर नशे के लिए कफ सिरप बेचने वालों और नकली दवा बनाने वालों का अंतर-राज्यीय गिरोह वर्षों से यह काम कर रहा है। यानी ईमानदार व्यापारियों/उद्यमियों को कानून के अनुपालन में भारी राशि और समय खर्च करना पड़ रहा है और बेईमान सरकारी तंत्र को मालामाल कर रहे हैं। भारत ने व्यापक ट्रेड डील्स की हैं। इनके तहत मैन्युफैक्चरिंग को भारी उछाल देना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आसिआन, जीसीसी, साफ्टा, इफ्टा, मर्कोसुर में भारत का सामान जाता है। अगर भारत में चीन अपना बल्ब, मूर्तियां, सामान्य टोपियां तक बेच सकता है तो समस्या उद्यमिता में नहीं, उद्यमिता के माहौल के अभाव की है। अगर अनुबंधों को फलीभूत करना है तो सरकार उसके लिए माहौल भी दे।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

माता-पिता बच्चों के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएं

इन दिनों अपने बच्चों के लालन-पालन में कुछ अधिक ही अलर्ट माता-पिता उनसे अत्यधिक पूछताछ करते हैं और टोका-टाकी करते रहते हैं। इस चक्कर में वो भूल जाते हैं कि बच्चों के मनोविज्ञान पर विपरीत असर पड़ रहा है। कुछ माता-पिता तो भोजन के समय भी बच्चों को इतने अधिक विकल्प दे देते हैं कि बच्चे 'डिसीजन फटीग' में आ जाते हैं, यानी निर्णय लेने की क्षमता हिलने लगती है या वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। या तो बच्चे कह देते हैं या सोचते हैं कि क्या हम अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकते। और यहीं से माता-पिता की चुनौती शुरू हो जाती है। उनकी इच्छाओं की ज्यादा पूछताछ करना या अपनी इच्छा उन पर लादना, भविष्य में उनको एंग्जायटी में पटक देगा। जैसे किसी बच्चे को कई खिलौने ला दो तो वह खेलता नहीं है, खिलौने में उलझता है। और यदि एक खिलौना दे दो तो वो तबीयत से खेलता है। माता-पिता बच्चों के स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएं। उन्हें सुनें अधिक, सुनाएं कम और यदि सुनाना ही है तो प्रेरक प्रसंग और आदर्श पात्रों की बात कम से कम रात को सोने के पहले अवश्य सुना दें।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

सोलर प्लांटों के लिए पेड़ों की कटाई रुके

एक तरफ तो सरकार अधिकाधिक संख्या में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करती है। दूसरी ओर, सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए वनों से खेजड़ी जैसे पूजनीय वृक्षों को भी काटने से पीछे नहीं हट रही। पर्यावरण को बचाने के लिए अब सरकार को सोलर कम्पनियों द्वारा जंगलों से पेड़ों को काटने पर सख्त रोक लगानी चाहिए। पर्यावरण जीवित रहेगा तब ही भावी पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की जा सकती है। -अजीतसिंह सिसोदिया, खारा, राजस्थान

दलहन खेती को बढ़ावा मिले

दालों से बहुत-से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। किसानों को दलहन खेती की जानकारी लेनी चाहिए। सरकारें, कृषि विशेषज्ञ और किसान दलहन खेती को बढ़ावा दें तो दालों के दाम आसमान नहीं छू पाएंगे। दालों के निर्यात से किसानों और देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले 109 उन्नत किस्म के बीज जारी किए थे। उम्मीद है इसी तर्ज पर दलहन बीज भी तैयार किए जाएंगे। -राजेश कुमार चौहान, जालंधर, पंजाब

सड़क पर गड्ढे बन रहे जानलेवा

एक तरफ हमारे यहां शानदार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं बरसात के मौसम में सड़कों पर गड्ढों का अंबार लग जाता है। ये गड्ढे आम जनता की परेशानी कई गुना बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसे गड्ढे लोगों की मौतों का कारण भी बन जाते हैं। देश में गड्ढों भरी सड़कों की वजह से हर साल होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है।
-साजिद अली, इंदौर, मध्य प्रदेश

आमजन की पर्यावरणीय पहलें सराहनीय

महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ गांवों में जल-जंगल बचाने के लिए चल रहीं पर्यावरणीय पहलें उस भारत की तस्वीर दिखाती हैं, जहां समाधान किसी आदेश-योजना का इंतजार नहीं करते, बल्कि जमीन से उठते हैं। सोलापुर के पथरीले गांवों से लेकर धुळे के जंगलों और बेंगलुरु के बाहरी इलाके के एक छोटे गांव तक, लोगों ने साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो हरियाली की रक्षा असंभव नहीं। -कांतिलाल मांडोत, सूरत, गुजरात

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

जापान में सिर्फ एक छात्रा के लिए 14 महीने तक चली ट्रेन

जापान के होक्काइडो आइलैंड में करीब 14 माह तक पूरी ट्रेन महज एक छात्रा को ले जाने और वापस लाने के लिए संचालित की गई थी। 2015 की शुरुआत में जापान रेलवे ने शून्य यात्री भार के चलते क्युशिराताकी रेलवे स्टेशन को पूरी तरह बंद करने का निर्णय कर लिया था। लेकिन बाद में रेलवे प्रशासन को पता चला कि वहां से एक छात्रा रोजाना अपने स्कूल जाती है तो स्टेशन को संचालित रखा गया। जब छात्रा ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो इस स्टेशन को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया।

2016 में 21 मार्च को छात्रा ने अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा दी थी। इसी दिन क्युशिराताकी स्टेशन ने भी अपनी अंतिम सेवा दी।

पैनी नजर • चुनावों के मद्देनजर साम्प्रदायिक माहौल को गर्म बनाए रखने में लाभ देखा जा रहा है

असम की राजनीति में क्या चल रहा है?

सियासत

राजदीप सरदेसाई
वरिष्ठ पत्रकार
rajdeepsardesai52@gmail.com

सोशल मीडिया के पहले ही नैतिक रूप से चिंतनीय मानकों के बावजूद असम भाजपा ने जो वीडियो शेयर किया था, वह तो पतन की एक नई सीमा को छूने वाला था। इस विवादास्पद वीडियो (जिसे अब हटा दिया गया है) में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को 'पॉइंट ब्लैंक' रेंज से एयर राइफल चलाते दिखाया गया था। उनके निशाने पर दो व्यक्ति थे- एक टोपीधारी, एक दाढ़ीधारी। वीडियो में दावा किया गया था कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ और असमिया अस्मिता की रक्षा के पक्ष में है। लेकिन वीडियो से प्रकट होने वाली हिंसक, साम्प्रदायिक छवि खुले तौर पर द्वेषपूर्ण थी। किसी राज्य का मुख्यमंत्री- एक संवैधानिक रूप से निर्वाचित नेता- किसी समुदाय की तरफ इस तरह खुलकर बंदूक ताने- यह संवैधानिक दायित्वों के उल्लंघन का अत्यंत गंभीर उदाहरण है।

अलबत्ता बाद में सरमा ने दावा किया कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह की सफाई अब कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उस वीडियो को असम भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल से साझा किया गया था। हटाए जाने से पहले इसे दस लाख से अधिक बार देखा जा चुका था। और यह अपने तरह की इकलौती घटना भी नहीं थी।

कई महीनों से सरमा 'मियां' शब्द का उपयोग करते हुए एक टॉक्सिक प्रचार-अभियान चला रहे हैं। यह असम में बंगाली-भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक संबोधन है। सरमा ने 'मियांओं' के आर्थिक बहिष्कार तक की अपील की है- चाहे वे दुकानदार हों, सब्जी विक्रेता हों या ऑटो-रिक्शा चालक। अपने रुख पर खेद जताने के बजाय, सरमा ने उलटे अपने बयानों को असम की सांस्कृतिक-सभ्यतागत पहचान की रक्षा के लिए 'आवश्यक' बताया है।

जाहिर है कि सरमा को अपने इस तरह के बयानों में चुनावी लाभ की संभावना दिखती है। आज जब सरमा और उनके परिवार पर बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तब साम्प्रदायिक बयानबाजी जरूरी मसलों से ध्यान भटकाने के साथ ही समाज को ध्रुवीकृत करने का भी उपकरण बन जाती है।

'बाहरी' लोगों के प्रति गुस्सा दशकों से असम के जटिल जातीय परिदृश्य का हिस्सा रहा है। इस कारण से राज्य में मुसलमानों की आबादी लगभग 38 प्रतिशत होने के अनुमान के बावजूद, डेमोग्राफी में बदलाव और सांस्कृतिक क्षरण को लेकर आशंकाओं को भड़काना आसान हो जाता है। यही कारण है कि जो बात असम के बाहर प्रथम दृष्टया हेट-स्पीच मानी जाएगी, उसे राज्य के भीतर स्थानीय आबादी के ऐतिहासिक, भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के रूप में पेश किया जा रहा है।

भाजपा नेतृत्व भी इस आपत्तिजनक वीडियो पर चुप्पी साधे हुए है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के नारे के बावजूद असम के चुनावों को देखते हुए वहां साम्प्रदायिक माहौल को गर्म बनाए रखने में राजनीतिक लाभ देखा जाता है। भाजपा के नेतागण भी 'घुसपैठियों' के कथित खतरे का उल्लेख करना नहीं भूलते। जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी केंद्रीय बलों की जिम्मेदारी होती है।

अधिक चिंता की बात यह है कि आज स्वयं को 'सेकुलर' कहने वाला वर्ग भी बहुसंख्यकवादी राजनीति के विजयरथ के सामने लगभग निरुत्तर और निरुपाय दिखाई देता है। कुछ नागरिकों ने जरूर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उपरोक्त वीडियो के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन व्यापक राजनीतिक वर्ग ने सरमा की साम्प्रदायिकता का सीधा सामना करने को लेकर हिचकिचाहट दिखाई है। उन्हें अंदेशा है कि इससे हिंदू मतदाता उनसे और दूर हो सकते हैं।

आज बहुसंख्यक हिंदू वोटों के लिए लगी हुई है होड़...

एक समय था जब कांग्रेस जैसी पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता था; लेकिन आज भारतीय राजनीति में बहुसंख्यक हिंदू वोटों के लिए होड़ लगी है। शायद यही कारण है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इतनी बेबाकी से विवादित बयान दे पाते हैं।

एक समय था जब कांग्रेस जैसी पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता था; लेकिन आज बहुसंख्यक हिंदू वोटों के लिए होड़ लगी है। यदि असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में सरमा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, तो इसका कारण यह है कि वे हिंदू वोटों पर निर्भर नहीं हैं।

और शायद यही कारण है कि सरमा इतनी बेबाकी से हेट-स्पीच कर पाते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे एक नेता का भाजपा का पोस्टर-बॉय बन जाना भी समकालीन राजनीति में अवसरवादी पालाबदल की नायाब मिसाल है। असम के मुख्यमंत्री ने 2015 में चर्चित रूप से दावा किया था कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि राहुल गांधी ने एक निजी बैठक में उनका 'अपमान' किया था। यह कि राहुल ने असम के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अपने पालतू कुत्ते को बिस्कुट खिलाना अधिक महत्वपूर्ण समझा था। जबकि सच्चाई यह है कि जब कांग्रेस में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को महत्व नहीं मिला तो भाजपा उनके लिए एक सुरक्षित और अनुकूल विकल्प बन गई। तब, यह तथ्य भी भुला दिया गया कि भाजपा ने ही कभी सरमा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पर उनके पाला बदलते ही उनके खिलाफ सभी मामले या तो वापस ले लिए गए हैं या उनकी चाल सुस्त कर दी गई है।

57 वर्षीय सरमा आज भाजपा की नई पीढ़ी की अग्रिम पंक्ति में खड़े नेता हैं। यह वो पीढ़ी है, जो राजनीतिक शुचिता, नैतिक संयम या संवैधानिक मूल्यों की उन सीमाओं से बंधी नहीं दिखती, जिनसे अटल-आडवाणी युग के भाजपा नेता किसी हद तक बंधे थे। यह पीढ़ी सबसे बढ़कर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की तीव्र आकांक्षा से संचालित होती है। यही कारण है कि उत्तर-पूर्व में पार्टी के प्रमुख चेहरे, कुशल चुनाव प्रबंधक और संकटमोचक के रूप में सरमा को आज एक अमूल्य 'एसेट' माना जाता है। लेकिन राजनीति से इससे बेहतर की अपेक्षा रखने वाले नागरिक सरमा के रवैये से जरूर विचलित होंगे।

पुनश्च : जब हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की थी तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कथित रूप से पार्टी नेतृत्व को आगाह किया था कि 'वे भविष्य के नेता हैं, हम उनके जैसे नेता को मिस करेंगे।' आज एक दशक बाद वह 'भविष्य का चेहरा' क्या उन्हें किसी स्याह वर्तमान का हिस्सा लगता होगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

नजरिया • संसद ठप रहेगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा

संसद सुचारु रूप से चले, यह आखिर किसकी जिम्मेदारी?

विधायिका

आरती जेरथ
राजनीतिक टिप्पणीकार
aratijerath@gmail.com

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वालों के लिए यह देखना बहुत पीड़ादायक रहा है कि बजट सत्र में निरंतर हंगामे के बीच संसद की सम्मानित परम्पराएं टूटती रहीं। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारम्परिक उत्तर नहीं देने दिया गया हो। 2004 में मनमोहन सिंह को भी यह अवसर नहीं मिला था। लेकिन इस बार एक नया उदाहरण तब स्थापित हुआ, जब प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा में उस समय उपस्थित नहीं थे, जब प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया।

यदि विपक्ष-प्रेरित हंगामे ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस को निष्प्रभावी कर दिया, तो बजट पर चर्चा भी अराजकता की भेंट चढ़ती दिखी है। न तो सत्तारूढ़ भाजपा और न ही कांग्रेस-नेतृत्व वाला विपक्ष किसी ऐसे समझौते में दिलचस्पी दिखा रहा है, जिससे संसद के तीन वार्षिक सत्रों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले बजट सत्र को वांछित गंभीरता मिल सके। वास्तव में, सदन में व्यवधान और बार-बार स्थगन भाजपा के लिए अच्छा ही है, क्योंकि इससे उसे असहज सवालों से बचने का सुविधाजनक अवसर मिल जाता है। दूसरी ओर, विपक्ष- विशेषकर कांग्रेस- मानो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि हंगामा और नारेबाजी गंभीर व तर्कपूर्ण बहसों की तुलना में जनता तक उसका संदेश अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकती है।

कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में जब अरुण जेटली राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि संसद में अवरोध पैदा करना अलोकतांत्रिक नहीं है। एक वर्ष बाद लोकसभा में उनकी समकक्ष सुषमा स्वराज ने भी यही दृष्टिकोण दोहराया। उन्होंने 2012 में कहा था, संसद को चलने नहीं देना भी लोकतंत्र का ही एक रूप है।

संसद के हालिया इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक दलों के बीच यह धारणा लगभग एक सामान्य प्रवृत्ति बन चुकी है। 1995 में जब भाजपा विपक्ष में थी, तब उसने नरसिंह राव सरकार के दूरसंचार मंत्री सुखराम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पूरे शीतकालीन सत्र को ठप कर दिया था। 2001 में, वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान कांग्रेस ने तो तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का बहिष्कार ही कर दिया था। फर्नांडिस का नाम तहलका टेप प्रकरण में सामने आया था। कांग्रेस सांसद फर्नांडिस को संसद में बोलने से रोकने के लिए हंगामा करते थे। उन्होंने उस संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में भाग लेने से भी इनकार कर दिया, जिसकी अध्यक्षता फर्नांडिस कर रहे थे। 2010 में भी एक और शीतकालीन सत्र मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को झकझोर देने वाले 2जी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की भाजपा की मांग के कारण व्यर्थ चला गया था।

विपक्षी दलों को भले ही ऐसे व्यवधानों के लिए दोषी ठहराया जाए, यह भी सच है कि संसद का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है- चाहे इसके लिए उसे विपक्ष से समझौते की दिशा में एक कदम पीछे ही क्यों न लेना पड़े।

तीखे ध्रुवीकरण के इस दौर में- जब राजनीतिक खेमों के बीच दरारें गहरा चुकी हैं- संसद की प्रतिष्ठा बचाने के लिए संयम, धैर्य और समझौते की दिशा में एक कदम पीछे हटने की तत्परता अब पहले से अधिक जरूरी हो गई है।

जब फर्नांडिस के बहिष्कार का सिलसिला डेढ़ वर्ष तक खिंच गया था तो अंततः वाजपेयी सरकार को झुकना पड़ा था और चर्चा के लिए सहमत होना पड़ा था। तब राज्यसभा में भैरोंसिंह शेखावत और लोकसभा में मनोहर जोशी- दोनों सदनों के सभापतियों ने पहल करते हुए दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर बुलाया और संवाद का एक फॉर्मूला तैयार करने का प्रयास किया। इसी तरह, 2जी घोटाले पर जेपीसी की भाजपा की मांग को लेकर पूरे शीतकालीन सत्र तक अड़े रहने के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने भी अंततः झुकने का निर्णय लिया था, क्योंकि वह चाहती थी कि बजट सत्र सामान्य रूप से चल सके।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

फिक्र • मजदूरों, पंचायतों, राज्यों पर संकट गहराएगा

मनरेगा के इस नए स्वरूप से किसको लाभ होने वाला है?

रोजगार

अरुणा रॉय
निखिल डे
सामाजिक कार्यकर्ता

मनरेगा रद्द होने के बाद से देश में बहस छिड़ी है। सत्ता पक्ष का दावा है कि नई योजना के माध्यम से रोजगार रोका नहीं, बल्कि गारंटी को 100 से 125 दिन किया गया है। दूसरी ओर, विपक्ष और जनसंगठन इसे मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के अधिकारों पर हमला मानते हैं। उनका कहना है कि 125 दिन की गारंटी तो दूर, रोजगार की गारंटी ही कमजोर कर दी गई है।

इस बहस का केंद्रीय प्रश्न यही है कि क्या 125 दिनों की रोजगार गारंटी के लिए पर्याप्त और प्रभावी वित्तीय व्यवस्था मौजूद है? मनरेगा में श्रम मद का 100% भुगतान केंद्र की जिम्मेदारी थी और 100 दिन तक रोजगार का सार्वभौमिक अधिकार था। जबकि वीबी-जी राम जी में एक जटिल और सीमित वित्तीय ढांचा है। इसमें पहली बार राज्यों पर बिना सलाह-मशविरे के 40% का अनिवार्य बोझ डाला गया है।

इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं, जिनमें मांग के बजाय केंद्र के निर्णयानुसार आवंटन तय होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 258 के तहत भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जब कोई केंद्रीय कानून राज्यों पर व्यय की बाध्यता डालता है तो राज्यों की सहमति जरूरी होती है। वीबी-जी राम जी में ऐसा नहीं किया गया।

यह बहस कुछ दिन चलेगी, लेकिन 26 करोड़ पंजीकृत मनरेगा परिवारों के सामने रोजगार की चिंता तत्काल है। इसी संदर्भ में चार प्रश्न महत्वपूर्ण हैं : (1) किन क्षेत्रों को वीबी-जी राम जी योजना के लिए अधिसूचित किया जाएगा; (2) राज्यों को कितना मानक आवंटन मिलेगा; (3) राज्यों के बजट पर क्या असर पड़ेगा; और (4) राज्यों को कितना अतिरिक्त बोझ उठाना होगा।

उम्मीद थी कि वित्त मंत्री स्पष्ट करेंगी कि हर राज्य का हिस्सा क्या होगा, योजना कब शुरू होगी और देश का कितना भाग अधिसूचित किया जाएगा। लेकिन यह स्पष्टता नहीं मिल सकी है।

कानून की धारा 5(1) केंद्र को शक्ति देती है कि वह तय करे कि 125 दिनों की गारंटी किन क्षेत्रों में लागू होगी। यानी, जो क्षेत्र आज शामिल है, वह भविष्य में बाहर हो सकता है।

मान लें कि पहले वर्ष पूरे ग्रामीण भारत को अधिसूचित कर दिया जाए, तब भी 125 दिनों का दावा भ्रमपूर्ण है। मनरेगा में सक्रिय श्रमिकों को औसतन 60 दिनों से अधिक काम कभी नहीं मिला। 2024-25 में औसत लगभग 50 दिन रहा। गणना स्पष्ट है : लगभग 9 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड परिवारों को 125 दिन का रोजगार देने के लिए प्रतिदिन 375 रुपए की औसत लागत के अनुसार लगभग 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए। इसके विपरीत बजट में अनुमानित कुल व्यय लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए है। इसमें राज्यों का 40% हिस्सा भी शामिल है। यदि 375 रुपए प्रतिदिन मानें तो लगभग 8.65 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड धारकों को प्रति परिवार केवल 46 दिन का ही काम मिल पाएगा।

बजट से यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि किस राज्य को कितना आवंटन मिलेगा और किसे कितना अतिरिक्त जुटाना होगा। राज्य संसाधन नहीं जुटा पाए तो रोजगार में गिरावट का दोष उन्हीं पर डाला जा सकता है। जबकि कई राज्यों में पहले से ही वित्तीय संकट है और इतनी बड़ी राशि जुटाना उनके लिए कठिन है।

मनरेगा पूरी दुनिया में गरीब मजदूरों को हक और जीने का आधार देने की एक मिसाल था। उसे रद्द करके एक ऐसा कानून लाया गया है, जो शायद वित्तीय उलझनों से उबर नहीं पाएगा। बजट से भी इसको लेकर स्पष्टता नहीं आई है।

केंद्रीय बजट के बाद भी वीबी-जी राम जी के वित्तीय प्रावधानों को लेकर सवालों के जवाब नहीं मिले। इतना तो स्पष्ट है कि 125 दिन की सार्वभौमिक रोजगार गारंटी एक खोखला वादा है। रोजगार अधिकार को जिस जटिल वित्तीय व्यवस्था में उलझाया गया है, उससे मजदूरों, पंचायतों और राज्यों पर संकट गहराएगा। मनरेगा पूरी दुनिया में गरीब मजदूरों को हक और जीने का आधार देने की एक मिसाल था। उसे रद्द करके एक ऐसा कानून लाया गया है, जो शायद वित्तीय उलझनों से उबर नहीं पाएगा।

(ये लेखकों के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • मातृत्व का अर्थ अपनी इच्छाओं, आत्मसम्मान या पहचान को खत्म कर देना नहीं होता...

जन्म देने वाली महिलाओं को कैसे देखें- बिना उनसे नजरें फेरे?

फेमिनिज्म

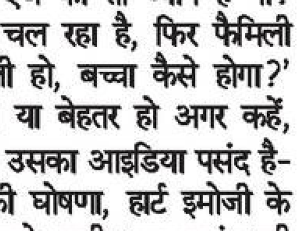

मेघना पंत
पुरस्कृत लेखिका, पत्रकार-वक्ता
meghnapant@yahoo.com

'कब प्रेग्नेंट होओगी तुम? एज का तो ध्यान है ना? करियर तो तुम्हारा ठीक ही चल रहा है, फिर फैमिली कब बनाओगी? इतनी पतली हो, बच्चा कैसे होगा?' समाज को प्रेग्नेंसी पसंद है। या बेहतर हो अगर कहें, समाज को प्रेग्नेंसी से बढ़कर उसका आइडिया पसंद है- उसका अमूर्त स्वरूप, उसकी घोषणा, हार्ट इमोजी के साथ वॉट्सएप ग्रुप में भेजी जाने वाली अल्ट्रासाउंड की फोटो। जैसे ही किसी स्त्री का विवाह होता है, उस पर दबाव बनाया जाने लगता है- गुड न्यूज कब दे रही हो? डॉक्टर उसे इशारों में बार-बार याद दिलाते हैं, इर्द-गिर्द मंडराते रिश्तेदार पूछताछ करने लगते हैं। पूरा समाज तय डेडलाइन वाले किसी पब्लिक-प्रोजेक्ट की तरह उसे बताता रहता है कि जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ।

और इसके बावजूद, जैसे ही प्रेग्नेंसी दिखने लगती है- असली, शारीरिक तौर पर फैलती हुई- तो हम असहज हो जाते हैं। दिल्ली में सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी ड्रेसिंग को लेकर हुए विवाद से यह फिर सामने आया। सामने एक गर्भवती स्त्री थी, जो अपने आराम, आत्मविश्वास या शायद खुशी के लिए कपड़े पहने हुए थी। और अचानक से समाज के सुर बदल गए- शालीन रहो, इसे ढककर रखो, एक होने वाली मां को ऐसा नहीं दिखना चाहिए...।

महिलाओं को ऐसे ही विरोधाभास में फंसाया गया है। उनसे मां बनने की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन जैसे ही वे मां बनीं, समाज उनसे अपनी हस्ती को ही मिटाने की मांग करने लग जाता है। हम मातृत्व को आदर्श मनाते हैं, लेकिन असल मातृत्व आकार लेने लगे तो हम उस पर लोक-लाज के पहरे बैठा देते हैं। हमें कोख चाहिए, स्त्री नहीं। त्याग चाहिए, व्यक्ति नहीं। बच्चा चाहिए, लेकिन उस शरीर की हमें परवाह नहीं है- जिसने दर्द, फैलाव और बदलावों को झेलकर उसे जन्म दिया।

गर्भवती देह अपने स्वरूप को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करे तो यह बात हमें बेचैन करती है। वह फैलती है, नजरों में आती है और अपने लिए आराम, खाना और ध्यान मांगती है। वह शांत नहीं रहती। इसीलिए समाज उसे अनुशासित करने दौड़ पड़ता है- कभी सलाह या निर्णय के नाम पर तो कभी नैतिकता का बोझ डालकर।

कोई गर्भवती महिला अपनी खुशी के लिए कपड़े पहने तो यह हमें याद दिलाता है कि मातृत्व का अर्थ अपनी इच्छाओं, आत्मसम्मान या पहचान को खत्म कर देना नहीं होता। गर्भवती महिला पूरी तरह एक जीवित मनुष्य है, दमकती हुई, किंतु थोड़ी-सी जटिल। लेकिन समाज नहीं जानता कि बिना किसी घबराहट इसे कैसे स्वीकारा जाए।

हमें मातृत्व का एक साफ-सुथरा, आदर्श रूप पसंद है- पवित्र, काम-भावना से रहित और हमेशा दानी बना रहने वाला। लेकिन जैसे ही कोई महिला खुद को देखकर कहती है कि मुझे अब भी अपने जैसा ही दिखना है तो खतरे की घंटी बज उठती है। यह कि- तुम इसे एंजॉय कैसे कर सकती हो? तुम अब भी पहले जैसी दिखने के बारे में कैसे सोच सकती हो?

गर्भावस्था महिलाओं को छोटा नहीं बनाती, बल्कि वह उन्हें और अधिक दृश्यमान बना देती है। यही विजिबिलिटी उनके लिए खतरा है। हम उन्हें शर्मिंदा करते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं और इस उम्मीद में उन पर नियंत्रण की कोशिश करते हैं कि वे फिर से स्वीकार्य अदृश्यता में चली जाएं। अगर हम सच में ही होने वाली मांओं का सम्मान करते, तो हम उन्हें नजर आने देते। उन्हें आराम, खुशी और आत्मविश्वास के लिए अपनी पसंद के कपड़े पहनने देते। उन्हें खूबसूरत महसूस करने देते। गर्भावस्था शर्मिंदगी की चीज नहीं है। यदि समाज इतनी शिद्दत से बच्चे चाहता है तो उसे यह भी सीखना होगा कि उन्हें जन्म देने वाली महिलाओं को कैसे देखा जाए- बिना उनसे नजरें फेरे। **(ये लेखिका के अपने विचार हैं)**

ग्लोबल फैमिली बिजनेस सर्वे

विस्तार में सबसे आगे भारतीय फैमिली कारोबार, 91% आगामी वर्षों में बिजनेस बढ़ने की उम्मीद कर रहे, दुनिया में ऐसी कंपनियां 73%

55% भारतीय फैमिली बिजनेस 2 साल में आक्रामक विस्तार करेंगे, पर उत्तराधिकार का संकट

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

भारतीय फैमिली बिजनेस उत्तराधिकार और गवर्नेंस के मामले में कुछ कमजोरियों के बावजूद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। पीडब्ल्यूसी का 'ग्लोबल फैमिली बिजनेस सर्वे' दुनियाभर की 1,325 कंपनियों के बीच कराया गया। इसमें शामिल 40 भारतीय कंपनियों में से 91% अगले दो साल में बिजनेस बढ़ने की उम्मीद कर रही हैं, जबकि वैश्विक औसत 73% है। खास तौर पर 55% भारतीय कंपनियां अगले 2 साल में आक्रामक विस्तार की योजना बना रही हैं, जबकि पूरी दुनिया में ऐसी कंपनियां औसतन 16% ही हैं। दुनियाभर में कई फैमिली बिजनेस भू-राजनैतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण विस्तार योजनाएं टाल रहे हैं।

मजबूती: 73% भारतीय फैमिली बिजनेस टेक्नोलॉजी की उन्नति को मौका मान रहे

अनुमान/नजरिया	भारत	वैश्विक
अगले 2 वर्षों में वृद्धि की उम्मीद	91%	73%
आक्रामक विस्तार की योजना	55%	16%
तकनीकी उन्नति को मौका मानना	73%	---
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्राथमिकता	39%	24%

- वैश्विक स्तर पर सिर्फ 25% कंपनियां ही 10% से ज्यादा ग्रोथ हासिल कर पाईं। दिलचस्प है कि सिर्फ दो साल पहले यह आंकड़ा 43% था।
- दो पहले के मुमाबले रफ्तार आधी रह जाने के बावजूद भारत के फैमिली बिजनेस डिजिटल, नए बाजार और विविधीकरण पर दांव लगा रहे हैं।

कमजोरी: बोर्ड में एक जैसे सदस्यों के चलते विविधता, विशेषज्ञता की कमी

भारतीय फैमिली बिजनेस में बोर्ड विविधता वैश्विक औसत से कम है, जो गवर्नेंस के मामले में कमजोरी का संकेत है। इससे मैनेजमेंट में विविधता और विशेषज्ञता की कमी आती है।

कमजोर पक्ष	भारत	वैश्विक
बोर्ड में महिला सदस्य नहीं	42%	32%
क्रॉस-इंडस्ट्री प्रतिनिधित्व की कमी	50%	29%
औसत बोर्ड साइज	6.6 सद.	5 सदस्य

(स्रोत: पीडब्ल्यूसी का 12वां ग्लोबल फैमिली बिजनेस सर्वे)

सेल्फ फाइनेंस: 85% बिजनेस मुनाफे से ही फंडिंग करते हैं

- फैमिली बिजनेस पारंपरिक रूप से लंबी अवधि के निवेश पर जोर देते हैं। 85% फर्म्स इनोवेशन फंडिंग के लिए मुनाफे का दोबारा निवेश करती हैं।
- 75% फर्म्स निकट-अवधि के नतीजों और लॉन्ग-टर्म लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाती हैं, जबकि केवल 25% शॉर्ट-टर्म अप्रोच अपनाती हैं।
- ऊंची ग्रोथ वाले 78% भारतीय फैमिली बिजनेस मुख्य कारोबार मजबूत करने पर जोर देते हैं, वैश्विक स्तर पर ये आंकड़ा 67% है।
- भारतीय फैमिली बिजनेस की लीडरशिप डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करती हैं। इनका ये रवैया नहीं बदला है।

फैमिली बिजनेस में स्पष्ट साझा उद्देश्य जरूरी

जिन फैमिली बिजनेस में साझा उद्देश्य स्पष्ट होता है वे बेहतर रणनीतिक फोकस रखते हैं। यह मॉडल तेज फैसले करने में मदद करता है। प्रदर्शन अब सिर्फ ग्रोथ या इनोवेशन से नहीं, बल्कि बड़े मिशन से मापा जाता है। अनिश्चितता बढ़ने पर मजबूत उद्देश्य और भी जरूरी हो जाता है। **-मैट एलन,** प्रोफेसर ऑफ फैमिली एंटरप्राइजेज, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट

चुनौती: 36% भारतीय फैमिली बिजनेस के पास स्पष्ट उत्तराधिकार योजना नहीं

विस्तार के मामले में आक्रामकता तब देखी जा रही है, 36% भारतीय फैमिली बिजनेस के पास स्पष्ट उत्तराधिकार योजना नहीं है, जो 28% के वैश्विक औसत से ज्यादा है।

बड़े मसले	भारत	वैश्विक
स्पष्ट उत्तराधिकार योजना की कमी	36%	28%
नई पीढ़ी को मैनेजमेंट ट्रांसफर का विरोध	52%	29%
अनिश्चितता से उत्तराधिकार में देरी	21%	10%
बोर्ड में सिर्फ परिवार के सदस्य	30%	---

बिजनेस ब्रीफ

अमेरिका-बांग्लादेश डील से भारत को नुकसान नहीं

नई दिल्ली | अमेरिका-बांग्लादेश ट्रेड डील से भारतीय कपड़ा बाजार को नुकसान नहीं होगा। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार, अमेरिका की जीरो-ड्यूटी पॉलिसी केवल बांग्लादेश के लिए नहीं है। जो भी देश 20% अमेरिकी कच्चे माल का उपयोग करेगा, उसे यह छूट मिलेगी। भारत अपनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के कारण इस नियम का अधिक फायदा उठा सकता है।

इंडिगो ने लागू किए नए पायलट नियमः डीजीसीए

नई दिल्ली | इंडिगो ने विमानन नियामक डीजीसीए को सूचित किया है कि उसने पायलटों के लिए नए ड्यूटी नियम (एफडीटीएल) पूरी तरह लागू कर दिए हैं। नियामक ने पुष्टि की है कि 10 फरवरी को मिली छूट खत्म होने के बाद अब सभी ऑपरेशन मानकों के तहत हैं। रात की ड्यूटी और लैंडिंग के कड़े नियमों से अब पायलटों को थकान नहीं होगी।

फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ तीन गुना भरा

मुंबई | फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ बुधवार को अंतिम दिन शाम 6 बजे तक 2.8 गुना सब्सक्राइब हुआ। 2,834 करोड़ रुपए के आईपीओ के तहत कंपनी ने 1.76 करोड़ शेयर बेच रही है। निवेशकों ने 4.95 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां लगाई। क्यूआईबी के लिए रिजर्व हिस्सा सबसे अधिक 4.41 गुना भरा। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.10 गुना सब्सक्राइब हुआ।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अब तक 9.40% बढ़ा

नई दिल्ली | वित्त वर्ष 2025-26 में 10 फरवरी तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.43 लाख करोड़ हो गया। यह पिछले साल की समान अवधि में कलेक्शन से 9.4% ज्यादा है। इस दौरान ग्रॉस कलेक्शन 23.37 लाख करोड़ रहा, जिसमें से 3.94 लाख करोड़ रिफंड कर दिए गए। इस बीच कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में भी 10.3% बढ़ोतरी हुई।

सर्वम एआई ने ग्लोबल मॉडल्स को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली | भारतीय स्टार्टअप सर्वम एआई ने दावा किया है कि उसका मॉडल इंडिक भाषाओं के बेंचमार्क पर ओपनएआई के जीपीटी-4, गूगल जेमिनाई और एंथ्रॉपिक के क्लाउड जैसे बड़े ग्लोबल मॉडल्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी ने कहा कि उसका मॉडल हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली सहित कई भारतीय भाषाओं में अधिक सटीक है।

नए नियम • सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही सेल्स कॉल, गलत बिक्री पर रिफंड अनिवार्य

लोन के साथ बीमा, म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट जबरन नहीं बेच सकेंगे बैंक

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

बैंक और गैर-बैंकिंग कंपनियां (एनबीएफसी) अब लोन के साथ बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट्स जबरन नहीं बेच सकेंगे। दरअसल, आरबीआई ने मिस-सेलिंग रोकने के लिए बुधवार को नए नियमों का मसौदा जारी किया। इसमें डार्क पैटर्न, जबरन बंडलिंग और बिना सहमति के बिक्री पर सख्त रोक लगाई गई है।

यह ड्राफ्ट सभी रेगुलेटेड एंटिटी यानी सामान्य कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर लागू होगा। हालिया मसौदे पर चार मार्च तक मिले सुझावों पर गौर करने के बाद अंतिम नियम जारी होंगे। इसी साल एक जुलाई से नियम लागू होने पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बिक्री के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव नजर आएगा।

जुलाई से नए नियम लागू होने पर ये 5 बदलाव होंगे

1. **जबरन बंडलिंग पर रोकः** कोई भी बैंक लोन जैसे अपने प्रोडक्ट के साथ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड जैसे थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट जोड़कर नहीं बेच सकेंगे।
2. **सहमति जरूरीः** एक साथ कई प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहक से कंसेंट नहीं ली जा सकेगी। सभी प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग सहमति लेनी जरूरी होगी।
3. **डार्क पैटर्न बंदः** एप/वेबसाइट पर आम लोगों को गुमराह करने वाले डिजाइन या पहले से टिक बॉक्स जैसे तरीकों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
4. **सेल्स कॉल, विजिटः** सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही बैंक के कर्मचारी या सेल्स एग्जीक्यूटिव ग्राहक से अनुमति लेकर फोन कॉल या विजिट कर सकेंगे।
5. **फीस-चार्जः** नए नियमों के मुताबिक, बैंक और एनबीएफसी प्रशासनल मटेरियल स्पष्ट और तथ्यात्मक होना चाहिए। इनमें फीस और सभी तरह के अन्य चार्ज की स्पष्ट जानकारी होगी।

सभी बैंक, एनबीएफसी के लिए समान फ्रेमवर्क

कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट किस तरह के ग्राहक के लिए उपयुक्त है, इसके नियम सीमित संस्थाओं में थे। समीक्षा में पाया गया कि थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट्स (जैसे म्यूचुअल फंड), एजेंटों की गतिविधियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न (ग्राहकों को अंजाने में गलत निर्णय लेने के लिए उकसाना) के जरिये मिस-सेलिंग की शिकायतें बढ़ रही हैं। इसलिए सभी बैंक और एनबीएफसी के लिए एक-समान, व्यापक फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस हुई।

ये फायदे होंगेः गलत प्रोडक्ट बेचने पर पैसा वापस, मुआवजा भी मिलेगा

- **30 दिन में फीडबैक अनिवार्यः** बैंक और सभी वित्तीय संस्थाएं हर बिक्री के बाद ग्राहकों से अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया लेंगी।
- **मिस-सेलिंग पर रिफंडः** गलत या बिना सहमति के बिक्री साबित होने पर पूरा पैसा वापस करना होगा और मुआवजा देना होगा।
- **पूरी पारदर्शिताः** एजेंटों की अपडेटेड लिस्ट वेबसाइट पर देनी होगी। बैंक परिसर में वे अलग पहचान में दिखेंगे।

समर्पित एसएमई पोर्टल आएगा

एसएमई आईपीओ से जुटाई राशि की जांच

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

छोटी-मझोली कंपनियों (एसएमई) ने वित्त वर्ष 2024-25 में आईपीओ से 9,800 करोड़ और 2025-26 में 31 जनवरी तक 10,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज इनके मर्चेंट बैंकरों और प्रमोटरों की गहन जांच कर रहे हैं। इसके लिए साइट विजिट और एआई-आधारित ऑफर डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी की जा रही है, ताकि पता किया जा सके कि कहीं आईपीओ के जरिये जुटाई गई रकम का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ।

इस बीच बुधवार को बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने एसएमई प्लेटफॉर्म पर फंड डायवर्जन और मार्केट मैनिपुलेशन जैसी गंभीर घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एसएमई प्लेटफॉर्म पूंजी निर्माण के शक्तिशाली इंजन हैं, लेकिन केवल मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियों को ही सार्वजनिक बाजार में आने की अनुमति मिलनी चाहिए। सेबी ने फ्रेमवर्क मजबूत किया है, ताकि सिर्फ विश्वसनीय कंपनियां आईपीओ ला सकें। सेबी एलओडीआर नियमों की समीक्षा भी कर रहा है, ताकि अनावश्यक प्रावधान हटाए जा सकें।

अध्यादेश का असर

टाटा ट्रस्ट्सः 'लाइफटाइम मेंबर्स' पर अब लगेगा ब्रेक

मुंबई | टाटा ट्रस्ट्स के गवर्नेंस ढांचे में बड़े बदलाव के संकेत हैं। कारण यह है कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट (संशोधन) अध्यादेश 2025 में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। मसलन, बोर्ड में 25% लाइफटाइम ट्रस्टी होंगे। ट्रस्ट के दस्तावेज में कार्यकाल नहीं लिखे होने पर ट्रस्टी का कार्यकाल अधिकतम 5 साल ही माना जाएगा।

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट - एसडीटीटी

ट्रस्टी	भूमिका	कब से और क्या असर
नोएल एन टाटा	चेयरमैन, टाटा ट्रस्ट्स	साल 2022 से ही परमानेंट ट्रस्टी, एसडीटीटी में इकलौते
वेणु श्रीनिवासन	ट्रस्टी व वाइस चेयरमैन	2016 से पद पर। पहले से कार्यकाल फिक्स। 2028 तक रहेंगे ट्रस्टी।
विजय सिंह	ट्रस्टी	2018 से टर्म-बेस्ड ट्रस्टी रहे। 2024 में परमानेंट बनाना चाहा। अब फिक्स्ड टर्म कैटेगरी में माने जाएंगे।
प्रमित झावेरी	ट्रस्टी	2020 से पद पर, मौजूदा टर्म फरवरी 2026 में खत्म। इन्हें कहा है कि वे फिर ट्रस्टी नहीं बनेंगे।
डेरियस खंबाटा	ट्रस्टी	2023 से ट्रस्टी। कार्यकाल फिक्स टर्म कैटेगरी में बदलना पड़ेगा।
नेविल एन टाटा	ट्रस्टी	टेन्योर बेस्ड ट्रस्टीः 2025 से 2028 तक। पहले से ही इनका कार्यकाल फिक्स है।
भास्कर भट्ट	ट्रस्टी	टेन्योर बेस्ड ट्रस्टीः 2025 से 2028 तक। पहले से ही इनका कार्यकाल फिक्स है।

सर रतन टाटा ट्रस्ट-एसआरटीटी

एसआरटीटी 1918 की वसीयत के आधार पर संचालित होती है। कोई औपचारिक ट्रस्ट डीड नहीं। अब ट्रस्ट डीड बनाने पर विचार हो रहा है।

ट्रस्टी	रोल	क्या असर होगा
नोएल एन टाटा	ट्रस्टी	ट्रस्ट चेयरमैन के रूप में नेतृत्व
वेणु श्रीनिवासन	ट्रस्टी	कार्यकाल फिक्स करना होगा
विजय सिंह	ट्रस्टी	कार्यकाल फिक्स करना होगा
डेरियस खंबाटा	ट्रस्टी	टर्म-बेस्ड टेन्योरः पहले से ही फिक्स
जिमी एन टाटा	ट्रस्टी	कार्यकाल फिक्स करना होगा
जहांगीर एचसी	ट्रस्टी	कार्यकाल फिक्स करना होगा

दोनों प्रमुख ट्रस्ट... मिलकर टाटा संस में लगभग 52 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं। यह बड़ी बात इसलिए है कि टाटा संस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है।

बाजार • आईआरसीटीसी MSCI इंडेक्स से बाहर

बिड़ला कैपिटल और एलएंडटी फाइनेंस अब ग्लोबल इंडेक्स में

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर एमएससीआई ने अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में आदित्य बिड़ला कैपिटल और एलएंडटी फाइनेंस को शामिल किया है। वहीं, सरकारी कंपनी आईआरसीटीसी को इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद इंडेक्स में भारतीय कंपनियों की संख्या 164 से बढ़कर 165 हो गई है, हालांकि भारत का वेटेज 14.1% पर स्थिर रहेगा। नुवामा रिसर्च के मुताबिक, शामिल कंपनियों में करीब 4,490 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जबकि आईआरसीटीसी से 1,284 करोड़ रुपए की निकासी हो सकती है। इंडेक्स में शामिल होने से इन शेयरों की ग्लोबल साख बढ़ेगी।

स्मॉल कैप इंडेक्स से 28 कंपनियां हटीं, 7 नई जुड़ीं

ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में भारतीय कंपनियां 508 से घटकर 480 रह गई। दिलीप बिल्डकॉन और स्टरलाइट टेक जैसी 28 कंपनियां हटाई गई हैं। प्रीमियर एनर्जीज, जेएसडब्ल्यू सीमेंट समेत 7 नई कंपनियों ने जगह बनाई है।

एसबीआई चौथी मूल्यवान कंपनी, टीसीएस को पछाड़ा

एसबीआई ने टीसीएस को पांचवें नंबर पर धकेलकर देश की चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है। शेयर चढ़ने से एसबीआई का मार्केट कैप 10.92 लाख करोड़ हो गया, जबकि टीसीएस मार्केट कैप 10.53 लाख करोड़ रुपए रह गया।

आईटी-टेक में बिकवाली से सेंसेक्स, निफ्टी फ्लैट

सेंसेक्स बुधवार को 40 अंक गिरकर 84,234 और निफ्टी 18 अंक चढ़कर 25,954 पर बंद हुआ। बाजार फ्लैट रहने की मुख्य वजह आईटी और टेक शेयरों में भारी बिकवाली रही। वैश्विक स्तर पर एआई को लेकर उथल-पुथल से बीएसई का फोकस्ड आईटी और आईटी इंडेक्स 1.7% टूट गया। हालांकि, एसबीआई, मारुति, रिलायंस जैसे ब्लूचिप शेयरों में तेजी से बाजार की बड़ी गिरावट टल गई।

लागत • विदेशी टैलेंट ही चुनेंगी अमेरिकी कंपनियां, कम वेतन आकर्षक

91 लाख फीस भी कम, एच-1बी महंगा होने पर भी अमेरिका में नहीं रुकेंगी भारतीयों की भर्तियां

सुरभि ग्लोरिया सिंह | नई दिल्ली

एच-1बी वीसा की फीस 1 लाख डॉलर (करीब 90.70 लाख रुपए) होने पर भी मांग कम नहीं होगी। अगर यह फीस 2 लाख डॉलर (करीब 1.81 करोड़ रुपए) भी कर दी जाए, तो भी कंपनियां भारतीय जैसे विदेशी टैलेंट चुनेंगी। अमेरिका के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (एनबीईआर) की ताजा स्टडी में यह दावा किया गया है। अर्थशास्त्री जॉर्ज बोरजास की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका मुख्य कारण वेतन का बड़ा अंतर है। कंपनियां अमेरिकी मूल के कर्मचारी के मुकाबले एक औसत एच-1बी कर्मचारी को 16% कम सैलरी पर काम पर रखती हैं। कंपनियां 6 साल के वीसा पीरियड में प्रति कर्मचारी 1 लाख डॉलर बचाती हैं।

मेटा-एपल में सैलरी 1.4 करोड़, इन्फोसिस में 72 लाख

बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों और भारतीय आईटी कंपनियों के पे-स्केल में बड़ा अंतर है। मेटा और एपल जैसी कंपनियां एच1बी वीसा पेशेवर को 1.5 लाख डॉलर (करीब 1.36 करोड़ रुपए) तक वेतन देती हैं। इसके उलट, इन्फोसिस, विप्रो जैसी भारतीय कंपनियों में यह 80 हजार डॉलर (करीब 72.56 लाख रुपए) के आसपास है। यहां वेतन का अंतर बहुत ज्यादा है।

महज 1.4 सेकंड में कार पकड़ लेती है 100 किमी/घंटे की रफ्तार

लंदन | दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक हाइपरकार 'मैकमर्ट्री स्पियरलिंग' प्रोडक्शन जल्द शुरू होने जा रहा है। इसी साल गर्मियों से ग्राहकों को इसकी डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। यह कार महज 1.4 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है।
कीमतः सिंगल सीटर इस कार की कीमत 12.3 करोड़ रुपए है।

रणनीति • फाइनेंशियल, आईटी से बनाई दूरी

विदेशी फंड्स ने मेटल शेयरों में 11,526 करोड़ रुपए लगाए

जतिन भूटानी | मुंबई

भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। जनवरी 2026 में इन निवेशकों ने बाजार से कुल 33,336 करोड़ रुपए की निकासी की है। अगस्त 2025 के बाद यह एक महीने में बिकवाली का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

ब्रोकरेज फर्म पीएल कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 से ही विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इस दौरान केवल अक्टूबर 2025 में ही नेट निवेश देखा गया था। जनवरी की गिरावट में सबसे ज्यादा मार डिफेंस, आईटी और कंजंप्शन से जुड़े शेयरों पर पड़ी है। हालांकि इस बिकवाली के बीच विदेशी निवेशकों ने मेटल और माइनिंग सेक्टर पर भरोसा जताया है।

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेशी निवेशक अब डिफेंसिव और फाइनेंशियल शेयरों से पैसा निकालकर साइक्लिकल सेक्टर्स में शिफ्ट हो रहे हैं।

ट्रेंडः माइनिंग कंपनियों के शेयर भी अब पसंदीदा

जनवरी में मेटल और माइनिंग सेक्टर विदेशी निवेशकों की सबसे बड़ी पसंद बनकर उभरा। इस सेक्टर में विदेशी निवेशकों ने 11,526 करोड़ रुपए नेट निवेश किए। यह राशि दिसंबर 2025 के 2,984 करोड़ रु. के मुकाबले करीब चार गुना अधिक है। मेटल सेक्टर में खरीदारी अब अपने लंबे समय के औसत स्तर को भी पार कर गई है।

दबावः एफएमसीजी से 7,497 करोड़ की निकासी

आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले एफएमसीजी सेक्टर में जनवरी में 7,497 करोड़ रुपए की निकासी हुई। यह पिछले साल की समान अवधि और दिसंबर 2025 की बिकवाली से कहीं ज्यादा है। हेल्थ सर्विसेज में भी निकासी की रफ्तार बढ़ी है और यह 6,162 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। विदेशी निवेशक कंज्यूमर सर्विसेज से भी 5,513 करोड़ रु. निकाल चुके हैं।

बिजनेस एंकर **दिलचस्प •** निवेश के लिए लिस्टेड कंपनियां बेहतर, प्रदर्शन दे रहे इसकी गवाही

गैर-लिस्टेड कंपनियां आय में लिस्टेड फर्म्स से पीछे

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

देश के लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद है। वजह साफ है। सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में 3,175 गैर-लिस्टेड कंपनियों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (पैट) कुल आय का 5.75% रहा। यह पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। दूसरी तरफ इसी अवधि में 3,973 लिस्टेड कंपनियों का पैट मार्जिन 8.11% रहा। यह अंतर इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि बीते वित्त वर्ष गैर-लिस्टेड कंपनियों की बिक्री 8.62% बढ़ी, जबकि लिस्टेड कंपनियों की सिर्फ 5.1% बढ़ पाई।

एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों को चढ़ते शेयर बाजार का अतिरिक्त लाभ

लिस्टेड कंपनियों को ज्यादा कमाई के तीन बड़े कारण

भास्कर एक्सपर्ट

जी. चोक्कालिंगम
एमडी, इक्विनॉमिक्स रिसर्च

1. भारतीय शेयर बाजार में कई साल से मोटे तौर पर तेजी रही है। ऐसे में लिस्टेड कंपनियों को लागत कम करने और अतिरिक्त कमाई निकालने में सहूलियत होती है क्योंकि हर अतिरिक्त रुपए से वैल्यूएशन में बड़ा उछाल आता है।
2. लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर हर अतिरिक्त कमाई के लिए लागत कम करने और इंक्रीमेंटल अर्निंग्स निकालने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे लिस्टेड फर्मों में पूंजी लागत का बेहतर इस्तेमाल होता है।
3. बाहरी शेयरधारक ज्यादा होने से लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटरों पर मार्जिन बढ़ाने का अतिरिक्त दबाव बना रहता है। गैर-लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटरों पर ऐसा कोई दबाव नहीं होता।

गैर-लिस्टेड कंपनियों को इसलिए कम होती है आय

गैर-लिस्टेड कंपनियों में प्रमोटर यदि 100 करोड़ रुपए कमाए, तो संपत्ति सिर्फ उतनी ही बढ़ती है। लेकिन कोई लिस्टेड कंपनी 100 करोड़ रुपए कमाए, तो उसका वैल्यूएशन 1,000 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लिस्टेड कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी कमाई के मल्टीपल (गुणक) पर ट्रेड करती हैं।

रणनीतिक लाभः कम कर्ज से कम ब्याज खर्च

- एक इटालियन स्टडी कहती है कि लिस्टेड कंपनियां तेज ग्रोथ करती हैं। ये कम कर्ज का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में ब्याज पर खर्च का अनुपात कम रहता है। इसीलिए मार्जिन गैर-लिस्टेड कंपनियों से बेहतर रहता है।
- इक्विनॉमिक्स रिसर्च का अनुमान है कि जीएसटी में कटौती से डिमांड बढ़ेगी। इससे आगामी तिमाहियों में सभी कंपनियों की आय बढ़ेगी। लेकिन लिस्टेड कंपनियों का इंसेंटिव स्ट्रक्चर उन्हें आगे रखेगा।

रोल्स-रॉयस सीईओ की पीएम मोदी से मुलाकात

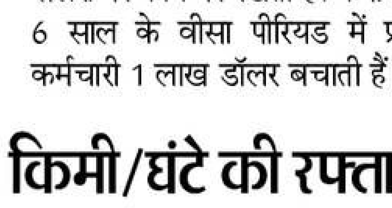

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

रोल्स-रॉयस भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने जा रही है। इस योजना को साझा करने के लिए कंपनी के सीईओ तुफान एर्गिनबिल्जिक ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में 'विकसित भारत' लक्ष्य में रोल्स-रॉयस की भागीदारी और विस्तार पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को शानदार बताते हुए कंपनी के उत्साह का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत के इनोवेटिव और ऊर्जावान युवा इस साझेदारी में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

वंदे मातरम्

राष्ट्रगीत *वंदे मातरम्* की प्रतिष्ठा और प्रयोग का बढ़ना स्वागतयोग्य है। वंदे मातरम् के 150वें वर्ष में केंद्रीय गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि तमाम आधिकारिक अवसरों पर *वंदे मातरम्* का 3 मिनट 10 सेकंड का छह छंदों वाला संस्करण बजाया या गाया जाए। निर्देश में यह भी उल्लेख है कि राष्ट्रगीत से पहले राष्ट्रगान होगा और सभी श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़ा होना पड़ेगा। सामान्य तौर पर सरकारी कार्यक्रमों में यह अनिवार्यता रहेगी। सिनेमा हॉल में यह निर्देश लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय का यह निर्देश पूरे देश में लागू हो गया है और कुछ ही महीनों में व्यावहारिक रूप से राष्ट्रगीत की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। अपने देश में राष्ट्रगान तो लगभग सभी को याद है, पर राष्ट्रगीत भी अब जुबान पर चढ़ने वाला है। अभी तक राष्ट्रगीत की अनिवार्यता नहीं थी और कहीं-कहीं ही यह सुनाई पड़ता था। राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा बदलाव है, जिसका असर समाज और भारतीयों के व्यक्तित्व पर पड़ना तय है।

यह बात विगत दिनों ही साफ हो गई थी कि सरकार *वंदे मातरम्* को लोकप्रिय बनाना चाहती है। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृतनिष्ठ बांग्ला में 1870 के दशक में रचित इस गीत को सर्वप्रथम स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा मातृभूमि की प्रशंसा के लिए अपनाया गया था। साल 1950 में गीत के पहले दो छंदों को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। गीत का यही संक्षिप्त संस्करण ज्यादा उपयोग में आता रहा है। अब गीत का विस्तारित छह-छंद वाला संस्करण आधिकारिक कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। यह एक साहसिक फैसला है। यह गीत मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाने के लिए विख्यात रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी अतुलनीय भूमिका रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि *वंदे मातरम्* जैसे भावपूर्ण गीत की जरूरत देश को है और जो गीत आजादी की लड़ाई में हमारे काम आया था, उसका उपयोग हमें आगे भी जारी रखना चाहिए। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, दोनों को पूरा करने में चूंकि पांच मिनट से भी कम समय लगेगा, इसलिए इनकी जोड़ी लोकप्रिय हो जाएगी। हालांकि, इन गीत या गान के भाव को समझना ज्यादा जरूरी है। वैसे, राष्ट्र को इसका यथोचित लाभ तभी मिलेगा, जब यह फैसला सिद्धांत तक सीमित न रहे, बल्कि व्यावहारिकता में राष्ट्र भाव को प्रेरित करे। अपने देश में तेज विकास, स्थिरता, वास्तविक लोकतंत्र, प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए राष्ट्र भाव बहुत जरूरी है।

अपने देश में राष्ट्रगान 'जन गण मन' तो लगभग सभी को याद है, पर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' भी अब जुबान पर चढ़ने वाला है। देश प्रेम बढ़ाने वाले इस गीत की जरूरत है।

सरकारी कार्यक्रमों में *वंदे मातरम्* को अनिवार्य किया गया है, तो सरकारी कामकाज के प्रति भी लोगों की शिकायतों में कमी आनी चाहिए। ध्यान रहे, 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत 93वें स्थान पर था। सरकार में भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे 89 प्रतिशत भारतीय एक बड़ी समस्या मानते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 जैसे कड़े कानून के बावजूद पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो पाई है। भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर सार्वजनिक सेवाओं और विकास पर पड़ा है। ताजा आंकड़ों को देखें, तो बीते पांच वर्ष में धन शोधन के पांच हजार से ज्यादा मामलों में ईडी ने जांच या कार्रवाई की है। सैकड़ों आला अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। दागी नेताओं की भी भरमार है। दो लाख से ज्यादा भारतीय प्रतिवर्ष अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। भारत में पैसे कमाना और कहीं विदेश में बसने का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में, यह उम्मीद हम कर सकते हैं कि *वंदे मातरम्* जैसा जीवंत गीत हम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम बढ़ाएगा।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

12 फरवरी, 1951

पिलानी का शिक्षा-केन्द्र

पिलानी राजस्थान का सुपरिचित शिक्षा-केन्द्र है। इस केन्द्र को स्थापित हुए आधी शताब्दी बीत चुकी है और यह अपनी स्वर्ण जयन्ती मना रहा है। इस शिक्षा-केन्द्र की शुरुआत एक छोटी-सी पाठशाला के रूप में हुई थी, किन्तु उसने अब विशाल रूप धारण कर लिया है। उससे न केवल राजस्थान के बल्कि दूर दूर के विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। पिलानी में जिस बिड़ला विद्या-प्रहार का उद्घाटन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने किया, उसमें अब तक सात लाख वर्गफुट के भवन बनाये जा चुके हैं और निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का व्यय आवश्यक होगा। पिलानी शिक्षा-केन्द्र में इस समय कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा इंजीनिरिंग के 4 कालेज, दो हाई-स्कूल- एक बालकों का तथा दूसरा बालिकाओं का, एक मॉन्टेसरी स्कूल तथा 9 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, जिनमें 3,200 विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। इसके अलावा, इस केन्द्र द्वारा आसपास के क्षेत्र में 75 ग्राम पाठशालायें और चलाई जाती हैं, जिनमें 4 हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। इस शिक्षा-केन्द्र की स्थापना, विकास और संचालन का श्रेय बिड़ला परिवार को है।

राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा है कि यह एक परिवार के विद्या-प्रेम और कौशल का फल है, जिसे देखकर कोई भी चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकता। मरुभूमि के एक निर्जन स्थान में उच्च शिक्षा का प्रबन्ध और उसके लिए सभी आधुनिक सुविधाओं को जुटाना आसान काम नहीं था। किन्तु बिड़ला परिवार ने पिलानी की मरुभूमि को हरियाली में बदल दिया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि अगर ईश्वर धन दे तो उसका उपयोग इसी प्रकार के पुण्य कृत्यों में होना चाहिये।

बिड़ला शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री धनश्यामदासजी ने अपने भाषण में उन आलोचनाओं का जिक्र किया है, जो मौजूदा शिक्षा-प्रणाली की इन दिनों की जाती है। उनका यह कहना सही है कि ऐसी आलोचनायें कुछ मदद नहीं देतीं। जब शक्ति हमारे हाथ में नहीं थी, तब ऐसी आलोचनाओं का कुछ मूल्य था। किन्तु अब शक्ति हमारे हाथ में आ चुकी है, तब आलोचना करने के बजाय यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम जिस शिक्षा-प्रणाली को दोषपूर्ण समझते हैं, उसको बदल दें और अपनी मनपसन्द प्रणाली प्रचलित करें, जो राष्ट्र की आज की आवश्यकताओं को भली प्रकार पूरा कर सके।

बोलने ही नहीं, सोचने की भी आजादी हो

यहां स्कैन करें
मनोज कुमार झा | राज्यसभा सदस्य

एक सांविधानिक लोकतंत्र में नैतिकता का विस्तार सभी नागरिकों तक होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं तक नहीं, जो हमारी जाति, धर्म, क्षेत्र या उपनाम साझा करते हों।

इन दिनों हमारे सार्वजनिक जीवन में एक अभूतपूर्व अपेक्षा का पोषण हो चला है कि राजनीतिक विचार उपनामों से तय होने चाहिए। नागरिकता को गौण मान लिया जाता है और राजनीतिक विवेक को पारिवारिक पहचान से विरासत में मिला हुआ समझा जाता है। इस दृष्टि में 'उपनाम' एक पूर्व निर्धारित पटकथा बन जाता है। जो उससे हटता है, उसे स्वतंत्र सोच नहीं, बल्कि विश्वासघात के रूप में देखा जाता है। ऐसे में, तर्कपूर्ण असहमति नहीं, बल्कि अपमान सामने आता है। यह सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं है; यह सांविधानिक स्वायत्तता के प्रति गहरे असहज भाव को दर्शाती है। लोगों को सबसे अधिक विचलित यह बात नहीं करती कि कोई असहमत है, बल्कि यह करती है कि कोई प्राथमिक राजनीतिक कसौटी के रूप में संविधान को चुनता है, न कि वंश या पहचान को।

भारत की सांविधानिक कल्पना इसी तर्क को तोड़ने के लिए गढ़ी गई थी। संविधान नागरिकों को उनके उपनाम, कुल या विरासत में मिली निष्ठाओं से नहीं पहचानता, वह समान नैतिक संस्था की भाषा बोलता है। वह यह मानकर चलता है कि लोग उस सामाजिक पहचान से स्वतंत्र होकर नैतिक चिंतन और राजनीतिक निर्णय लेने में सक्षम हैं, जिसमें वे जन्म लेते हैं। इस स्वायत्तता को नकारना, सांविधानिक नागरिकता की आत्मा को रिक्त कर देना है। फिर भी, समकालीन विमर्श में पहचान को अनुशासनात्मक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

इन दिनों राजनीतिक असहमति को सामुदायिक कर्तव्य से विचलन के रूप में पेश किया जाता है। तर्क की जगह संकेत और आरोप ले लेते हैं; समझाने की जगह निगरानी आ जाती है। अब यह नहीं पूछा जाता कि आप क्या सोचते हैं या क्यों, बल्कि यह पूछा जाता है कि आप किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य हैं? यह एक गहरी असांविधानिक प्रवृत्ति है, जो नागरिकों को कल्पित बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि बना देती है और राजनीति को विचारों की प्रतिस्पर्द्धा के बजाय निष्ठाओं की जनगणना में बदल देती है।

सांविधानिक लोकतंत्र एक अतिव्यापी सर्वसम्मति पर निर्भर करता है- अर्थात विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के नागरिकों का न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे साझा मूल्यों पर एकत्र होना। यह तभी संभव है, जब सांविधानिक मूल्यों को जाति, कुल या समुदाय जैसी विरासतगत निष्ठाओं से ऊपर रखा जाए। जब राजनीतिक विवेक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपनामों से आज्ञाकारी ढंग से निकले, तब नागरिकता जन्म का संयोग बनकर रह जाती है और नैतिक स्वायत्तता चुपचाप समर्पित हो जाती है।

इस तरह के संकीर्णतावाद का खतरा केवल सामाजिक विभाजन नहीं, बल्कि सांविधानिक क्षरण है। जैसा कि मार्था नुसबाम (अमेरिकी दार्शनिक) ने कहा है, जो निष्ठाएं केवल निकट और परिचित तक सीमित रह जाती हैं, वे अक्सर 'नैतिक रूप से निष्क्रिय', यहां तक कि हानिकारक हो जाती हैं, जब वे दूरस्थ दूसरों की समान गरिमा को पहचानने से रोकती हैं। संविधान की रूपांतरकारी शक्ति इसी आग्रह में निहित है कि हम अपने दायरे को संकुचित नहीं, बल्कि विस्तृत करें। वह अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे स्वयं को विरासतगत पहचान के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि समान नैतिक दर्जे के धारक के रूप में देखें। एक सशक्त गणराज्य के लिए सबसे बड़े संभव 'हम' का निर्माण आवश्यक है, जो रक्त या जन्म से नहीं, बल्कि न्याय, गरिमा और स्वतंत्रता के साझा संकल्प से बंधा हो।

एक और बड़ा खतरा है। जब पहचान राजनीतिक वैधता का मापदंड बन जाती है, तब सांविधानिक विवेक विस्थापित हो जाता है। अधिकारों की रक्षा इसलिए नहीं की जाती कि वे न्यायसंगत हैं, बल्कि इसलिए कि वे समूह-हित से मेल खाते हैं। अन्याय को तब तक सहन कर लिया जाता है, जब तक वह 'अपने' लोगों को लाभ पहुंचाता हो। इसी तरह सांविधानिक नैतिकता नाटकीय टूटन से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के सुविधाजनक समझौतों से क्षीण होती है। एक सांविधानिक लोकतंत्र में नैतिक क्षितिज का विस्तार सभी नागरिकों तक होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं तक नहीं, जो हमारी जाति, हमारा धर्म, क्षेत्र या उपनाम साझा करते हों।

यदि मुक्ति की राजनीति को नारे से आगे कुछ अर्थ रखना है, तो उसे इस फिसलन का प्रतिरोध करना होगा। वह इस मान्यता पर टिक नहीं सकती कि विरासतगत निष्ठा नैतिक तर्क से ऊपर है। वह जीवित ही नहीं रह सकती, यदि नागरिकों को उनकी सौंपी गई पहचान के विरुद्ध सोचने का अधिकार ही न दिया जाए। मुक्ति की शुरुआत सत्ता से, परंपरा से और आवश्यकता पड़ने पर अपने ही समुदाय से असहमति के साहस से होती है, जब वे सांविधानिक नैतिकता के विरुद्ध खड़े हों।

पहचान स्वभावतः बहुल है। जैसा कि अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक *आइडेंटिटी ऐंड वॉयलेंस* में कहते हैं, हम एक साथ कई पहचान में रहते हैं- पेशेवर, भाषायी, क्षेत्रीय, वैचारिक, नैतिक- और संदर्भ के अनुसार उनकी प्रासंगिकता बदलती रहती है। मैं विश्वविद्यालय में एक शिक्षक हूं, अकादमिक मंचों पर शोधकर्ता, राजनीतिक बहसों में एक नागरिक और हां, एक विशेष समुदाय में जन्मा व्यक्ति भी। इसलिए कोई एक पहचान यह तय नहीं कर सकती कि मैं क्या सोचूं? यह आग्रह कि विरासतगत समूह-परिचय ही हर संदर्भ में निर्णायक हो, वही है, जिसे अमर्त्य सेन 'एकल पहचान' की खतरनाक अवधारणा कहते हैं। यह ऐसा सरलीकरण है, जो मानवीय जटिलता को नकार देता है। यह मान लेता है कि जाति या धार्मिक पृष्ठभूमि, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता या आर्थिक नीति पर मेरी राय पहले से तय कर देती है। यह बौद्धिक दरिद्रता तो है ही, नैतिक रूप से दमनकारी भी है। नागरिकता की मांग है कि हम इस समतलीकरण से इनकार करें और अपने राजनीतिक निर्णयों को वंश नहीं, विवेक व संदर्भ के अधीन रखें।

भारत जैसे विविध और असमान गणराज्य में पहचान की निश्चितताओं में शरण लेना समझ में आता है, किंतु उस प्रलोभन के आगे झुकने की कीमत बहुत भारी है। यह नागरिकता को क्षीण करता है, राजनीतिक कल्पना को समतल करता है और सैद्धांतिक असहमति के द्वार बंद कर देता है। यदि हम सचमुच गणराज्य की रक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो हमें केवल बोलने के अधिकार की नहीं, बल्कि सोचने के अधिकार की भी रक्षा करनी होगी- स्वतंत्र रूप से, स्वायत्त रूप से और सांविधानिक रूप से। इससे कुछ भी कम, लोकतंत्र को वंश की पहचान में बदल देता है। इसी भविष्य को रोकने के लिए संविधान लिखा गया था।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

निरर्थक ज्ञान के दलदल से शिक्षा को बचाना होगा

यहां स्कैन करें
अनुराग बेहर | सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

एक जहरीली सड़ांध आज पूरी दुनिया पर तारी है। 'स्लॉप' शब्द इसी सड़ांध का हिस्सा है, जिसे कुछ प्रकाशनों ने 2025 में 'साल का शब्द' चुना है। उच्चारण से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, जो है- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा निर्मित निम्न गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री। इस शब्द का प्रयोग कभी 'कीचड़' के लिए होता था, लेकिन अब यह अपने नए रूप में हमें उस चीज को नाम देने में मदद कर रहा है, जिससे हम चौतरफा घिरे हुए हैं। आज पूरी दुनिया में निरर्थक बातों की बाढ़-सी आ गई है, जिससे हमारे आसपास का जहर और घातक हो गया है।

दार्शनिक हैरी फ्रैंकफर्ट की चर्चित किताब है- *ऑन बुलशिट*। यह 'टॉकिंग नॉनसेंस' यानी 'बकवास करने' पर केंद्रित है। कुछ घटिया बातें 'पूरी तरह बकवास' होती हैं, हालांकि सभी नहीं। इनका सत्य से कोई संबंध नहीं होता। चूंकि हम पूरी तरह से इसमें रमे हुए हैं, इसलिए इसके कुछ अहम पहलुओं को समझना उचित होगा। इसका सार यही है कि बकवास करने वालों को इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके दावे सही हैं या गलत, बल्कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कोई खास लक्ष्य साधा जा सके या वक्ता की छवि बनाई जा सके। फ्रैंकफर्ट के मुताबिक, सही या गलत के बजाय बोलने वाले की चिंता इससे बच निकलने की होती है।

जिन लोगों ने सोचा था कि एआई शिक्षा में सुधार का रामबाण है, उन्हें भी अब एहसास हो रहा है कि यह शिक्षा का आधार ही खत्म कर रही है।

आज दुनिया में 'टेक्नोहॉलिक्स' और 'टेक्नो-जॉम्बी' जैसे विचार एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। 'टेक्नोहॉलिक्स' इस सोच के प्रति कट्टर होते हैं कि तकनीक ही सभी समस्याओं का समाधान है और तरक्की का एकमात्र मार्ग। वहीं, 'टेक्नो-जॉम्बी' सोच बार-बार गलत साबित हो चुकी है, फिर भी हर बार जीवित हो उठती है। जैसे, शिक्षा के क्षेत्र में यह विचार कि 'तकनीक सीखा सकती है'। तकनीक के क्षेत्र का हर व्यक्ति 'टेक्नोहॉलिक' नहीं होता और न हर तकनीकी सोच को 'जॉम्बी' कहा जा सकता है। बावजूद इसके, ऐसे विचारकों की संख्या बहुत अधिक है। 'टेक्नोहॉलिक' की नई खेप में एआई के अगुवा शामिल हैं। उनकी अटूट मान्यता है कि एआई मानवता की सभी समस्याओं का समाधान है। कुछ तो यह भी मानते हैं कि यही इंसान को मौजूदा परिस्थितियों से उबार सकेगी। निश्चय ही, एआई के क्षेत्र में कई समझदार लोग भी हैं, लेकिन उनमें से कई सारे तो काफी दूर निकल चुके हैं।

द इकोनॉमिस्ट में एक लेख प्रकाशित हुआ है- 'एड-टेक फायदेमंद हैं, पर ज्यादातर बेकार'। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल की निंदा की गई है। लेख में लिखा गया है, 'स्कूलों में तकनीक का चलन ठोस प्रमाणों के बजाय आक्रामक मार्केटिंग पर आधारित है' और 'लंबे समय के रुझान से यह आशंका बढ़ जाती है कि कक्षा में उपकरणों के बढ़ते उपयोग से पठन-पाठन व अन्य विषयों में छात्रों के प्रदर्शन में भारी गिरावट आती है'। अच्छी बात है कि इस पत्रिका ने एड-टेक को लेकर बांधे गए तूमार को पहचान लिया है।

नौकरी की बात करें, तो एआई की वजह से इसकी बढ़ती संख्या के दावे की हवा विश्व आर्थिक मंच की बैठक में एक बड़ी ऊर्जा कंपनी के सीईओ ने 'रोजगार संकट' की घोषणा करते हुए निकाल दी। उद्योग जगत में कई लोग यह मानने लगे हैं कि एआई करोड़ों नौकरियां लील जाएगी। उन्हें यह भी नहीं पता कि एआई इतने रोजगार पैदा कर सकेगी या नहीं, जो खत्म होती नौकरियों के बराबर हो। इसी तरह, जिन लोगों ने सोचा था कि एआई शिक्षा में सुधार का रामबाण है, उन्हें भी अब एहसास हो रहा है कि यह वास्तव में शिक्षा की बुनियाद ही खत्म कर रही है। वे मानने लगे हैं कि एआई आधारित एप भी अन्य तकनीकों की तरह शिक्षा की असल दुनिया में कमोबेश बेकार हैं।

बहरहाल, आधुनिक युग में शिक्षा और इसके लिए बने ढांचे हमारे बच्चों को दुनिया से तालमेल बिठाने और उसे आकार देने की क्षमता विकसित करने के प्राथमिक संगठित सामाजिक तंत्र हैं। लिहाजा, हमें शिक्षा को इस दूषित प्रभाव से बचाना होगा, क्योंकि वैश्विक अराजकता से मुकाबला करने में एआई की अहम भूमिका है। बेशक, ऐसा करना कठिन हो, लेकिन यही सबसे सही राह है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सुविधा और खुशी

बाजार, बस अड्डे, कॉलेज, मंदिर... चाहे किसी भी जगह थोड़ी देर खड़े हो जाइए। सामने से गुजरने वाले लोगों पर गौर कीजिए। ध्यान से देखिए, कितने चेहरों पर खुशी नाच रही है। सौ लोग निकल गए, तो उनमें से केवल चार-पांच चेहरों पर हंसी दिखेगी। ऐसे चेहरे वाले लोग 20-25 साल से कम उम्र के होते हैं। 30 के पार पहुंचे लोग यूं दिखते हैं, मानो उनका सब कुछ लुट गया है। रुखी नजर से देखते हुए, उदासी और मायूसी से भरी गंभीर मुख-मुद्रा में चलते मिलते हैं, मानो गमी के घर से लौट रहे हों।

किसलिए बाहर जाकर देखना है? खुद अपने आपको आईने में देखिए न! पांच साल की उम्र में आप बगीचे में तितली के पीछे भाग रहे थे, उस समय आपके चेहरे पर जो उल्लास नाच रहा था, क्या वह अब दिखाई दे रहा है? पांच साल की उम्र में तितली को छूते ही उसके मोहक रंग आपके हाथ पर झिलमिलाते हुए चिपक गए। उस वक्त आपको यही महसूस हुआ था कि दुनिया में इससे बढ़कर कोई आनंद है ही नहीं। आपके अंदर से खुशी छलक-छलककर बिखर रही थी, है न?

पांच वर्ष की आयु में आपके पास क्या था? आज आपके पास क्या-क्या है? ऊंची पढ़ाई, कंप्यूटर, मकान, गाड़ी, पहली तारीख आते ही बैंक खाते में जमा हो रही तनख्वाह, सोते समय भी साथ रहता सेलफोन... आपने कितना कुछ इकट्ठा कर रखा है! चंद सदियों पहले, सारे जहान को जीतने का दम भरने वाले शहंशाहों को भी इतनी सारी सुविधाएं मयस्सर नहीं थीं। फिर भी क्या आपकी खुशी उसी अनुपात में बढ़ी है?

इसलिए इच्छित वस्तु न मिलने पर यदि आप मुंह लटकाएं फिर रहे हैं, तो यह मूर्खता ही है। वांछित वस्तु मिलने के बाद भी खुशी मनाने का हुनर न जानकर तड़प रहे हैं। इस तरह का एक बंगला चाहिए, उस तरह की एक कार... उनकी तरह सुखमय जीवन। इस बात की परवाह नहीं की कि वह आप पर जंचेगा या नहीं, आपके लायक है भी कि नहीं; बस उसे अपनी प्रकृति बनाना चाहते हैं।

किसी ने सलाह दी कि इन दिनों सॉफ्टवेयर बिजनेस जोरों पर है, इसे सुनकर आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। एक सज्जन आपको दयनीय दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, वह देखिए बदरंग कमीज पहने जो आदमी घूम रहा, उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अमेरिका में बड़ी धाक थी। मंदी आई और उसे वापस भारत भेज दिया गया। अब वह भुखमरों का संघ बनाने के बारे में सोच रहा है, इसलिए मेरी मानें, तो शेयर बिजनेस शुरू कर दीजिए। शेयर बिजनेस तो सांप-बिच्छू हैं, क्या वे आपको छोड़ देंगे?

चंद सौ साल पहले, सारे जहान को जीतने का दम भरने वाले शहंशाहों को भी इतनी सारी सुविधाएं मयस्सर नहीं थीं, जितनी आज आपको हैं। क्या आपकी खुशी उसी अनुपात में बढ़ी है?

साफ है, अपनी प्रकृति को पहचाने बिना उल्टी दिशा में पतवार चलाते जाएंगे, तो जिंदगी तबाह ही होगी।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति

बस्तर की सुंदरता देखकर लगता है कि मां दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। मौसम बदलने के साथ प्रकृति करवट लेती है और यहां के लोग उत्सव मनाते हैं। जीवन जीने का तरीका देशवासी बस्तर के निवासियों से सीख सकते हैं।

अनुलोम-विलोम

साइबर धोखाधड़ी

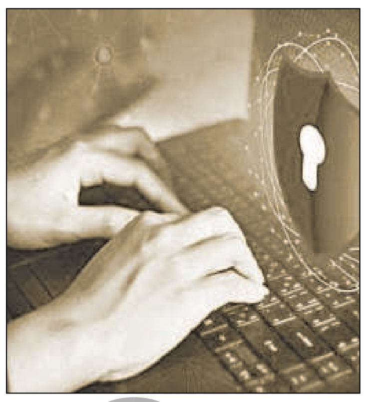

साइबर सुरक्षा तंत्र अब भी मजबूत नहीं

डिजिटल युग ने जहां जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर धोखाधड़ी के मामलों में भी चिंताजनक वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी ठगी की नई पद्धति ने आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। इस तरह की धोखाधड़ी में अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से लोगों को डराते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे किसी गंभीर अपराध में फंस चुके हैं। भय व मानसिक दबाव में आकर कई लोग जीवन भर की कमाई इन साइबर ठगों के हवाले कर देते हैं। अखबारों की सुर्खियां इसकी तस्दीक भी करती हैं।

ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई, बैंकों और रिजर्व बैंक के रवैये पर नाराजगी जताना यह संकेत देता है कि साइबर सुरक्षा तंत्र अभी अपेक्षित स्तर तक मजबूत नहीं हो पाया है। यदि बैंक समय पर संदिग्ध लेन-देन को रोकने और खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई करें, तो ठगी के अनेक मामलों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग पर आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम विकसित हो चुके हैं, जो असामान्य लेन-देन की तुरंत पहचान कर सकते हैं। विकसित देशों में 'रियल-टाइम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग' और 'बिहेवियरल एनालिटिक्स' जैसे उपायों से साइबर अपराधों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है, लेकिन भारत में इसे पूरी तरह से अपनाया नहीं जा सका है। इन उपायों को व्यापकता में लागू करना वक्त की मांग है।

सरकार जो उपाय उचित समझेगी, वह करेगी ही, पर लोगों को भी समझना होगा कि कोई सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने का आदेश नहीं देती। अनजान लिंक पर क्लिक करने, स्क्रीन शेयर करने या ओटीपी बताने से लोगों को बचना चाहिए। मोबाइल और बैंकिंग एप में 'टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' का उपयोग तथा समय-समय पर पासवर्ड बदलना भी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए केवल अदालत की सख्ती पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए बैंकों, नियामक संस्थाओं, सरकार और आम नागरिकों, सभी को मिलकर एक सशक्त डिजिटल सुरक्षा संस्कृति विकसित करनी होगी। जब तक तकनीकी सतर्कता, संस्थागत जवाबदेही और नागरिक जागरूकता का समन्वय नहीं होगा, तब तक डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता खतरे में बनी रहेगी। चूंकि आने वाला वक्त तकनीक का है, इसलिए जरूरी है कि इन चुनौतियों को जल्द दूर किया जाए।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

सुरक्षा के जरूरी कदम उठाए जा रहे

आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा किसी देश की संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता का अभिन्न अंग है। भारत, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यहां के 86 प्रतिशत से अधिक परिवार अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में, साइबर खतरों का सामना मजबूती से करने के लिए भारत के साइबर सुरक्षा तंत्र को निरंतर मजबूत बनाया जा रहा है। सीईआरटी-इन और आई4सी जैसी प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से सरकार ने एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली विकसित की है, जो साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफल सिद्ध हो रही है।

भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) इस तंत्र का मुख्य आधार स्तंभ है। यह सातों दिन व चौबीसों घंटे निगरानी के साथ फिशिंग, रैनसमवेयर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमलों का तत्काल प्रतिकार करती है। इसने साइबर स्वच्छता केंद्र स्थापित कर मैलवेयर हटाने के लिए मुफ्त टूल उपलब्ध कराए हैं, जिससे लाखों उपकरण सुरक्षित हुए हैं। इसी तरह, 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' ने 'प्रतिबिंब' सॉफ्टवेयर के जरिये अपराधियों के सिम कार्ड लोकेशन ट्रैक कर 6,000 से अधिक गिरफ्तारियां कराईं और 17,000 अवैध संबंध उजागर किए। इसने 42 लाख चोरी हुए मोबाइल फोन ब्लॉक भी किए, जो डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में क्रांतिकारी साबित हुआ। सुखद है कि वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 21,633 करोड़ रुपये और सीईआरटी-इन को 269 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत रीयल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाई जा रही है, जिससे साइबर अपराधों की रोकथाम दर में वृद्धि हुई है। गृह मंत्रालय की समन्वित कार्रवाई से 36,000 से अधिक जांचों में मदद मिली है।

हालांकि, सरकार के उक्त प्रयास तब अधिक सफल होंगे, जब हम सतर्क रहेंगे। अपना ओटीपी किसी को शेयर न करें। फिर भी दुर्घटना हो जाए, तो साइबर क्राइम में खोए पैसे वापस पाने के लिए तुरंत कार्रवाई जरूरी है। खासकर शुरुआत के एक-दो घंटे (गोल्डन ऑवर) बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान सफलता की दर बहुत अधिक है। इसलिए, तुरंत 1930 हेल्पलाइन या बैंक कस्टमर केयर पर कॉल करें और ट्रांजेक्शन फ्रीज करवाएं। भारत की साइबर सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सुधार जारी है। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र और साइबर सुरक्षित भारत जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा कर रहे हैं।

विनय सिंह बैस, टिप्पणीकार

अपने घर बैठे चलाएं होम-स्टे व्यवसाय

आज का पर्यटक होटलों के बजाय स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का वास्तविक अनुभव लेना चाहता है। इसीलिए अब होम स्टे जैसी आतिथ्य सेवाएं एक संगठित स्टार्टअप क्षेत्र के रूप में उभरी हैं। वहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जरूरत के अनुसार होटल रूम की कमी है। शायद यही कारण है कि बीते सालों में इस बिजनेस में आय बढ़ी है। अब सरकारी स्तर पर इसके लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। कैसे? बता रही हैं श्वेता राकेश

भारत में पर्यटन उद्योग जहां एक ओर लगातार विस्तार कर रहा है, वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 2 लाख से अधिक होटल कमरों की कमी है। नए होटल विकसित करना जहां भारी निवेश, जमीन और लंबी मंजूरी प्रक्रिया से जुड़ा है, वहीं होम-स्टे और बी-एंड-बी (बेड एंड ब्रेकफास्ट) जैसे मॉडल कम लागत और कम समय में इस जरूरत को पूरा करने का विकल्प दे रहे हैं, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नए अवसर भी बन रहे हैं।

हॉस्पिटैलिटी अब बड़े होटलों तक सीमित नहीं रही। हिमाचल प्रदेश की होम-स्टे नीति 2025 के तहत कुल्लू जिले में 1,390 से अधिक होम-स्टे पंजीकृत हो चुके हैं। इनके संचालन के लिए प्रशिक्षित हॉस्पिटैलिटी पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। छोटे शहर भी पीएम गति शक्ति और उड़ान जैसी योजनाओं के चलते नए अवसर दे रहे हैं।

होम-स्टे की बढ़ती मांग

कॉग्निटिव मार्केट रिसर्च के अनुसार भारत में होम-स्टे बाजार में साल 2031 तक लगभग 11 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म मेकमायट्रिप की कुल रूम-नाइट बिक्री में होम-स्टे की हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत हो चुकी है और एक लाख से अधिक कमरे सूचीबद्ध हैं। बुकिंग डॉट कॉम जैसे वैश्विक मंचों पर भी वैकल्पिक आवास की मांग बढ़ रही है, जिससे होम-स्टे संचालन व प्रबंधन से जुड़े करिअर अवसर बढ़ने के संकेत मिलते हैं।

सरकारी नीतियों से मिल रहा समर्थन

पर्यटन को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें भी होम-स्टे के विकल्प को समर्थन दे रही हैं। केंद्र सरकार की इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के बाद देश के 18 राज्यों ने होम-स्टे के लिए अलग दिशानिर्देश और योजनाएं तैयार की हैं, जिनमें वित्तीय सहायता, टैक्स राहत, मार्केटिंग सपोर्ट और क्षमता निर्माण जैसे प्रावधान शामिल हैं। इनकी जानकारी संबंधित राज्य के टूरिज्म पोर्टल से मिल सकती है। इससे होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े युवाओं के लिए नए मौके बने हैं।

प्रशिक्षण और डिग्री : हालांकि, इस काम में विशेष डिग्री या डिप्लोमा की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म में डिप्लोमा/डिग्री से संचालन, गेस्ट हैंडलिंग और सर्विस मैनेजमेंट की समझ मिलती है। शॉर्ट-टर्म हॉस्पिटैलिटी और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन बुकिंग, प्रचार और कमाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये कोर्स होम-स्टे को पेशेवर रूप देने और कारोबार को टिकाऊ बनाने में मदद करते हैं।

होम-स्टे की अवधारणा : इसका मतलब है अपने घर के कुछ कमरे पर्यटकों के लिए अल्पकालिक खोलना। पर्यटक कम खर्च में स्थानीय अनुभव और घर जैसा माहौल पाने के लिए आते हैं। भारत में इसे शुरू करने के लिए राज्य पर्यटन विभाग में पंजीकरण और मालिक का घर में रहना अनिवार्य है। अधिकतम 6 कमरे (12 बेड) तक ही किराए पर दिए जा सकते हैं। पुलिस सत्यापन, स्वच्छ पेयजल आदि नियम पालन करना जरूरी है।

बनारस में गेस्ट हाउस फैमिली नाम से होमस्टे चला रहीं छाया सिंह बताती हैं, 'इस बिजनेस में तजुर्बा और दिल से काम करना सबसे जरूरी है। कुछ समय अन्य होम-स्टे देखकर सीखें, फिर शुरू करें। फीडबैक लेकर सुधार करें और अपने मेहमानों के साथ जुड़े रहें। साफ-सफाई और अच्छा व्यवहार होना जरूरी है। यदि ये सही हैं, तो कमाई बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। आप अपने होम-स्टे की ऑनलाइन भी लिस्टिंग कर सकते हैं।'

मार्केट रिसर्च और निवेश : होम-स्टे शुरू करने से पहले स्थानीय मांग, प्रतियोगी और मेहमानों की प्रोफाइल समझना जरूरी है-जैसे परिवार, युवा या विदेशी पर्यटक। दो से 3 कमरे तैयार करने में लगभग 4-10 लाख रुपये और मासिक खर्च 25,000-35,000 रुपये हो सकता है। यह घर और सुविधाओं पर निर्भर करता है।

संचालन और कमाई : बुकिंग बढ़ाने के लिए ओटीए प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया व स्थानीय प्रचार का सहारा लिया जा सकता है। सही सेवा योजना से हर माह 80 हजार रुपयों से ज्यादा की आय संभव है और कारोबार बढ़ने की संभावना रहती है।

सरकारी प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और कुछ वेबसाइट

- बिहार सरकार होम-स्टे मालिकों को आर्थिक सहायता दे रही है। शहरी पर्यटन स्थलों से 5 किमी और ग्रामीण/इको-टूरिज्म क्षेत्रों से 10 किमी के भीतर रहने वाले मकान-मालिक प्रति कमरे 2.5 लाख रुपये तक बैंक लोन ले सकते हैं, जिसका ब्याज पर्यटन विभाग वहन करेगा। होम-स्टे से जुड़ी जानकारी और पंजीकरण के लिए संबंधित वेबसाइट tourism.bihar.gov.in पर 'मुख्यमंत्री होम-स्टे/बेड एंड ब्रेकफास्ट (BnB) नीति' देखी जा सकती है।
- इसी तरह उत्तराखंड के लिए homestay.uttarakhandtourism.gov.in पर जा सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश की होम-स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति में होम-स्टे, बीएंडबी और ग्रामीण होम-स्टे जैसे मॉडल शामिल हैं। पंजीकरण ऑनलाइन होता है, फिर जिला स्तर पर निरीक्षण और अनुमोदन होता है। पंजीकरण की वैधता आमतौर पर तीन वर्ष रहती है। सुविधाओं व शुल्क के आधार पर श्रेणियां तय की गई हैं। पंजीकृत होम-स्टे को प्रशिक्षण, प्रचार और तकनीकी सहयोग का लाभ भी मिलता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के पोर्टल पर जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं - up-tourismportal.in

विशेषज्ञ की राय

होम-स्टे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक हिस्सा है, लेकिन होटल से अलग है। कम खर्च में अपना छोटा-मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या किसी कारणवश घर से ही लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, तो यह अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। पर्यटन स्थलों में इसकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि ये घर जैसा माहौल देते हैं और होटल की तुलना में कम खर्चीले हैं। पेशेंट रिहैबिलिटेशन के लिए भी होम-स्टे पसंद किए जा रहे हैं। कारण है इसका प्रकृति के करीब होना, होटल की तुलना में सस्ता होना, शांत और स्वच्छ वातावरण होना। इसे शुरू करने के लिए विशेष डिग्री की जरूरत नहीं, लेकिन सरकारी नियमों की जानकारी होना जरूरी है। हालांकि, अब होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज में होमस्टे प्रबंधन को शामिल किया जा रहा है। इससे जुड़े कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस कर सकते हैं। **डॉ. संजीव आचार्य**, वरिष्ठ करिअर काउंसलर

जॉब/करिअर

- संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सर्विसेज (प्रीलिमिनरी) इग्जामिनेशन 2026 के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
कुल पद : 933
अंतिम तिथि : 24 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। यूपीएससी की वेबसाइट **upsc.gov.in** पर जाएं।
- पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस की भर्तियां की जाएंगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
कुल पद : 5138
अंतिम तिथि : 24 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : बैंक की वेबसाइट है- **pnb.bank.in**
- दिल्ली हाईकोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल/रिस्टोरर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
कुल पद : 152
अंतिम तिथि : 23 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करें। वेबसाइट **delhihighcourt.nic.in** पर जाएं।
- नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में असिस्टेंट फोरमेन के पद रिक्त हैं। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कुल पद : 270
अंतिम तिथि : 05 मार्च 2026
आवेदन प्रक्रिया : आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर लॉगइन करें - **nclcil.in**
- नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) में प्रोफेसर समेत विभिन्न पदों पर आवेदन का अवसर है। नियुक्ति जूलॉजी, हिंदी समेत अन्य विभागों में की जाएगी।
कुल पद : 117
अंतिम तिथि : 20 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट **ncert.nic.in** पर जाएं।
- रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में लेवल-1 (7वां वेतन आयोग) के तहत असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर समेत विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
कुल पद : 22195
अंतिम तिथि : 02 मार्च 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट है : **rrbchennai.gov.in**
- भारतीय स्टेट बैंक में सर्कल बेस्ड अधिकारी के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं।
कुल पद : 2273
अंतिम तिथि : 18 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : एसबीआई की वेबसाइट **sbi.bank.in** पर लॉगइन करें।
- यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, झारखंड में अप्रेंटिस की भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां फिटर, मशीनिस्ट समेत विभिन्न ट्रेड में होंगी।
कुल पद : 364
अंतिम तिथि : 28 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। वेबसाइट है : **ucil.gov.in**

(नोट : आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें।)

भेजें अपना सवाल

करिअर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें
nayiraheincareer@gmail.com

एग्रीकल्चर डिग्री से देश-विदेश में कारोबार

एक्सपर्ट टिप्स

आशीष आदर्श
करिअर काउंसलर

- **मेरी खास रुचि फार्मिंग और कृषि में है। क्या मैं इसकी पढ़ाई करने के बाद विदेश से आयात-निर्यात का बिजनेस कर सकता हूं?**
राजेन्द्र अवस्थी

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की एक बड़ी आय कृषि से होती है। जहां एक ओर इस सेक्टर में सरकारी नौकरियां भी निकलती हैं, वहीं आप खुद का कृषि बिजनेस स्थापित कर करोड़ों का व्यापार देश-विदेश में कर सकते हैं। करिअर की दृष्टि से 10+2 पीसीएम या पीसीबी के छात्रों के लिए 4 वर्षीय बीएससी इन एग्रीकल्चर कोर्स लाभदायक है, जिससे आप यह सीखते हैं कि खेती को एक वैज्ञानिक और पेशेवर करिअर के रूप में कैसे किया जाए।

इस कोर्स में कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीक, प्रोडक्शन, सॉइल मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर इत्यादि के साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जैसे विषयों की पढ़ाई होती है, जो आपको तकनीकी रूप से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में माहिर बनाते हैं। थ्योरी, प्रैक्टिकल और फील्ड ट्रेनिंग वाला यह कोर्स देश के कई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में उपलब्ध है।

देश की प्रतिष्ठित एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर से संबंधित 4 वर्षीय अवधि वाले कुल 9 बैचलर डिग्री कोर्सेज और 4 बीटेक कोर्सेज कराए जाते हैं : बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरीज, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएससी फूड न्यूट्रीशन एंड डाइटेटिक्स, बीएससी सेरीकल्चर, बीएससी नेचुरल फार्मिंग, बीएससी एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एवं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। वर्तमान में देश में 4 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और 10 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, जहां से बीएससी एग्रीकल्चर सहित कई अन्य कोर्स किए जा सकते हैं।

दाखिले की बात करें, तो भारत सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत स्थापित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी आईसीएआर द्वारा एक प्रवेश जांच परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे सीयूईटी-आईसीएआर कहते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद सरकारी क्षेत्र में कई अवसर मिलते हैं। आपकी नियुक्ति एग्रीकल्चरल ऑफिसर, ब्लॉक कृषि अधिकारी, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर जैसे पदों पर हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में तमाम एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग एवं फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों में एग्री सेल्स ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर जैसे पदों पर नौकरी कर सकते हैं।

तमाम बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियां भी बीएससी एग्रीकल्चर उत्तीर्ण स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पदों पर नियुक्त करती हैं। साथ ही, ऑर्गेनिक खेती, नर्सरी बिजनेस, सीड प्रोडक्शन, डेयरी, पोल्ट्री, मशरूम फार्मिंग इत्यादि के रूप में अपना बिजनेस शुरू कर देश-विदेश में व्यापार कर सकते हैं।

नौकरी से पहले थोड़ी तैयारी जरूरी

कॉलेज से निकलते ही नौकरी करना कई युवाओं का सपना होता है। परेशानी तब आती है, जब उन्हें नौकरी तो मिल जाती है, पर काम की समझ न होने के कारण दबाव में आकर मौके निकल जाते हैं

करिअर टिप्स

नौकरी की शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती ऑफिस की कार्यशैली को समझना होता है। कॉलेज के पुराने ढर्रे से निकलकर यहां हर फैसले और काम की जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ती है और सबसे अहम होते हैं नतीजे। अच्छी बात यह है कि सही दिशा में की गई थोड़ी-सी तैयारी इस बदलाव को आसान बनाती है और यहीं से मजबूत करिअर की शुरुआत होती है-

- **काम को नतीजे से जोड़ें :** कॉलेज में काम का मतलब होता है असाइनमेंट पूरा करना। नौकरी में काम का मतलब होता है तय नतीजा लाना। कई फ्रेशर्स कहे गए निर्देश तो मान लेते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि उनसे क्या हासिल होना चाहिए। इसलिए नौकरी से पहले यह समझ जरूरी है कि हर काम पूरा हुआ से ज्यादा काम के नतीजे से जुड़ा होता है।
- **बिना कहे जिम्मेदारी लें :** कई फ्रेशर्स झिझक के कारण पहल करने के बजाय हर कदम पर निर्देश का इंतजार करते हैं, जबकि ऑफिस में छोटा सा सुझाव देना भी एक अहम कौशल माना जाता है। यही आदत आपको जिम्मेदार और भरोसेमंद बनाती है।

- **पेशेवर अंदाज सीखें:** केवल अंग्रेजी जानना काफी नहीं है। ईमेल कैसे लिखनी है, कब और कैसे जवाब देना है, मीटिंग में अपनी बात कैसे रखनी है, जैसी छोटी बातों की समझ से ही ऑफिस में पेशेवर रवैया बनता है।
- **समय एवं प्राथमिकता समझें :** कॉलेज प्रोजेक्ट में देर हो जाना चल सकता है, लेकिन नौकरी में समय पर काम पूरा करना भरोसे की बुनियाद होता है। इतना ही नहीं, कौन-सा काम पहले करना है और किसे बाद में यह समझ विकसित न होना भी करिअर को नुकसान पहुंचाता है।
- **सीखने और समझने का नजरिया:** नौकरी की शुरुआत में सब कुछ आसान और सीधा नहीं होता। काम उलझा हुआ लग सकता है और चीजें हमेशा योजना के मुताबिक भी नहीं चलतीं। इसलिए शुरुआती दौर को सीखने और समझने के नजरिए से लें।
- **प्रतिक्रिया से भी सीख लें :** शुरुआती दिनों में अकसर सुधार के लिए फीडबैक या प्रतिक्रिया मिलती है। कई फ्रेशर्स इसे अपनी क्षमता पर सवाल मान लेते हैं, लेकिन असल में फीडबैक सीखने का अवसर होता है। इसलिए मानसिक तौर पर तैयार रहें, शुरुआती दिनों में हर बार तारीफ नहीं मिलती और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।
- **काम को दिखाना भी सीखें :** कई युवा अपना काम ठीक से कर लेते हैं, लेकिन उसे टीम या बॉस तक सही तरीके से पहुंचाने में घबराते हैं। अपडेट देना, प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देना और अपने योगदान को साफ तौर पर बताना भी काम पूरा करने जितना ही जरूरी है। यह आदत आपकी काबिलियत दिखाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और टीम का भरोसा जीतने में मदद करती है।

कार्तिक मेहता

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। कारोबार के लिए विदेश जाने के अवसर भी मिल सकते हैं।

वृष : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार से लाभ में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। परिवार का साथ मिलेगा।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। कारोबार में बदलाव हो सकता है।

कर्क : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। धैर्यशीलता बनाए रखें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

सिंह : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है।

कन्या : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। कारोबार में बदलाव हो सकता है। परिवार व मित्रों का साथ मिल सकता है।

तुला : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टमय रहेगा।

वृश्चिक : आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कारोबार में लाभ में वृद्धि होगी, परंतु कारोबार विस्तार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। परिश्रम अधिक रहेगा।

धनु : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध एवं विवाद से बचें। धैर्य रखें। बातचीत में भी संतुलित रहें। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र के सहयोग से लाभ में वृद्धि हो सकती है।

मकर : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता का साथ मिलेगा। कारोबार से आय में वृद्धि होगी।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में बदलाव हो सकता है। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा।

मीन : मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं। परिवार की सेहत का ध्यान रखें।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

12 फरवरी, गुरुवार, **शक संवत् :** 23, माघ (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग :** 01, फाल्गुन मास प्रविष्टे 2082 **इस्लाम :** 23, शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत् :** फाल्गुन कृष्ण दशमी तिथि दोपहर 12.23 मिनट तक, पश्चात एकादशी तिथि, हर्ष योग रात्रि 03.06 मिनट तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में दोपहर 01.43 मिनट तक उपरांत धनु राशि।

सूर्य उत्तरायण। शिशिर ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 12.23 मिनट तक। फाल्गुन संक्रांति। स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि यदि समृद्धि को आकर्षित करना हो, तो क्या उपाय करने चाहिए?
-मनीषा सहाय, मेरठ

- अपनी रसोई में एक लोटा साफ पानी भरकर रखना अत्यंत शुभ होता है। यह हमेशा धन समृद्धि को आकर्षित करने वाला होता है।
- सुबह आठ बजे से पहले स्नान करने का नियम बना लें। यह बहुत शुभ माना जाता है।
- हमेशा यह ध्यान रखें कि सुबह-सुबह न तो किसी को अपशब्द बोलें न ही किसी से झगड़ा करें। ऐसी चीजें आपके घर के वातावरण की ऊर्जा को बहुत प्रभावित करती हैं।
- रसोई एवं कमरों में रात को कोई भी गंदगी बिल्कुल न रखें।

वर्ग पहेली : 8238

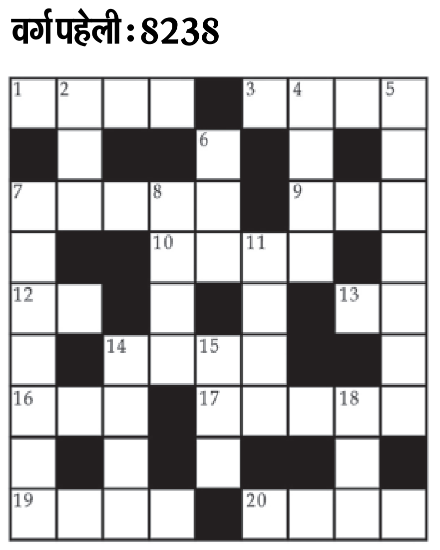

बाएं से दाएं
1. तपस्या करने वाली स्त्री; पतिव्रता स्त्री; सती स्त्री; कुटकी; जटामासी; बड़ी गौरखमुंडी (4)
3. अनुचित कार्य को रोकने के लिए किया जाने वाला प्रयास; नियंत्रण; निवारण; अवरोध; रुकावट (4)
7. थकाना; शिथिल करना; पराजित करना; हरा देना; साहस तोड़ना (2,3)
9. मठाधीश; मंडली का प्रमुख साधु; मुख्य पुजारी (3)
10. पूरी तरह से; प्रत्यक्ष; बिल्कुल (4)
12. सूत में पिरोये मनके; लड़ी; हार (2)
13. जनक; जन्मदाता; तात (2)
14. लेटने की एक स्थिति (4)
16. वचन; वादा; इकरार (3)
17. निषिद्ध करना; रुकवाना; वर्जित करना (2,3)
19. काटना; छांटना; छोटा करना (4)
20. पृथ्वी; धरती; सतह; क्षेत्र (4)

ऊपर से नीचे
2. हारा हुआ; पराजित; विजित; प्रभावहीन (3)
4. कुचला हुआ; बारीक (4)
5. पूजा की प्रतिज्ञा पूरी करना; मन्नत बढ़ाना (3,4)
6. कूल; तीर; तट (3)
7. परिमाण दर्शाने वाला; परिमाणद्योतक; मात्रा सूचक (7)
8. जायकेदार; शोरबेदार; रसवाला (4)
11. एकत्रित करना; सहेजना (4)
14. अनुचित व्यवहार; बदचलनी (4)
15. आहुति; पीड़ा; उलटी; मतली (3)
18. चांदी; धवल; शुभ्र (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8237

1 ठो	2 क	र	खा	3 ते	फि	4 र	ना	■
■	ना	■	■	ली	■	ख	■	5 बा
6 अं	त	का	7 ल	■	8 ह	वा	दा	र
धे	■	■	लि	■	■	ना	■	बा
9 र	क्त	■	10 त	ड़ि	11 त	■	12 गै	र
म	■	13 ली	■	■	र	■	■	हो
14 च	म	क	ना	■	15 स	ह	16 म	ना
ना	■	पा	■	17 बा	■	■	च	■
■	18 उ	ल	टी	सी	धी	सु	ना	ना

सुडोकू : 8220

*कठिन

5			4	9				
	3		1					4
		6					1	
		5		2				
	1	4				5	7	
				4		9		
	8					7		
7					9		5	
				6	7			2

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8219

9	1	8	6	5	4	3	7	2
6	3	2	9	1	7	8	4	5
5	4	7	3	8	2	1	9	6
4	6	3	8	7	9	2	5	1
1	7	5	2	4	6	9	8	3
8	2	9	1	3	5	7	6	4
3	8	4	5	9	1	6	2	7
2	5	1	7	6	8	4	3	9
7	9	6	4	2	3	5	1	8